जबलपुर, नई दिल्ली एवं पटना से एक साथ प्रकाशित

www.pratahkiranlive.com

राष्ट्रीय दैनिक

प्रातःकिरण

हर खबर की खबर

10

■ वर्ष -01 ■ अंक - 201 ■ जबलपुर, गुरूवार, 19 फरवरी 2026 ■ विक्रम संवत् 2082 ■ पेज - 12 ■ मूल्य रू 04.00

सुविचार

मुश्किल वक्त ही योद्धा बनाता है।

संक्षिप्त समाचार

ईशान किसन की आईसीसी टी-20 रैंकिंग के टॉप-10 में धांसू एंट्री

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी टी20 रैंकिंग के शीर्ष 10 में आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। इस रैंकिंग अपडेट में तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव भी शीर्ष 10 में शामिल हैं, जो भारतीय बल्लेबाजों के दबदबे को दर्शाता है। भारतीय सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने मौजूदा टी20 विश्व कप में 40 गेंदों पर 77 रनों की मैच-विनिंग पारी खेलकर आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बना ली है। 732 रेटिंग अंकों के साथ वह रैंकिंग में आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड को पीछे छोड़ते हुए, वह अब टी20 प्रारूप में आईसीसी रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं।

बिहार : तीन लाख के कुख्यात इनामी अपराधी ने किया समर्पण

मुंगेर। स्पेशल एरिया कमेटी के कमांडर व सशस्त्र नक्सली दस्ते के सदस्य तथा सरकार द्वारा तीन लाख रुपये के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा ने बुधवार को मुंगेर पुलिस केंद्र में पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) राकेश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उसने एक एके-47, एक एके-56, दो इंसास राइफल और 505 राउंड कारतूस पुलिस को सौंपे। कार्यक्रम में डीआईजी राकेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पीणीकर और एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को माला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया।

60 से अधिक मामले दर्ज

जानकारी के अनुसार, सुरेश कोड़ा के खिलाफ मुंगेर, लखीसराय और जमुई समेत विभिन्न थानों में हत्या, आगजनी, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित करीब 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2008 में उसके खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था, जबकि अंतिम मामला जुलाई 2025 में दर्ज किया गया। मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने कहा कि सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद न केवल मुंगेर जिला बल्कि पूरा बिहार आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में बिहार में कोई भी हथियारबंद नक्सली सक्रिय नहीं है। उन्होंने बताया कि सुरेश कोड़ा मुंगेर जिले के लड़ैयांटांड थाना क्षेत्र के पैसरा गांव का निवासी है और लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था।

कार्टून कोना

लाड़ली बहनों और किसानों पर धनवर्षा; बिना नए टैक्स के 'रोजगार' और 'सिंहस्थ' पर जोर, मध्यप्रदेश बजट में किसके लिए क्या?

मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

● प्रात :किरण संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विधानसभा में 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का तीसरा बजट पेश हुआ है। इसमें किसान, महिलाओं को खास सौगातों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं।

रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर मालिकाना हक देने के लिए नई योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत मुद्रांक और पंजीयन (रजिस्ट्री) का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार ने इसके लिए बजट में ?3,800 करोड़ का प्रावधान रखा है।

भोपाल को 18 नई सड़कों की सौगात, 143 करोड़ मंजूर

राजधानी भोपाल को बजट में बड़ी सौगात मिली है। कुल 18 सड़कों - 8 शहरी और 10 ग्रामीण मार्ग - के निर्माण के लिए 143.4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बरखेड़ीकला-बरखेड़ीखुर्द, एम्स से डीआरएम रोड और साकेत नगर सहित कई

अहम मार्गों का निर्माण होगा। इसके अलावा 35 किमी ग्रामीण सड़क पर 70 करोड़ और 44 किमी मार्ग के संधारण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

थीम पर 4.38 लाख करोड़ का रोलिंग बजट

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट 2026-27 को 'समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश' के विजन से जोड़ा। 4,38,317 करोड़ का यह बजट 'GYANII'- गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री - पर आधारित बताया गया। सीएम के मुताबिक, यह प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है और लगातार तीसरी बार कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया।

बजट में नए टैक्स से राहत

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए कहा- इस वित्तीय वर्ष के बजट में किसी प्रकार के नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांवों हेतु 793 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। बजट भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने इसे विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी बताया।

विधानसभा में जोरदार हंगामा

बजट भाषण के दौरान सदन में भारी गहमागहमी का माहौल भी बना हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने राज्य पर बढ़ते 4.94 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के विरोध में नारेबाजी की। विपक्षी नेता अपने साथ खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर आए, जिसपर लिखा है- 'कर्ज बजट से ज्यादा है।' विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत रहके हुए सीट पर शांत होकर बैठने को भी कहा, पर विपक्ष की नारेबाजी जारी रही।

किसके लिए फायदेमंद है बजट? सीएम मोहन यादव ने बताया विज़न

- मध्य प्रदेश विधानसभा में 4,38,317 करोड़ रुपये का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे विकास की नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि अगले दो वर्षों की विकास रूपरेखा तय करने वाला 'रोलिंग बजट' है।
- सरकार ने कृषि के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जबकि सड़कों के विस्तार पर 21,630 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 'द्वारका योजना' के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- सीएम के मुताबिक, राज्य 30 प्रतिशत ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण पर भी खास फोकस रखा गया है।

एआई समिट में मोदी की मेगा डिप्लोमेसी

एस्टोनिया, फिनलैंड, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वेन के साथ नई शुरुआत

● नई दिल्ली, एजेंसी

'एआई' इम्पैक्ट समिट में भागीदारी के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समानांतर रूप से एक सक्रिय कूटनीतिक मिशन भी साधते दिख रहे हैं। समिट से इतर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें इस बात का संकेत हैं कि भारत वैश्विक मंचों का उपयोग केवल बहुपक्षीय चर्चाओं तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उन्हें रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के अवसर में भी बदल रहा है। डिजिटल तकनीक, व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार जैसे मुद्दों पर हुई ये वार्ताएं बताती हैं कि मोदी सरकार भविष्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए साझेदारियां गढ़ रही है और भारत की वैश्विक भूमिका को लगातार विस्तार दे रही है।

जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ताओं की बात है तो आपको बता दें कि उनकी और एस्टोनिया के राष्ट्रपति की मुलाकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता ('एआई') इम्पैक्ट समिट के इतर ऐसे समय हुई जब डिजिटल सहयोग वैश्विक कूटनीति का अहम आधार बनता जा रहा है। दोनों नेताओं ने भारत-एस्टोनिया संबंधों की विभिन्न धाराओं की समीक्षा की और खास तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई-गवर्नेंस और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (स्नञ्ज) की वार्ताओं के ऐतिहासिक समापन और उसके शीघ्र क्रियान्वयन पर भी सहमति जताई गई। सामरिक दृष्टि से एस्टोनिया, जो डिजिटल गवर्नेंस में विश्व अग्रणी माना जाता है, भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उपयोगी साझेदार है। बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया के साथ मजबूत रिश्ते भारत की यूरोप नीति को भी मजबूती देते हैं।

'एआई' की दुनिया में भारत का डंका, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, 24 घंटे में 2.5 लाख प्रतिज्ञाएं

भारत ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 24 घंटे में 2.5 लाख से अधिक एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञा हासिल कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित यह उपलब्धि इंडिया एआई मिशन के तहत नैतिक और मानव-केंद्रित एआई उपयोग को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान का परिणाम है। श्री वैष्णव ने आज घोषणा की कि भारत ने 24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। 16-17 फरवरी के 24 घंटों के दौरान 250,946 वैध प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुईं। यह घोषणा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन, MeitY के अतिरिक्त सचिव, इंडियाएआई मिशन के सीईओ और एनआईसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह, इंडियाएआई की सीओओ कविता भाटिया, इंटेल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल इंजीनियरिंग ग्रुप के महाप्रबंधक श्रीनिवासन अयंगर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक प्रवीण पटेल उपस्थित थे।

हरित ऊर्जा की ओर भारत के बढ़ते कदम!

भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी

● नई दिल्ली, एजेंसी

मंत्री ने भारत-ब्रिटेन अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल की शुरुआत के मौके पर यह जानकारी दी। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा तथा 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता और स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत की गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता अब 272 गीगावाट से अधिक हो गई है। यह घोषणा भारत-ब्रिटेन अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल की शुरुआत के दौरान की गई, जिसमें ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून भी मौजूद थीं। कार्यबल की औपचारिक शुरुआत के मौके पर जोशी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 35 गीगावाट से अधिक सौर तथा 4.61 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल किया।

भारत-अमेरिका व्यापार : 500 अरब डॉलर का सामान आएगा भारत : पीयूष गोयल

● नई दिल्ली, एजेंसी

भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब अमेरिका की ओर एक बड़ा रणनीतिक बदलाव कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर (लगभग 41 लाख करोड़ रुपये) का सामान खरीदने का इरादा रखता है। इस मेगा ट्रेड डील का खाका लगभग तैयार है, जिसे मार्च में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इस समझौते के केंद्र में ऊर्जा विविधता, हाई-टेक उपकरण और एविशन सेक्टर है। अमेरिका के अनुसार भारत ने रूसी तेल के आयात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोकने की प्रतिबद्धता भी जताई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब गिने-चुने देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता।

खरगोन नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म मामला... चार को उम्रकैद

मंडलेश्वर। खरगोन के डाबरिया रोड पर डेढ़ साल पहले दोस्त के साथ स्कूटी से घूमने निकली नाबालिग बालिका से डरा-धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार आरोपितों को न्यायालय ने उम्रकैद व जुर्माने का फैसला सुनाया है। कार्यालय मंडलेश्वर खरगोन के अनन्यत: विशेष लोक अभियोजक प्रदीपसिंह अलावा ने बताया पीड़िता ने स्वयं पुलिस थाना खरगोन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

बीएमसी की हार के बाद राज ठाकरे बदलेंगे पाला? डिप्टी सीएम शिंदे से की मुलाकात

● मुंबई, एजेंसी

मुंबई में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। यह बैठक मुंबई नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक निवास नंदनवन में मुलाकात की। यह बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने बातचीत थी।

दोनों दलों की भूमिका महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात का परिदृश्य केवल शिष्टाचार भेंट से कहीं आगे है, क्योंकि दोनों दल महाराष्ट्र के राजनीतिगत समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

असम कांग्रेस में घमासान

भूपेन बोराह का 'अपमान' वाला इस्तीफा

गौरव गोगोई बोले- ये भाजपा में जाने के बहाने हैं

● असम/नई दिल्ली, एजेंसी

असम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नए सिरे से उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह ने पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। बोराह ने सोमवार को कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिससे पूरे राज्य में राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया। उनकी घोषणा के तुरंत बाद, कुछ स्थानीय पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की थी और अपने फैसले पर पुनर्विचार किया था।

हालांकि, हालिया घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि बोराह ने वास्तव में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस कदम को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर अपने नए हमले में बोराह ने कहा कि उन्होंने पार्टी को अपने 32 साल दिए, लेकिन गौरव गोगोई के हाथों कई मौकों पर उनका अपमान किया गया।

जांच

डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव प्रापर्टी मामला

निगम का खुलेगा संभाग क्रमांक 13 स्वास्थ्य विभाग का उप-कार्यालय

कलेक्टर-निगमायुक्त की पारदर्शी कार्रवाई और सूझबूझ से निपटा मामला

● प्रात :किरण संवाददाता, जबलपुर

शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा जमाने और लीज शर्तों का उल्लंघन करने वाले तत्वों के विरुद्ध नगर निगम ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह और निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार की पारदर्शी कार्यशैली, सूझबूझ और तत्परता के चलते नगर निगम को बाजार मूल्य के अनुसार लगभग 50 करोड़ रुपये की बेशकीमती संपत्ति वापस मिल गई है।

निगमायुक्त अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के स्वामित्व वाले म्युनिसीपल प्लॉट

क्रमांक 51 की लीज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। यह भूखंड लगभग 25 हजार 47 वर्गफुट क्षेत्रफल का है, जिसे अब पुनः निगम के कब्जे में ले लिया गया है। जांच में पाया गया कि लीजधारी द्वारा लीज की शर्त क्रमांक 3, 5, 6, 7, 8 एवं 10 का खुला उल्लंघन किया जा रहा था।

प्राथमिक जांच में सामने आया कि लीजधारी ने निगम की बिना अनुमति के इस भूमि का दान एवं वसीयत कर दी थी। साथ ही, भूखंड का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो लीज शर्तों के विपरीत था। इतना ही नहीं, वर्ष 2020-21 से लीज भू-भाड़ा भी जमा नहीं किया गया। मामले की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रशासन को लगी, जिसके बाद निगमायुक्त ने संपदा विभाग के अधिकारियों से विस्तृत और सूक्ष्म जांच कराई। जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होने पर लीज डीड की कंडिका 6 के तहत निगम ने भूखंड पर पुनः प्रवेश स्थापित करते हुए लीज निरस्त कर दी।

इस कार्रवाई से भूमाफियाओं के मंसूबों पर करारा प्रहार हुआ है। प्रशासन का कहना है कि नगर निगम की संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

निगमायुक्त के अनुसार, अब इस भूमि पर संभाग क्रमांक 13 के स्वास्थ्य विभाग का उप-कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा मिलेगी और जनहित के कार्यों को गति मिलेगी। यह कार्रवाई नगर प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का उदाहरण बनकर सामने आई है।

खास मुलाकात

फ़िल्म धुरंधर के अब्दुल भुट्टावी से ख़ास बातचीत

सारिका राय, जबलपुर

देशभक्ति और आतंकवाद जैसे संवेदनशील विषयों पर आधारित फिल्म 'धुरंधर' एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले भाग की सफलता के बाद अब धुरंधर-2 का टीज़र रिलीज हो चुका है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। मेकर्स का दावा है कि इस बार कहानी और भी ज्यादा गहराई, रोमांच और खुलासों के साथ सामने आएगी।

धुरंधर-2 के टीज़र ने बढ़ाई उत्सुकता

हाल ही में रिलीज हुए टीज़र में तेज़-तर्रार बैकग्राउंड म्यूज़िक, दमदार संवाद और सस्पेंस से भरे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। फिल्म देश के खिलाफ रची जाने वाली साजिशों, आतंकी संगठनों की रणनीतियों और उनके नेटवर्क को उजागर करने का दावा करती है।

26/11 और संसद हमले की घटनाओं पर आधारित कहानी

फिल्म में 2008 में (26/11 मुंबई हमले) और 2001 में (संसद हमला) जैसे बड़े आतंकी घटनाक्रमों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है।

भोपाल के अभिनेता संजय मेहता निभाएंगे अहम भूमिका

फिल्म में भोपाल के वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता संजय मेहता एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने पहले भाग में 'अब्दुल भुट्टावी' का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा था। दूसरे भाग में भी अब्दुल भुट्टावी की भूमिका निभा रहे हैं, जो 26/11 मुंबई हमलों से जुड़ा एक अहम चेहरा माना जाता है।

संजय मेहता ने साझा किए अनुभव

भोपाल के रंगमंच से जुड़े संजय मेहता लंबे समय से थिएटर और अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। थिएटर में मजबूत उपस्थिति के बाद अब वे फिल्मों में भी गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे किरदार निभाना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक और संवेदनशील घटनाओं को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

वार्ड-वार्ड घूमकर निगमायुक्त ने परखी स्वच्छता और जन-सुविधाओं की हकीकत

7 संभागों का किया दौरा, दिए निर्देश

जबलपुर, प्रातः किरण, संवाददाता

शहर की स्वच्छता व्यवस्था को चाक-चैबंद करने और आगामी त्यौहारों के मद्देनजर जन-सुविधाओं का जायजा लेने के लिए नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार एक्शन मोड में नजर आए। मंगलवार सुबह 06:30 बजे से ही निगमायुक्त ने शहर के विभिन्न सात संभागों 3, 4, 8, 12, 13, 14 और 16 का दौरा किया। दो घंटे के इस सघन निरीक्षण के दौरान उन्होंने गलियों, बस्तियों और कॉलोनियों की सफाई व्यवस्था के साथ जल वितरण, प्रकाश, पेंटिंग और अन्य विकास कार्यों की जानकारी ली।

निगमायुक्त ने संभागों के अंतर्गत आने वाले वार्डों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था, सुचारू जल वितरण, स्ट्रीट लाइट और सौंदर्यीकरण हेतु चल रहे पेंटिंग कार्यों का

बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने नाला-नालियों की सफाई और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति देखते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सार्वजनिक और सामुदायिक प्रसाधन केंद्रों का भी अवलोकन किया और वहां स्वच्छता

त्यौहारों को लेकर विशेष सतर्कता

आगामी रमजान माह की तैयारियों को लेकर निगमायुक्त विशेष रूप से संवेदनशील दिखे। क्षेत्रीय वार्ड पार्षदों अख्तर अंसारी, समरीन कुरैशी के साथ उन्होंने वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रद्दी चैकी, नूरी नगर,तालिब शाह चैक, सुब्बा शाह और रजा चैक, अमन चैक आदि का निरीक्षण किया और सभी संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर निगम स्वास्थ्य, जल, उद्यान, लोककर्म, अतिक्रमण आदि विभाग के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

14 करदाताओं के खिलाफ कुर्की कार्रवाई

जबलपुर। शहर की बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को निरंतर बनाए रखने के लिए नगर निगम इन दिनों वसूली को लेकर एक्शन मोड में है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में निगम का पूरा राजस्व अमला मैदान में उतरकर बकाया करों की वसूली सुनिश्चित कर रहा है। वसूली अभियान के संबंध में निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना है, बल्कि ईमानदार करदाताओं के सहयोग से शहर के सौंदर्यीकरण और जनसुविधाओं को बेहतर बनाना भी है। अभियान के दौरान मुख्यालय सहित दमोहनाका, भानतलैया, राँझी और सुहागी संभागों में प्रभावी कार्यवाही की गई। करदाताओं ने निगम की अपील को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही चेक के माध्यम से भुगतान किया। उन्होंने बताया कि संभाग क्रमांक 6 के अंतर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, संभाग क्रमांक 8 भानतलैया अंतर्गत राधाकृष्ण वार्ड, राँझी के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड,गोकलपुर वार्ड, पंडित भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड, संभाग क्रमांक 15 सुहागी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 76 के करीब 14 करदाताओं के खिलाफ कुर्की कार्रवाई की गई।

डिजिटल स्ट्राइक : पर्दे के पीछे साइबर के 'टाइगर'

जबलपुर, प्रातः किरण, संवाददाता

12 माह में 1000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार

बदलते अपराधी तरीकों के बीच साइबर सेल की टीम पुलिस की सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरी है। वर्ष 2025 के दौरान महज 12 महीनों में साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए 1000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका निभाई है। ये वही 'साइलेंट वॉरियर्स' हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर पुलिस की आंख और कान बनते हैं। आज अपराध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधों से लेकर ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड और साइबर क्राइम तक-हर मामले में तकनीकी जांच पहली जरूरत बन गई है। साइबर सेल की टीम कॉल डिटेल रिकॉर्ड (ष्टष्ठक्र), आईपी एड्रेस ट्रैकिंग, लोकेशन एनालिसिस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए अपराधियों तक पहुंच बनाती है। कई बार आरोपी को भनक तक नहीं लगती और पुलिस उसकी पूरी डिजिटल कुंडली तैयार कर लेती है।

डकैती से लेकर साइबर फ्रॉड तक सुलझाए केस

खितौला थाना क्षेत्र में ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई डकैती के मामले में साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों को बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इसी तरह विजय नगर थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी में हुई लूट के खुलासे में भी साइबर टीम की अहम भूमिका रही। बरगी, भेड़ाघाट, माढ़ोताल, आधारताल, पनागर और तिलवारा सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई लूट की घटनाओं में भी तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुंच सकी।

'मुस्कान अभियान' में बड़ी सफलता

साइबर सेल ने 'मुस्कान अभियान' के तहत 600 से अधिक लापता बच्चों और किशोरों को खोजने में मदद की। लोकेशन ट्रैकिंग और डिजिटल डाटा विश्लेषण के जरिए कई परिवारों को उनके बच्चे वापस मिल सके। इसके अलावा फरार इनामी वारंटियों और आदतन अपराधियों की तलाश में भी साइबर सेल ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में तकनीकी सहायता देकर एक हजार से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक अपराधों से निपटने में साइबर टीम की भूमिका लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे सक्रिय रहने वाली यह टीम डिजिटल दुनिया में अपराधियों की हर चाल पर नजर रख रही है। अब अपराधी चाहे जितनी चालाकी बरतें, साइबर के 'टाइगर' उनकी डिजिटल पहचान ढूंढ ही निकालते हैं।

व्यवसायियों के स्वास्थ्य को नई दिशा देगा निरामय

एक मार्च को शहीद स्मारक में कार्यशाला का आयोजन

जबलपुर। वर्तमान समय में उद्योग व्यापार जगत से जुड़े अधिकांश व्यवसायी बंधु तनाव ग्रस्त जीवन जी रहे हैं जिससे वे लंबी अवधि में विभिन्न रोगों से जाने अनजाने ग्रस्त हो जाते हैं। जबलपुर के करदाताओं में दीर्घायु जीवन, उत्तम स्वास्थ्य एवं तनाव रहित जीवन को जीने की कला पर एक अद्भुत कार्यशाला निरामय का आयोजन 1 मार्च रविवार को शहीद स्मारक में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश की शीर्ष उद्योग व्यापार संस्था फेडरेशन आफ मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा डायवेल कोर फाऊंडेशन जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में व्यापारियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं सचेत किया जाएगा। फेडरेशन के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने इस अवसर पर जानकारी दी कि आधुनिक जीवनशैली के परिप्रेक्ष्य में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन एवं आंतरिक प्रसन्नता का समन्वय आज समय की आवश्यकता बन गया है। सभी वर्गों के व्यक्ति आज बढ़ते हुए तनाव से जूझ रहे हैं। इसी उद्देश्य से निरामय का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन, तनाव प्रबंधन एवं संतुलित जीवनशैली से संबंधित चिकित्सक एवं विशेषज्ञ व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न भ्रांतियां सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी प्रचारित की जाती है जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है तथा यह देखने में आया है कि अक्सर हम गलत जानकारी का शिकार भी बनते हैं। व्यापारी के लिए स्वयं के लिए समय निकालना कठिन होता है तथा स्वास्थ्य संतुलन के प्रति उसकी प्राथमिकता कम होती है। स्वास्थ्य संतुलन तथा वैलनेस पर आधारित उक्त कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य की पद्धति पर प्रकाश डाला जाएगा।

इस अवसर पर डायवेल कोर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. परिमल स्वामी ने बताया की जबलपुर में अपनी तरह का यह पहला आयोजन है, जिसमें स्वस्थ जीवन जीने की कला एवं पद्धतियों को आसान तकनीक एवं तरीकों से जनमानस को समझाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिवर्सल आफ हार्ट डिसीज़ पर सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश मेहता भी मुंबई से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जो उपस्थित व्यापारियों के प्रश्नों का जवाब देंगे तथा उनकी भ्रांतियां को भी दूर करेंगे। बैठक में उपस्थित हिमांशु राय, गीता शरत तिवारी, इंद्र कुमार खन्ना, सुनील श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, सीए मनीष कौशल ने बताया कि व्यापारियों के अलावा विभिन्न प्रोफेशनल व्यक्ति जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स विशेषज्ञ, अधिवक्ता, डॉक्टर आदि भी इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

यातायात में बाधक यूनिपोल उखाड़ें — **ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले**

शहर के प्रवेश मार्गों से कब्जे हटाएं

जबलपुर, प्रातः किरण, संवाददाता

जिला सड़क सुरक्षा समिति की आज मंगलवार को संपन्न हुई बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इनमें चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर संकेतक, ब्लिंकर्स, रिफ्लेक्टर्स और प्री-फेब्रिकेटेड डिवाइडर लगाने, डिवाइडर की रंगाई-पुताई करने, प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने तथा जहाँ आवश्यकता हो वहाँ सर्विस रोड बनाने का निर्णय शामिल है। इसके साथ ही बायपास रोड पर अंधमूक चौराहे सहित शहर के सभी प्रवेश मार्गो की सर्विस रोड पर हुये अतिक्रमणों को हटाने तथा भारी वाहनों की अवैध पार्किंग को प्रतिबंधित करने का निर्णय बैठक में लिया गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की मौजूदगी में आयोजित की गई इस बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने व्यस्तम मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ई-रिक्शा और पिकअप वाहनों के संचालन पर निश्चित समय के लिये रोक लगाने, ई-रिक्शा संचालन के लिये रुट निर्धारित करने तथा मंडला और डिंडौरी जाने वाली यात्री बसों के शहर के भीतर संचालन बंद करने मंडला और डिंडौरी मार्ग पर बस स्टैंड के लिये स्थान चिन्हित करने का फैसला भी लिया गया। शहर के भीतर यातायात में बाधक यूनिपोल को चिन्हित कर हटाने के निर्देश भी बैठक में दिये गये। बैठक में नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी, स्मार्ट सिटी के सीईओ अनुराग सिंह तथा लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बताया गया कि रानीताल चौराहा और बल्देवबाग चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल जल्द ही चालू हो जाएंगे। दीनदयाल चौक की रोटरी का नया ले-आऊट तैयार हो जाने पर यहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल लगाये जाएंगे।बलदेवबाग से ट्रांसपोर्टर्स के ऑफिसों को चाण्डालभाटा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में शीघ्र शिफ्ट कराने के निर्देश बैठक में दिये गये। चौराहों पर यातायात को सुगम बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने जहाँ आवश्यकता हो वहाँ प्री-फेब्रिकेटेड अथवा स्थाई डिवाइडर बनाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। पाटन और जबलपुर मार्ग पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये इस मार्ग पर बसे बड़े गांवों के समीप सर्विस रोड बनाने का सुझाव दिया गया ताकि लोग वाहनों से सीधे मुख्य सड़क पर न आयें। बैठक में बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने महाराजपुर, गांधीग्राम और सिहोरा के बरगी मोहला में फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसी प्रकार रमनपुरा घाटी में मार्ग का रि-एलायमेंट किया जा रहा है। तिलवारा-लम्हेटाघाट मार्ग पर दुर्घटनाएं रोकने सर्विस रोड और यू-टर्न बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गये। बायपास और राजमार्ग पर डिवाइडर में बनाये गये अवैध कट को दूर करने के निर्देश सबंधित निर्माण एजेंसियों को दिये गये। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बायपास पर अवैध पार्किंग को रोकने अंधमूक चौराहे से रिंगरोड तक ट्रकों की पार्किंग के लिये 14 स्थान चिन्हित किये गये हैं।

एलटीटी-दानापुर और पुणे-दानापुर के बीच जबलपुर होकर चलेगी डेली स्पेशल

पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, जबलपुर, कटनी एवं सतना स्टेशनों पर ठहराव

जबलपुर। रेलवे द्वारा आगामी त्यौहारों होली पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में मध्य रेल से प्रारम्भ/टर्मिनेट होने वाली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01143/01144 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-दानापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस व पुणे-दानापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल से होकर अपने गंतब्य को जाएगी।

गाड़ी संख्या 01143 एलटीटी से दानापुर स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 21 से 28 फरवरी 2026 तक एवं होली के अवसर पर 01 से 08 मार्च 2026 तक प्रतिदिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान कर इटारसी रात 21:10 बजे, पहुँचकर अगले दिन जबलपुर 02:25 बजे, कटनी 04:00 बजे, सतना 07:10 बजे पहुँचकर मार्ग से होते हुए सायं 18:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01144 दानापुर से एलटीटी स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 22 फरवरी से 01 मार्च 2026 तक एवं होली के अवसर पर 02 से 09 मार्च 2026 तक प्रतिदिन दानापुर स्टेशन से रात 21:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन प्रयागराज छिवकी प्रातः 05:45 बजे, सतना 10:05 बजे, कटनी 12:00 बजे, जबलपुर दोपहर 13:45 बजे, इटारसी 17:30 बजे पहुंचकर और तीसरे दिन 07:45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुँचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 01449 पुणे से दानापुर स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 21 से 28 फरवरी 2026 तक एवं होली के अवसर पर 01 से 08 मार्च 2026 तक प्रतिदिन पुणे स्टेशन से दोपहर 15:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी प्रातः 05:40 बजे, जबलपुर सुबह 09:05 बजे, कटनी 10:30 बजे, सतना दोपहर 12:55 बजे पहुँचकर मार्ग से होते हुए तीसरे दिन 02:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01450 दानापुर से पुणे स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 23 फरवरी से 02 मार्च 2026 तक एवं होली के अवसर पर 03 से 10 मार्च 2026 तक प्रतिदिन दानापुर स्टेशन से प्रातः 05:00 बजे प्रस्थान कर सतना 18:10 बजे, कटनी 19:50 बजे, जबलपुर 21:35 बजे, पहुँचकर अगले दिन इटारसी 01:20 बजे और सायं 18:15 बजे पुणे स्टेशन पहुँचेगी।

47 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं, एनजीटी में याचिका दायर

जबलपुर। जलजीवन मिशन द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर के घरों में सप्लाई हो रहा 47 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। अत्यंत दूषित पानी की सप्लाई को देखते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के लिए एनजीटी में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने बताया कि जबलपुर शहर की 80 प्रतिशत पाइप-लाइनें नाले-नालियों से होकर गुजर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप-लाइन की औसतन उम्र 20 वर्ष होती है, लेकिन कई स्थानों पर यह लाइनें 50-50 सालों से बदली नहीं गई हैं, जिसके चलते बार-बार लीकेज हो रहे हैं और लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंच रहा है।

अब तक तैयार नहीं हुई डीपीआर- याचिकाकर्ता ने बताया कि इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी नगर निगम ने अब तक नाले-नालियों से गुजरने वाली पाइप-लाइनों को बदलने के लिए चिन्हित नहीं किया, न ही कोई डीपीआर बनाई गई। उन्होंने एनजीटी से निगम को इस संबंध में आदेश देने की मांग की है, ताकि जल्द से जल्द शहरवासियों को शुद्ध पानी मुहैया हो सके।

संक्षिप्त समाचार

136 किसानों के भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ

जबलपुर। मझौली तहसील अंतर्गत वृहताकार सेवा सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित उपार्जन केन्द्र पर धान का वि य करने वाले किसानों के सत्यापन की कार्यवाही के बाद सभी मापदंडो पर पात्र पाये गये 174 किसानों में से 136 किसानों को भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शेष 38 किसानों को भुगतान की कार्यवाही जांच में अपात्र पाये गये उन किसानों से वसूली के बाद किया जायेगा जिन्हें उपार्जन राशि का भुगतान हो चुका है। जिला उपार्जन नियंत्रक के मुताबिक वृहताकार सेवा सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित उपार्जन केन्द्र पर धान खरीदी में अनियमितताओं की शिकायत की जांच में दोषी पाये गये खरीदी केन्द्र प्रभारी रत्नेश भट्ट एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर अमन सेन के विरूद्ध पूर्व में ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस उपार्जन केन्द्र पर धान वि य करने वाले किसानों की जानकारी का प्रमाणीकरण पुलिस के माध्यम से कराया गया था तथा कई ऐसे किसान पाये गये जिनके द्वारा धारित कृषि भूमि स्थल से काफी दूर खरीदी केन्द्र का चयन किया गया था।

महाकोशल कॉलेज में कॅरियर मेला आज

जबलपुर। स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना एवं जिला रोजगार कार्यालय, जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकोशल स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर में एक दिवसीय युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार जिला स्तरीय कॅरियर अवसर मेला आगामी 19 फरवरी को महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित किया जा रहा है। उक्त मेला आयोजन का पोस्टर रिलीज किया गया। इस अवसर पर प्रो. अरुण शुक्ल, मेला संयोजक ने बताया कि यह जबलपुर जिले के युवाओं के लिए प्लेसमेंट का सुनहरा अवसर है। जिले के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, आईटीआई एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को मेले में सम्मिलित होने के लिए सूचना प्रदान कर दी गई। इस मेले में लगभग 35 कंपनियां प्लेसमेंट हेतु उपस्थित रहेगी। उद्यमिता के अंतर्गत महाविद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये उत्पादों की प्रदर्शनी मेला का आकर्षण केंद्र रहेगी। इन उत्पादों का मेले में वि य किया जायेगा। मेले में युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार अवसरों की जानकारी एवं मार्गदर्शन तथा युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए शासकीय विभागों के विभिन्न स्टॉल भी लगाये जायेंगे। प्रो. शुक्ल ने जिले के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के अधिक से अधिक विद्यार्थियों से मेले में उपस्थित होने की अपील की है। इस अवसर पर महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष आशीष राव, प्राचार्य डॉ. अलकेश चतुर्वेदी, एम.एस. मरकाम, उपसंचालक, जिला रोजगार कार्यालय, जबलपुर, ज्योति रामरेडी, डॉ. ज्योति जुनगरे, डॉ. महेन्द्र कुमार कुशवाहा, उपस्थित रहे।

धूमधाम से निकला चादर जुलूस

जबलपुर। मोमिनपुरा तलैया गोहलपुर स्थित दरगाह हजरत बहादुर अली शाह रह. तथा बाबा अब्दुल खालिक रह. का सालाना दो दिनी उर्स का आगाज गुस्ल से हुआ। दरगाह के बबलू बाबा ने बताया कि सज्जादा इकरार हुसैन रशीदी की सरपरस्ती में दोपहर मोमिनपुरा से चादर जुलूस निकाला गया जो गोहलपुर, मंसूराबाद, मछली मार्केट, नालबंद मोहल्ला, चार खंभा होते हुए दरगाह पहुंचा, जहां चादर व गुलपोशी की गई। इसके बाद शाम 7 बजे से लंगर आयोजित हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। रात्रि 11 बजे से महफिले कव्वाली में मुकामी कव्वालों ने अपने कलाम पेश किये, देर रात तक चले कार्य म मे श्रोता मंत्र मुग्ध हो गये। उर्स के दूसरे दिन बुधवार शाम 4 बजे से रंग महफ़िल व कुल होगा।

जरूरतमंदों को बांटे गैस कनेक्शन

जबलपुर। हर गरीब परिवार को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिले, इसी उद्देश्य के साथ समाजसेवी मंगन सिद्दीकी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में विगत दिवस पूर्व विधानसभा के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के पम्प हाउस मैदान में लगभग 65 गैस कनेक्शन बांटे गए। इस दौरान आयोजित वितरण कार्य म में समाजसेवी मंगन सिद्दीकी के साथ शमशुल हसन, नौशाद बक्श, हाजी हसन खान, ताजुद्दीन, सुहैल सौदागर, सिराज अंसारी, गुलाम नबी, माबूद खान, रहीम अंसारी, राजू वक़ार, आज़ाद, भोला, सुहैल, अकरम आदि के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

साढ़े तीन करोड़ की फूड सेफ्टी लैब बनी 'शोपीस'

जांच के लिए अब भी राजधानी पर निर्भर संस्कारधानी

जबलपुर, प्रातः किरण,संवाददाता

डुमना क्षेत्र में करोड़ों की लागत से तैयार की गई फूड सेफ्टी लैब (खाद्य प्रयोगशाला) अब तक शुरू नहीं हो सकी है। करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च कर आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित की गई यह लैब एनएबीएल प्रमाणन के अभाव में बंद पड़ी है। नतीजतन शहर के खाद्य सैंपलों की जांच आज भी भोपाल भेजकर करानी पड़ रही है। लैब का संचालन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज़ (एनएबीएल) के प्रमाणन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाणित जांच रिपोर्ट अदालत में मान्य नहीं होती। बताया जा रहा है कि एनएबीएल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है और निरीक्षण की तारीखें बार-बार आगे बढ़ाई जा रही हैं।

मिलावटखोरों को मिल रहा फायदा

स्थानीय स्तर पर जांच सुविधा उपलब्ध न होने से दूध, तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भोपाल भेजे जा रहे हैं। वहां से रिपोर्ट आने में हफ्तों लग जाते हैं। इस देरी का सीधा फायदा मिलावटखोर उठा रहे हैं। शहर में नकली दूध, केमिकल युक्त मसाले और एक्सपायर्ड सामान की बिक्री की शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया धीमी होने से आरोपियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो पा रही। हाल ही में कुछ मामलों में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त की गई, लेकिन रिपोर्ट लंबित होने से दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अटकी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डुमना की लैब चालू हो जाए तो स्थानीय स्तर पर त्वरित जांच संभव होगी और मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

मार्च-अप्रैल में आ सकती है टीम

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एनएबीएल प्रमाणन अनिवार्य प्रक्रिया है। विभागीय प्रयास जारी हैं और संभवत: मार्च या अप्रैल में निरीक्षण टीम आएगी। प्रमाणन मिलते ही लैब में नियमित जांच कार्य शुरू कर दिया जाएगा।फिलहाल करोड़ों रुपये की लागत से बनी यह लैब 'सफेद हाथी' साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण सुविधा का वर्षों तक बंद रहना सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। शहरवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही यह प्रयोगशाला कागजों से निकलकर जमीन पर सक्रिय होगी और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनेगी।

मिलावटी मिठाईयां और अमानक पनीर बेचने वालों पर कार्रवाई

नर्मदा रोड स्थित हीरा स्वीट्स समेत 13 प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख का जुर्माना

जबलपुर। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की सख्त कार्रवाई में शहर के 13 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 4 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्याय निर्णायक अधिकारी, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत ने यह दंड अधिरोपित किया। कार्रवाई का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित और मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

कार्रवाई के तहत नर्मदा रोड स्थित हीरा स्वीट्स के विक्रेता पर बिना खाद्य अनुज्ञप्ति कारोबार करने और मिथ्याछाप बूंदी लड्डू बेचने के आरोप में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं साउथ सिविल लाइन स्थित दीपक डेयरी और नर्मदा रोड स्थित श्री डेयरी के संचालकों पर अमानक पनीर बेचने के आरोप में 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह रांझी स्थित अलका भंडार पर मिथ्याछाप मलाई बर्फी बेचने के मामले में 50 हजार रुपए, जबकि साकेतनगर रांझी स्थित स्नैक्स अटैक पर बिना खाद्य पंजीयन कारोबार करने के कारण 15 हजार रुपए का दंड लगाया गया। इसके अलावा मझौली स्थित सुनील कुमार जैन गोदाम पर 30 हजार, हॉट एन चीप रेस्टोरेंट, रांझी पर 15 हजार, श्री गणेश अनाज भंडार, निवाड़गंज पर 25 हजार, सिंघई इंटरप्राइजेस, शास्त्री ब्रिज पर 20 हजार, और आदेश आइसक्रीम, अंपायर टॉकीज रोड पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अन्य मामलों में राम अनाज भंडार (गढ़ा फाटक) पर 20 हजार, बहरानी फार्मा (द्वारका नगर), अशोक गुप्ता सब्जी विक्रेता (कृषि उपज मंडी) और पारस किराना (मुकादमगंज) पर 10-10 हजार रुपए का दंड लगाया गया। वहीं लक्ष्य अग्रवाल (अधारताल) और सुप्रीम प्लास्टिक (भेड़ाघाट रोड) पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को एक माह के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य पंजीयन या अनुज्ञप्ति निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों की तलाश

जबलपुर। थाना विजयनगर मारपीट में घायल को उपचार हेतु गैलेक्सी अस्पताल उखरी तिराहा मे भर्ती होने की सूचना पर गैलेक्सी अस्पताल पहुंची पुलिस को खेमराज उर्फ पिन्टू पटेल उम्र 55 साल निवासी लक्ष्मीपुर विजय श्री टावर के पीछे विजयनगर ने बताया कि वह कान्ट्रेक्टर है दिनाँक 17/02/26 के रात्रि लगभग 10 बजे अपनी मोटर साइकिल से पुराने घर भूमि तलैया बडा

पदोन्नति में आरक्षण मामले में उभय पक्षों की बहस पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में स्पष्टीकरण दिया गया कि हर विभाग में प्रमोशन के लिए कमेटी बनेगी। सरकार का कहना है कि कमेटी सुनिश्चित करेगी आरक्षण नियमों का पालन हो। सरकार ने यह भी कहा कि जो पूर्व में आरक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग में पदोन्नति प्राप्त किए हैं, उनकी गणना उनके वर्ग में ही की जाएगी। एससी व एसटी का अर्थात 16 एवं 20 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है। दलील दी गई कि वर्ष 2002 के नियमों को हाईकोर्ट के द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है। इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है, इसके बावजूद मप्र शासन ने महज नाम मात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर जस के तस नियम बना दिये। मामले में उभयपक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

कई इलाकों से गरजा निगम का बुल्डोजर, हटाए कब्जे

जबलपुर, प्रातः किरण संवाददाता

निगमायुक्त के अतिक्रमण मुक्त जबलपुर और सुगम यातायात को बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के निर्देश के तहत शहर के विभिन्न इलाकों से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की हई। अपर आयुक्त अरविंद शाह के मार्गदर्शन में की गई कार्यवाही के संबध में अतिक्रमण प्रभारी मनीष कुमार तड़से ने बताया कि कटंगा ब्रिज के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अनधिकृत अतिक्रमण हटाए गए साथ सड़क किनारे लगाए ठेले टपरों को अलग किया गया। वहीं बड़ी ओमती आनंद साईकिल वाला फुटफात पर लगे अवैध अतिक्रमण कर लगाए गए साईकिलो को हटाने की कार्यवाही की गई ओर चेतावनी दी गई। मरघटाई करिया पाथर में अतिक्रमण अमले द्वारा कार्यवाही करते हुए नाले के ऊपर अवैध निर्माण कार्य रोका गया।

इसके अलावा निगमायुक्त के निर्देशानुसार सिविक सेंटर ओर समदड़िया मॉल क्षेत्र में लगातार कार्यवाही की जा रही हे उसी क्रम में लगातार क्षेत्र में अमले

द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। गीता भवन क्षेत्र को सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाएं रखने के लिए आज कार्यवाही की गई जिसमें अनधिकृत कावड़ी की दुकान हटाई गई। गढ़ा बाजार में निर्माणाधीन सड़क तथा नाला में बाधक 3 मकानों के चिन्हित भाग को हटाने की कार्यवाही की गई जिससे सड़क निर्माण पूरा किया जा सके। तैय्यब अली चौपाटी में अनधिकृत अतिक्रमण अलग करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अखिलेश सिंह भदौरिया, एकता रघुवंशी तथा सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी दीपेंद्र सिंह रावत,दल प्रभारी एवं कर्मचारीगण लक्षण कोरी, नदीम खान, जोसफ प्रवीण, अंकित पारस, वीरेंद्र मिश्रा, कुलदीप त्रिपाठी, दुर्गा राव, अभिषेक समुद्रे, ब्रज किशोर तिवारी एवं अन्य संबंधित स्टाफ उपस्थित रहा।

शिक्षा

जिले के 195 स्कूलों में सिर्फ 70 में ही लैब स्थापित

125 स्कूलों में नहीं बनी लैब, किताबों के सहारे विद्यार्थी

जबलपुर, प्रातः किरण, संवाददाता

जिले में सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने की योजना जमीनी स्तर पर अधूरी नजर आ रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रत्येक हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में आधुनिक आईसीटी (इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) लैब स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2021 से इस योजना पर अमल शुरू हुआ, लेकिन करीब पांच साल बाद भी जिले के 195 स्कूलों में से केवल 70 स्कूलों में ही लैब बन पाई हैं, जबकि 125 स्कूल आज भी लैब विहीन हैं।

इस स्थिति के कारण हजारों छात्र-छात्राएं प्रायोगिक शिक्षा से वंचित हैं और केवल किताबों के सहारे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। खासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों में विद्यार्थियों को सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है। माइक्रोस्कोप से अध्ययन, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कंप्यूटर आधारित प्रयोग जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी निजी स्कूलों के छात्रों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं।

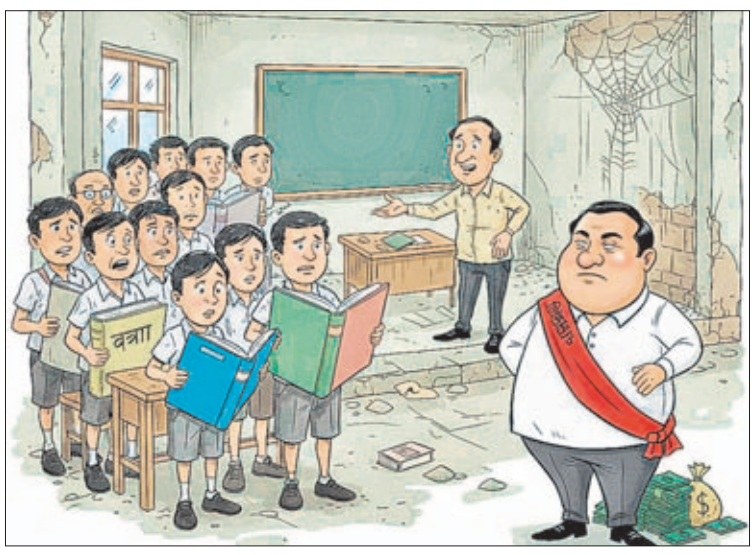

90 स्कूलों को मिली स्वीकृति

शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 70 स्कूलों में लैब तैयार हो चुकी हैं। इसके अलावा 90 और स्कूलों में लैब निर्माण की स्वीकृति मिल गई है और जल्द कार्य शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि पाटन, कुंडम, सिहोरा, मझौली और ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 25 स्कूलों में अब तक लैब के लिए स्वीकृति भी नहीं मिली है। यहां के विद्यार्थियों को कब तक प्रयोगशाला सुविधा मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं है।

ग्रामीण स्कूलों की घोर अनदेखी

सबसे ज्यादा लैब विहीन स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। कई हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल माध्यमिक शालाओं के भवन में संचालित हो रहे हैं, जहां पर्याप्त कक्षाएं तक नहीं हैं। ऐसे में लैब निर्माण की संभावना और भी कम हो जाती है। शहरों के कुछ स्कूलों में पहले से बनी लैब को अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण विद्यार्थियों को डिजिटल और प्रायोगिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है।

बजट होने के बावजूद नहीं दिखा सुधार

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पिछले वर्ष पेयजल और शौचालय मरम्मत के लिए जारी राशि भी पूरी तरह उपयोग नहीं हो सकी और लैप्स हो गई।विशेषज्ञों का मानना है कि लैब बनने से विद्यार्थियों को प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, डिजिटल ज्ञान बढ़ेगा, बोर्ड परीक्षाओं में प्रैक्टिकल अंक बेहतर आएंगे और ग्रामीण छात्र भी आईटी, इंजीनियरिंग व मेडिकल जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम हो सकेंगे। फिलहाल सवाल यह है कि बिना लैब के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी निजी स्कूलों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

किसानों से धोखाधड़ी का बड़ा मामलाः अब तक 40 से अधिक ट्रैक्टरों की बिक्री का आरोप

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता। जबलपुर जिले में किसानों से ट्रैक्टर लेकर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का मामला सामने आया है। मझगवां थाना क्षेत्र के घुघरी कला टिकरिया निवासी किसान आशीष पटेल ने पुलिस को बताया कि उनका ट्रैक्टर किराए पर लेने वाले दो लोगों ने उसे ही बेच दिया। पीड़ित किसान आशीष पटेल ने एसपी कार्यालय में दी गई शिकायत में बताया कि दीपक पुरी और कृष्ण कुमार यादव नाम के दो व्यक्तियों ने उनका ट्रैक्टर किराए पर लिया था। आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी कागजात तैयार करके वही ट्रैक्टर भारत सिंह लोधी को बेच दिया। इस धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित ने सिहोरा के थाना और एसडीओ से की थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई किसानों के साथ धोखा, बड़ा गिरोह सक्रिय आशीष पटेल का आरोप है कि यह कोई इक्का-दुक्का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संगठित गिरोह है। उन्होंने बताया कि दीपक पुरी और कृष्ण कुमार यादव पर मझौली, गोसलपुर और मझगवां थाना क्षेत्रों में भी इसी तरह की कम से कम 30 से 40 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों पर यह भी आरोप है कि वे इसी तरह फर्जीवाड़ा करके ट्रैक्टरों को गाडरवारा, गोटेगांव, सागर और दमोह जिलों में बेच चुके हैं।

अजय गुप्ता ने संभाली पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की कमान

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में प्रशासनिक फेरबदल के साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुभवी अधिकारी श्री अजय गुप्ता (2009 बैच) ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक का पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं, जिनमें निर्बाध बिजली आपूर्ति और वितरण प्रणाली का आधुनिकिकरण सबसे ऊपर है। पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि कंपनी का प्राथमिक लक्ष्य पूर्व क्षेत्र के सभी जिलों में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना है।

मप्र बजट मिली-जुली प्रतिक्रिया : व्यापारी कल्याण कोष न बनने से निराशा, फिर भी अधोसंरचना निवेश से बढ़ी उम्मीद

37,500 नौकरियों की घोषणा, व्यापार जगत ने जताई उम्मीद-चिंता

प्रातः किरण संवाददाता, जबलपुर।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये के बजट पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों ने मिश्रित प्रतिं याएं दी हैं। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में पेश किए गए इस बजट को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में "GYANI" थीम–गरीब कल्याण, युवा शक्ति , अन्नदाता, नारी शक्ति तथा अधोसंरचना एवं उद्योग–पर आधारित बताया गया है।स्टार्टअप और निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष कर राहत व वित्तीय प्रोत्साहन की कमी को कमजोर पक्ष बताया। उन्होंने बढ़ते राज्य ऋण पर भी चिंता जताई।

बजट विकसित मप्र वाला है

जबलपुर उत्तर मध्य के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने बजट को 'विकसित मध्यप्रदेश' के विजन को साकार करने वाला बताया। उनके अनुसार 37,500 सरकारी नौकरियों की घोषणा, 15 हजार शिक्षकों और 22,500 पुलिस पदों पर भर्ती, शिक्षा के लिए 31,953 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 24,144 करोड़ रुपये का प्रावधान युवाओं और आमजन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटन करते हुए वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया गया है।

जनविश्वास का बजटः पूर्व महापौर

पूर्व महापौर प्रभात साहू ने इसे जनविश्वास का बजट बताया, जबकि महाकोशल चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अखिल मिश्र ने व्यापारी कल्याण कोष की घोषणा न होने पर निराशा जताई, फिर भी अधोसंरचना और रोजगार बढ़ोतरी को सकारात्मक कदम बताया।

बजट संतुलित और दूरदर्शी

संभागीय अध्यक्ष कैट दीपक सेठी ने बजट को संतुलित और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। वहीं फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में बड़े प्रावधानों की सराहना की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई,

कागजों में उड़द की खेती, जमीन पर खड़ा है करोड़ों का अवैध निर्माण, प्रशासन ने शुरू की जांच

उत्तम स्वामी की बढ़ी मुश्किलें: जबलपुर आश्रम निकला अवैध

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता।

भेड़ाघाट के हीरापुर बंधा गांव में स्थित हाई-प्रोफाइल संत उत्तम स्वामी का आलीशान आश्रम अब कानूनी जांच के घेरे में है। दुष्कर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे उत्तम स्वामी के खिलाफजिला प्रशासन ने जमीन संबंधी दस्तावेजों की जांच तेज कर दी है। ताजा खुलासे के अनुसार, जिस जमीन पर यह भव्य आश्रम खड़ा है, वह राजस्व रिकॉर्ड में आज भी 'कृषि भूमि' के रूप में दर्ज है। 17 फरवरी को लोक सेवा केंद्र से जारी खसरा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना लैंड डायवर्शन (व्यपवर्तन) और उचित अनुमति के इस साम्राज्य का विस्तार किया गया है।

कागजों में फसल, जमीन पर महलः नियमों की धज्जियां

सरकारी दस्तावेजों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। खसरा नंबर 46/1 के रिकॉर्ड के मुताबिक, इस जमीन पर आज भी 'उड़द' की फसल उगाई जा रही है, जबकि हकीकत में यहाँ 1 एकड़ (67 हजार वर्गफीट) से अधिक क्षेत्र में पक्का निर्माण हो चुका है। साल 2025 में हस्तांतरित हुई इस जमीन पर

बिना ग्राम पंचायत या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के आलीशान परिसर खड़ा कर दिया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजनीतिक रसूख के कारण अब तक अधिकारी इस अवैध निर्माण पर आंखें मूंदे बैठे थे।

दो शिष्यों में बंटवारा, कथा के पंडाल तक पहुंचा विवाद

जांच में एक और पेच सामने आया है कि यह विशाल भूखंड दो हिस्सों में विभाजित है। एक हिस्सा उत्तम स्वामी के नाम है, तो दूसरा हिस्सा उनके गुरुभाई मंगलनाथ स्वामी के नाम दर्ज है। हाल ही में आयोजित भागवत कथा का भव्य पंडाल मंगलनाथ के हिस्से वाली जमीन पर लगाया गया था। चूंकि पूरी जमीन का मद कृषि है, इसलिए इतने बड़े सार्वजनिक आयोजन की अनुमति और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन अब दोनों स्वामियों के स्वामित्व वाले दस्तावेजों की सूक्ष्मता से पड़ताल कर रहा है।

प्रशासन की सख्तीः क्या चलेगा बुलडोजर

दुष्कर्म के आरोपों और अवैध निर्माण की पुष्टि के बाद अब प्रशासन बैकफुट पर नहीं दिख रहा है। जबलपुर के शहपुरा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि भूमि पर बिना डायवर्शन के पक्का निर्माण पूर्णतः अवैध है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि यदि जांच रिपोर्ट में उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो अवैध हिस्से को ध्वस्त करने या भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकती है। रसूख के दम पर खड़ा किया गया यह अवैध किला अब जमींदोज होने की कगार पर है।

जांच शुरू,सख्त कार्रवाई होगी

राजस्व नियमों के तहत कृषि भूमि पर बिना डायवर्शन के निर्माण प्रतिबंधित है। हीरापुर बंधा आश्रम के रिकॉर्ड मंगाए गए हैं, यदि उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मदन सिंह रघुवंशी, एसडीएम, शहपुरा (जबलपुर)

एसडीएम का रीडर 5000 की रिश्वत लेते पकड़ाया

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता। मंडला के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के रीडर को बुधवार लोकायुक्त दल ने पांच हजार रूपयों की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। यह रिश्वत खसरे में गलती से नाम गलत होने पर उसे सुधारने के लिए ली जा रही थी। टीम ने आवेदक की शिकायत की जांच करने के बाद ट्रेप कार्यवाही की। लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि आवेदक गेंदलाल निवासी ग्राम दरगड़ तहसील निवास की शिकायत पर निवास के एसडीएम कार्यालय में छापा मारा गया। इसमें आरोपी सहायक ग्रेड- 3 काशीराम मरावी को 5000 रूपए लेते हुए पकड़ा है। एसपी का कहना है कि गेंदलाल के पिताजी की कृषि भूमि के खसरे में इसके पिता जी का नाम त्रुटिवश मूल चंद के स्थान पर फूलचंद दर्ज है। खसरे में उक्त नाम सुधार करवाने के एवज में आरोपी काशीराम मरावी, सहायक ग्रेड-3 रीडर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवास द्वारा 10000 रु रिश्वत की मांग की जा रही थी। 18 फरवरी को आरोपी उपरोक्त को 5000 लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। 'ट्रेप दल में टीएलओ निरीक्षक शशिकला मस्कुले, निरीक्षक जितेन्द्र यादव, उप निरीक्षक शिशिर पांडेय मौजूद रहे।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

क्षेत्राधिकार के आधार पर भोजशाला प्रकरण वापस इंदौर खंडपीठ भेजा गया

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता।

धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले की कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए इस प्रकरण को वापस इंदौर खंडपीठ स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि चूंकि धार जिला भौगोलिक रूप से इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत आता है, इसलिए नियमानुसार इसकी सुनवाई वहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज तत्काल इंदौर भेजे जाएं। इससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जबलपुर मुख्य पीठ में सूचीबद्ध हुआ था।

एएसआई की 98 दिवसीय सर्वे रिपोर्ट पर टिकी नजरें

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत को बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 98 दिनों की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट वर्तमान में हाईकोर्ट की सुरक्षा में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, इस सीलबंद रिपोर्ट को अब खुली अदालत में खोला जाना है, ताकि सभी पक्षकार इस पर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकें।

23 फरवरी को इंदौर हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई

अब इस बहुचर्चित मामले का अगला पड़ाव 23 फरवरी 2026 को इंदौर हाईकोर्ट में होगा। इस दिन बड़ी बेंच के समक्ष एएसआई की गोपनीय रिपोर्ट को अनसील किए जाने की प्रबल संभावना है। कानूनी जानकारों के अनुसार, यह सुनवाई भोजशाला विवाद की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है।

मानेगांव के ग्रामीणों का खदान परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन

15 दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता। आदर्श आदिवासी ग्राम समिति मानेगांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार को जबलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर, खनिज अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी और नल-जल विभाग को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुंगेली बरगी स्थित खदान परियोजना में तय शर्तों और परामर्श अधिकारी के आश्वासनों का पालन नहीं होने का आरोप लगाया। समिति अध्यक्ष बी.एल. मरकाम, उपाध्यक्ष विनोद कोल, सचिन किशन मरावी और कोषाध्यक्ष दसवीं सलाम ने बताया कि खदान संचालन शुरू होने से पहले गांववासियों को कई सुविधाओं का आश्वासन दिया गया था। इनमें खदान क्षेत्र की तारबंदी, स्कूल व आंगनबाड़ी परिसर तथा परिवहन मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण, धूल नियंत्रण के लिए दिन में तीन बार पानी का छिड़काव, सड़क मरम्मत व नाली सफाई के लिए वार्षिक राशि, नए वाहनों का उपयोग तथा नियमित मॉनिटरिंग शामिल थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सभी वादे धरातल पर पूरे नहीं हुए, जिससे धूल, प्रदूषण और सड़क क्षति की समस्या बढ़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो गांव में खदान से जुड़े वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा और खदान संचालन ठप किया जाएगा।

अंधी हत्या का पर्दाफाश

प्रेमी ही निकला तनु का कातिल

वैलेंटाइन डे पर प्रेमी ने ही रची थी प्रेमिका की हत्या की साजिश, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता।

संस्कारधानी के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया गांव में वैलेंटाइन डे के दिन हुई युवती की अंधी हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिसे युवती अपना प्रेमी समझकर सात जन्मों का साथ निभाने के सपने देख रही थी, उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी योगेश उर्फ ईशु और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कांफ्रेंस में एसपी सम्पत उपाध्याय ने मामले की जानकारी दी।

शादी के विवाद में खूनी खेल

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका तनु चक्रवर्ती, मुख्य आरोपी योगेश उर्फईशु पर लंबे समय से शादी करने का दबाव बना रही थी। योगेश उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और इसी मंशा से उसने हत्या की खौफनाक साजिश रची। 14 फरवरी को जब पूरी दुनिया प्रेम का उत्सव मना रही थी, तनु अपने घर से किसी शादी समारोह में जाने का बहाना बनाकर निकली थी। वहां से योगेश उसे अपने तीन दोस्तों,पंकज बर्मन, राजा उर्फ अंकित श्रीवास और एक अन्य साथी के साथ सिमरिया गांव के पास ले गया।

एआई तकनीक से हुई शिनाख्तः ऐसे बेनकाब हुए हत्यारे

घटनास्थल पर शादी की बात को लेकर तनु और योगेश के बीच फिर से विवाद शुरू हुआ। तैश में आकर योगेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तनु का गला दबाया और जब वह बेसुध हो गई, तो साक्ष्य मिटाने और पहचान छुपाने की नीयत से भारी पत्थर से उसका चेहरा कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शव मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना थी। चेहरा बुरी तरह कुचला होने के कारण पहचान संभव नहीं थी, जिसके लिए पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड फोटो जारी की। इस तकनीक की मदद से मृतका की शिनाख्त तनु चक्रवर्ती के रूप में हुई। इसके बाद कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस मुख्य आरोपी योगेश तक पहुंची। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके दो साथियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है।

कार्रवाई

4 नाबालिग बच्चियों को आरपीएफने रेस्क्यू किया

शक्तिपुंज एक्सप्रेस में मानव तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता।

पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल अंतर्गत कटनी आरपीएफ ने अपनी तत्परता और खुफिया सूचना के आधार पर एक बड़े संभावित अपराध को विफल कर दिया है। हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस में सफर कर रही झारखंड की चार नाबालिग लड़कियों को संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। आरपीएफ की इस कार्रवाई ने न केवल बच्चियों को असुरक्षित हाथों में जाने से बचाया, बल्कि मानव तस्करी के नेटवर्क की ओर भी इशारा किया है।

खुफिया सूचना पर घेराबंदी और फिल्मी स्टाइल में चैन पुलिंग

मामले की शुरुआत आरपीएफ को मिली एक गोपनीय सूचना से हुई। सूचना मिली थी कि झारखंड के पलामू जिले की चार नाबालिग बच्चियों को दो संदिग्ध युवक बहला-फुसलाकर जबलपुर के रास्ते गुजरात ले जा रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ निरीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तत्काल 11 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में बाल संरक्षण तंत्र के सदस्यों को भी शामिल किया गया ताकि बच्चियों की सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सुनिश्चित की जा सके। जब ट्रेन न्यू कटनी जंक्शन की ओर बढ़ रही थी, तभी टीम ने घेराबंदी शुरू की। जैसे ही ट्रेन कटनी साउथ के आउटर पर पहुँची, संभवतः संदिग्धों को पुलिस की मौजूदगी का अंदेशा हो गया। इसी बीच ट्रेन में अचानक चैन पुलिंग की गई। ट्रेन रुकते ही चारों बच्चियां नीचे उतरकर भागने लगीं। पुलिस ने मुस्तैदी

दिखाते हुए पीछा किया और चारों को सुरक्षित हिरासत में ले लिया। हालांकि, इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर साथ में मौजूद संदिग्ध युवक मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है।

बाल विवाह का दबाव या तस्करी का जाल

हिरासत में लेने के बाद जब बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने बच्चियों से प्रारंभिक पूछताछ की, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बच्चियों ने बताया कि उनके परिजन उन पर कम उम्र में शादी (बाल विवाह) करने का दबाव बना रहे थे। इसी दबाव और घर के माहौल से तंग आकर वे घर छोड़कर निकल गईं। हालांकि, पुलिस और जांच एजेंसियां इस थ्योरी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि इतनी कम उम्र की बच्चियों का झारखंड से गुजरात तक का लंबा सफर अकेले तय करना लगभग नामुमकिन है। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें किसी संगठित गिरोह द्वारा बेहतर जीवन या काम का लालच देकर मानव तस्करी या श्रम शोषण के लिए ले जाया जा रहा था। वर्तमान में पुलिस मानव तस्करी, बाल विवाह और जबरन श्रम, इन तीनों ही एंगल्स से सघन जांच कर रही है।

नाबालिगों को बालिका गृह में भेजा

आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों नाबालिगों को वर्तमान में सुरक्षित बालिका गृह में भेज दिया है। वहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग की जा रही है ताकि वे बिना किसी डर के अपनी बात कह सकें। उनके विस्तृत बयान दर्ज होने के बाद मामले की कड़ियां जुड़ना तय है। रेलवे सुरक्षा बल ने इस संबंध में झारखंड पुलिस और बच्चियों के परिजनों को आधिकारिक सूचना भेज दी है। परिजनों के आने और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। आरपीएफ का कहना है कि वे उन संदिग्ध युवकों का पता लगा रहे हैं जो ट्रेन में उनके साथ मौजूद थे, ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

नगर निगम के वसूली अभियान: 9 करदाताओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई

जबलपुर, प्रातःकिरण संवाददाता। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा संभागवार एवं वार्डवार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिन करदाताओं के द्वारा बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाया करों की राशि जमा नहीं की जा रही है, उन सभी करदाताओं के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुर्क सम्पत्तियों को अवधि के उपरांत वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नीलाम करने की कार्रवाई भी की जायेगी। संभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम की राजस्व टीम ने संभाग स्तरीय सदस्यों के सहयोग से कछपुरा, अधारताल और रांझी संभागों में प्रभावी कार्यवाही की। जिसमें संभाग क्रमांक 02 कछपुरा अंतर्गत रानीदुर्गवती वार्ड सरदार जगत सिंग बकाया राशि 61 हजार 73 रूपये होने पर संभागीय अधिकारी राजस्व निरक्षक ऋषि कुशरे एवं शत्रुंजय आरख करसंग्रहता विनोद धुर्वे गिरीश कश्यप शैलेष कुमार सेन के द्वारा तालाबंदी की कार्यवाही की गई।

विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में दिखी राज्य की तरक्की की नई इबारत, सकल घरेलू उत्पाद 16,69,750 करोड़ तक पहुंचा, मप्र में प्रति व्यक्ति आय 1,69,000 के पार

11.14 प्रतिशत की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था

कृषि क्षेत्र का दबदबा, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और बुनियादी ढांचे में सुधार

भोपाल, प्रातःकिरण संवाददाता।

मप्र सरकार ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है, जो राज्य के बजट से ठीक पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा देता है। आम आदमी के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में भारी उछाल आया है। यह बढ़कर 1,69,050 रुपए(अग्रिम अनुमान 2025-26) हो गई है। वर्ष 2024-25 में व्यक्ति आय 152615 रूपए थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों ग्रामीण और शहरी घर बने हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत और बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ा है। इसका लक्ष्य औसत जीवन प्रत्याशा को 67 वर्ष से बढ़ाकर 84 वर्ष करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित और गतिशील बनी है। वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन, पारदर्शी शासन और व्यवस्थित नीति क्रियान्वयन ने राज्य को स्थिर वृद्धि की राह पर स्थापित किया है। यह रिपोर्ट विकसित मध्यप्रदेश 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने अपनी विकास योजनाओं में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को प्राथमिकता दी है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे खेती से लेकर उद्योगों तक, हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की आर्थिक संरचना संतुलित, योजनाबद्ध और दीर्घकालिक परिणाम देने वाली है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 16,69,750 करोड़ आंका गया है, जो पिछले वर्ष के 15,02,428 करोड़ की तुलना में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देता है। स्थिर (2011-12) मूल्यों पर यह वृद्धि 8.04 प्रतिशत दर्ज की गई। लगातार बढ़ता उत्पादन, सुदृढ़ निवेश वातावरण और अनुकूल नीतियों ने राज्य की वास्तविक वृद्धि क्षमता को मजबूत किया है।

फाइल फोटो

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में आए बदलावों को दिखाया गया है। भोपाल में हुए महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन और ओडीओपी प्रदर्शनी से महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सरकार मातृ मृत्यु दर को वर्तमान 142 से घटाकर 20 से भी कम करने का लक्ष्य रखती है।

युवाओं के नौकरी के लिए तैयारी करेगी सरकार: युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन और शिक्षा एवं कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 14 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौते हुए हैं। इससे युवाओं को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग मिलेगी। सर्वेक्षण के अनुसार, विभिन्न औद्योगिक आयोजनों से राज्य में 9.29 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। खेल के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाया जा रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी निवेश: छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार क्षमता निर्माण और तकनीकी सुधार पर ध्यान दे रही है। 2025 में लगभग 8,000 एमएसएमई ने प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया। व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-मंडी जैसी योजनाओं का विस्तार हो रहा है। राज्य को निर्यात के क्षेत्र में चैलेंजर श्रेणी में 9वां स्थान मिला है। औद्योगिक क्षेत्रों में 11.71 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर काम चल रहा है।

खेती किसानी और आय में बढ़ोतरी

सर्वेक्षण के अनुसार, खेती-किसानी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें फसलें मुख्य हैं, का राज्य की अर्थव्यवस्था में 43.09 प्रतिशत योगदान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भावांतर भुगतान योजना एक अहम मॉडल है। यह योजना सीधे बैंक खातों के जरिए किसानों को मंडी मूल्य और तय मूल्य के अंतर की भरपाई करती है। पशुपालन क्षेत्र में 10.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो किसानों के लिए कमाई का एक नया जरिया बना है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक मछली उत्पादन को 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना है।

19287 करोड़ का अनुपूरक बजट

मोहन सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट में 19287.32 करोड़ के प्रस्ताव में 1650 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने पिछले दिनों में लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए किया है। बजट में 950 करोड़ रुपए की व्यवस्था नए कर्ज का ब्याज भुगतान करने और 700 करोड़ रुपए पुराने कर्ज के ब्याज राशि भुगतान के लिए तय किए गए हैं। इस तरह वित्त विभाग मे पुराने और नए कर्ज पर ब्याज राशि के भुगतान के लिए 1,650 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 23 फरवरी का दिन तय किया है। अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 8,934.03 करोड़ और पूंजीगत मद में 10353 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए कहा गया है कि बजट में सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विधानसभा में मंगलवार को सदन में पेश किए गए तीसरे अनुपूरक बजट में किए गए प्रावधान की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि में राज्य राशि के रूप में 100 करोड़ रुपए, वन विभाग में वन रोपण निधि पर ब्याज के भुगतान के लिए 161 करोड़ रुपए तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग में निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1,250 करोड़ रुपए तय किए गए हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग को 1,388 करोड़

अनुपूरक बजट में वाणिज्यिक कर विभाग में विभिन्न मदों में ट्रांसफर करने के लिए 1,388 करोड़ रुपए, श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिए 615 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। जिला खनिज फंड के लिए खनिज विभाग में 321 करोड़ तथा खनिज अधिनियम से रक्षित निधि के लिए 140 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग में ऊर्जा कंपनियों को अल्पकालीन ऋण देने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 2,630 करोड़, नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 15वें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 1,569 करोड़, मिलियन शहरों के अनुदान देने के लिए 248 करोड़, तथा विभागीय संस्थाओं को अल्पकालीन लोन देने के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सड़क, पुल के साथ भू अर्जन मुआवजा के लिए भी बजट

अनुपूरक बजट में सड़कों और पुल पुलियों के लिए भी राशि तय की गई है। लोक निर्माण विभाग में भू अर्जन के बाद मुआवजा देने के लिए 1,337 करोड़, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन कार्यों के लिए 225 करोड़, बड़े पुलों के निर्माण के लिए 125 करोड़ की व्यवस्था तय की गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त स्टांप शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान देने के लिए 605 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग में विभिन्न सिंचाई योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 4,700 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

बांधों और नहरों के लिए 300 करोड़ का बजट

जल संसाधन विभाग में बांध व नहर कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़, तकनीकी शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 600 करोड़ और मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के लिए 120 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। एमएसएमई विभाग के अंतर्गत एमएसएमई व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए 213 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विधायक के सवाल पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने सदन में दिया जवाब

पिछले 6 वर्षों में 1 प्रतिशत मजदूरों को भी नहीं मिला 100 दिन का

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन रोजगार का मुद्दा उठा। विधानसभा में विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के उत्तर में मंत्री प्रहलाद पटेल ने जवाब दिया। बताया कि- पिछले 6 वर्षों में 1 प्रतिशत मजदूरों को भी 100 दिन का रोजगार नहीं मिला है। प्रदेश में लगातार मजदूरी की मांग बढ़ रही और सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। वर्ष 2021 में 1 करोड़ 70 लाख 19 हजार 681 मजदूर पंजीकृत है, इनमें से 1 लाख 23 हजार 624 परिवारों को ही पूरे 100 दिवस का रोजगार मिला है।

मनरेगा के पोर्टल पर वर्ष जॉबकार्ड धारी परिवार की संख्या

वित्तीय वर्ष 2021 -2022 में 8665149
- 2022 -2023 में 8989804
- 2023 -2024 में 8812205
- 2024 -2025 में 9520454
- 2025 -2026 में 9815101 है

32,560 परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार मिला

2022 में 1 करोड़ 81 लाख 42 हजार 207 मजदूर पंजीकृत, इनमें से 63 हजार 898 परिवारों को ही 100 दिवस का रोजगार मिला। 2023 में 1 करोड़ 69 लाख 7 हजार 207 मजदूर पंजीकृत इनमें से 40 हजार 588 परिवारों को ही पूरे 100 दिवस का रोजगार मिला। 2024 में 1 करोड़ 70 लाख 42 हजार 207 मजदूर पंजीकृत इनमें से 30 हजार 420 परिवारों को ही 100 दिवस का रोजगार मिला। 2025 में 1 करोड़ 86 लाख 57 हजार 80 मजदूर पंजीकृत इनमें से 32 हजार 560 परिवारों को ही पूरे 100 दिवस का रोजगार मिला।

3.72 प्रतिशत आदिवासी मजदूर रजिस्टर्ड

मनरेगा अंतर्गत वन अधिकार पट्टा धारकों को वर्ष में 150 दिन रोजगार देने का प्रावधान था। मनरेगा अंतर्गत रजिस्टर्ड मजदूरों में 33.72 प्रतिशत आदिवासी मजदूर है। 4 जिलों में मात्र 1 परिवार को ही 150 दिन का रोजगार मिला। आदिवासी जिला झाबुआ में 150 दिन रोजगार का आंकड़ा शून्य रहा। सबसे ज्यादा अलीराजपुर में 112 परिवारों, छिंदवाड़ा में 28, धार में 21, मंडला में 17, दमोह में 16 रहा।

सरकारी स्कूल की बदहाली ने ली मासूम की जान: जर्जर दीवार गिरने से 5वीं कक्षा के छात्र की मौत

कटनी, प्रातःकिरण संवाददाता। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। जहां शासकीय स्कूल की जर्जर दीवार गिरने से 5वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सिर फटने से बहने लगा खून

दरअसल, बमहनगवां स्थित शासकीय स्कूल में मंगलवार को यह दर्दनाक हादसा हुआ था। जहां स्कूल परिसर में अचानक दीवार गिरने से कक्षा 5वीं के छात्र राजकुमार बर्मन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा। हादसे के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। घायल छात्र को तत्काल उपचार के लिए विजयराघवगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। छात्र की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

छत्तीसगढ़

रोमांच और प्रकृति का संगम शिशुपाल पर्वत बना छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब

रायपुर, प्रातःकिरण संवाददाता।

यदि आप प्रकृति, पहाड़ और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो महासमुंद जिले के सरायपाली में स्थित शिशुपाल पर्वत आपके लिए एक शानदार पर्यटन स्थल हो सकता है। आजकल शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। यह स्थान अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। रायपुर से 157 किमी और सरायपाली से लगभग 20 किमी की दूरी पर स्थित यह पर्वत पर्यटकों को प्रकृति के करीब जाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।

रोमांचक ट्रैकिंग का अनुभव

शिशुपाल पर्वत समुद्र तल से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए रोमांचक ट्रैकिंग मार्ग है, जो साहसिक गतिविधियों के प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ट्रैकिंग मार्ग में जंगल, चट्टानें और प्राकृतिक पगडंडियां शामिल हैं। पर्वत के ऊपर एक विशाल मैदान है, जहां से वर्षा ऋतु के दौरान पानी 1100 फीट नीचे गिरता है और भव्य जलप्रपात का निर्माण करता है। यह दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां की हरियाली और शांत वातावरण एक मनमोहक दृश्य का निर्माण करते हैं। पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। यहां पहुंचने वाले सैलानियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया गया।

प्राकृतिक सुंदरता और शांति

शिशुपाल पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहां का वातावरण, हरियाली और झरने पर्यटकों को मानसिक शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। यह स्थान फोटोग्राफी और प्रकृति के अद्भुत दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है।

राजधानी में 2 अंतर्राज्यीय महिला तस्कर गिरफ्तार, 10 किलो गांजा जब्त

रायपुर, प्रातःकिरण संवाददाता।

राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. पश्चिम डिवीजन और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ष्ट्ट) की संयुक्त टीम ने टिकरापारा थाना क्षेत्र में दबिश देकर दो महिला नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी गई है.

भाठागांव के पास पुलिस ने की घेराबंदी

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टिकरापारा के भाठागांव स्थित रावणभाठा मैदान के पास दो महिलाएं गांजा बेचने की फिराक में खड़ी हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राईम) स्मृतिक राजनाला और डीसीपी (पश्चिम) संदीप कुमार पटेल के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने घेराबंदी कर संदेह के आधार पर दो युवतियों को पकड़ा. तलाशी लेने पर उनके बैग से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ.

गिरफ्तार की गई महिलाओं की पहचान खिलेश्वरी वर्मा (18 वर्ष, भनपुरी, रायपुर) और इसरत बानो (21 वर्ष, शहडोल, मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी इसरत बानो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गैंग से जुड़ी हुई है. पुलिस अब इन महिलाओं के 'फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस' खंगाल रही है ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क (End-to-End) का भंडाफोड़ किया जा सके.

2026 में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर पुलिस नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 के शुरुआती दो महीनों में ही अब तक गांजा तस्करी के 14 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 30 आरोपियों को जेल भेजा गया है. पुलिस ने अब तक कुल 141.768 किलोग्राम गांजा, 2 लाख रुपये से अधिक कैश, 2 कार और 6 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 83 लाख रुपये से अधिक है.

विवाद

कोर्ट ने कहा- मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं

ACB-EOW चीफ समेत 3 अफसरों के खिलाफ दायर परिवाद खारिज

रायपुर, प्रातःकिरण संवाददाता।

छत्तीसगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी/ईओडब्ल्यू) के चीफ अमरेश मिश्रा, एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के विरुद्ध दायर परिवाद को खारिज कर दिया है. रायपुर की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा बेक की अदालत ने यह फैसला क्षेत्राधिकार (ज्यूरिडिक्शन) के अभाव में सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर विचारण करने का अधिकार उसके पास नहीं है.

क्या था कोर्ट का मुख्य आधार?

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज बयानों के संबंध में सुनवाई का अधिकार उसी न्यायालय को है, जहा वे बयान साक्ष्य के रूप में पेश किए गए हों. वर्तमान परिवाद में कोर्ट को विचारण की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, इसलिए इसे निरस्त किया गया. अदालत ने यह भी साफ किया कि परिवाद प्रचलनशील न होने के कारण प्रारंभिक साक्ष्य और धारा 94 ब्नह्रस्स् से संबंधित आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जा सकता.

अधिकारियों पर क्या थे आरोप?

परिवादी पक्ष ने आरोप लगाया था कि एसीबी के इन वरिष्ठ अधिकारियों ने कूट रचना (स्नश्रह्द्बठ्ठद्द) कर धारा 164 के तहत कथन दर्ज कराए थे. परिवादी ने इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए अदालत से अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

अदालत में हुई तीखी बहस

परिवाद की स्वीकार्यता को लेकर राज्य सरकार और परिवादी पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई:

बचाव पक्ष (राज्य सरकार): अधिवक्ता रवि शर्मा ने तर्क दिया कि यह मामला कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है. साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए उन्हें वैधानिक संरक्षण प्राप्त है.

परिवादी पक्ष: अधिवक्ता फैजल रिजवी ने दलील दी कि किसी भी अपराध की सूचना देना एक संवैधानिक अधिकार है और अदालत को इस पर विचार करना चाहिए.

अदालत के फैसले के बाद परिवादी पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने स्पष्ट किया है कि वे इस आदेश के खिलाफ रिवीजन पेश करेंगे. उन्होंने कहा कि परिवाद में लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित हैं और उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.

सरकार की सख्ती: ग्रामीण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार एसडीएम करुण डहरिया निलंबित

रायपुर, प्रातःकिरण संवाददाता।

साय सरकार ने आदिवासी किसान की पिटाई से मौत के मामले में सख्ती दिखाते हुए आरोपी एसडीएम करुण डहरिया को निलंबित कर दिया है. मामले में पहले ही एसडीएम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. निलंबन की अवधि में करुण डहरिया मुख्यालय सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है. जानकारी के अनुसार, 15-16 फरवरी की दरमियानी रात को बलरामपुरङ्करामानुजगंज जिले के कुसमी ब्लॉक में हंसपुर गांव में बॉक्साइट के अवैध खनन की जांच करने के लिए कुसमी एसडीएम करुण डहरिया गए हुए थे. आरोप है कि वह प्राइवेट गाड़ी में प्राइवेट लोगों को लेकर पहुंचे हुए थे.

सरना के पास तीन ग्रामीणों को एसडीएम और उनके साथ गए प्राइवेट लोगों ने रोका एवं पूछा कि कहां से आ रहे हो. इसके बाद अवैध उत्खनन का आरोप लगा रॉड, डंडे और लातङ्कघूंसों से पिटाई कर दी. ग्रामीणों को बेहोश होने तक के पीटा गया. मारपीट में घायल ग्रामीणों को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 62 वर्षीय ग्रामीण रामनरेश राम की मौत हो गई. वहीं 60 वर्षीय अजीत उरांव और 20 वर्षीय आकाश अगरिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले में घायल ग्रामीण आकाश अगरिया एवं अजीत उरांव ने बताया कि वे गेहूं के खेत में पानी की सिंचाई करने गए हुए थे. लौटने के दौरान बिना किसी पूछताछ या जांच अवैध खनन का आरोप लगा उनकी पिटाई की गई. घायल ग्रामीणों के बयान के आधार पर कुसमी एसडीएम करुण डहरिया और उनके साथ गए उनके बाहरी साथी विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजिल कुमार यादव व सुदीप यादव के खिलाफ राजपुर थाने में धारा 103, 115 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

मीठे पानी का संकटः कमी नहीं, कुप्रबंधन

डॉ. प्रियंका सौरभ

आज विश्व जिस सबसे गंभीर संसाधन संकट का सामना कर रहा है, उनमें मीठे जल का संकट अत्यंत गहन और बहुआयामी है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97 प्रतिशत खारा है और केवल लगभग 3 प्रतिशत मीठा जल है, जिसमें से भी बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए सुलभ है। इसके बावजूद, आज विश्व की 2-3 अरब आबादी वर्ष के किसी न किसी समय जल संकट से जूझती है। यह संकट केवल जल की भौतिक कमी का नहीं, बल्कि जल की घटती उपलब्धता और समान व सुरक्षित पहुँच-दोनों का संयुक्त संकट है, जो पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को एक साथ प्रभावित करता है। पिछले कुछ दशकों में मीठे जल की उपलब्धता में निरंतर गिरावट देखी गई है। इसका एक प्रमुख कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग की बढ़ती माँग ने जलभृतों पर असहनीय दबाव डाला है। हरित क्रांति के बाद सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल पर बढ़ती निर्भरता ने प्राकृतिक पुनर्भरण की क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों में भूजल स्तर का तीव्र पतन भविष्य की जल सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। कई क्षेत्रों में जलभृत स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता और भी अनिश्चित हो गई है। जल स्रोतों का प्रदूषण मीठे जल संकट का दूसरा बड़ा कारण है। नदियों, झीलों और भूजल में बिना शोधन के छोड़ा गया घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, भारी धातुएँ और कृषि रसायन जल को अनुपयोगी बना रहे हैं। विकासशील देशों में यह समस्या और भी गंभीर है, जहाँ शोधन अवसंरचना का अभाव है। परिणामस्वरूप, कई स्थानों पर जल उपलब्ध होते हुए भी पीने योग्य नहीं रह जाता, जिससे स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है और जल की प्रभावी उपलब्धता घट जाती है। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमनदों का तीव्र पिघलना, वर्षा के पैटर्न में अनिश्चितता और सूखे-बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति देखी जा रही है। हिमालय, आल्प्स और एंडीज जैसे क्षेत्रों में हिमनदों का सिकुड़ना दीर्घकाल में नदियों के प्रवाह को अस्थिर कर रहा है। अल्पकाल में यह बाढ़ का कारण बनता है, जबकि दीर्घकाल में स्थायी जल संकट को जन्म देता है। मानसूनी क्षेत्रों में अनियमित वर्षा ने जल भंडारण और कृषि योजना को भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसके साथ ही, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रों का तेजी से क्षरण हुआ है। शहरीकरण, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग और रियल एस्टेट विकास ने झीलों, तालाबों, बाढ़ मैदानों और दलदलों को नष्ट कर दिया है। ये पारिस्थितिक तंत्र न केवल जल संग्रह और भूजल पुनर्भरण में सहायक होते हैं, बल्कि बाढ़ और सूखे के प्रभावों को भी संतुलित करते हैं। इनके विनाश से जल चक्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। जनसंख्या वृद्धि और उपभोग के बदलते पैटर्न ने भी मीठे जल पर दबाव बढ़ाया है। शहरी जीवनशैली, जल-गहन उद्योग और भोजन की बदलती आदतें-विशेषकर मांसाहारी आहार-ने प्रति व्यक्ति जल पदचिह्न को बढ़ाया है। परिणामस्वरूप, जल की माँग प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से कहीं अधिक हो गई है। जहाँ एक ओर जल की उपलब्धता घट रही है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में जल उपलब्ध होते हुए भी लोगों की पहुँच उससे वंचित है। इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त अवसंरचना है। कई देशों में जल संग्रहण, शोधन और वितरण की व्यवस्थाएँ कमजोर हैं। पुराने पाइपलाइन नेटवर्क, उच्च लीकेज और अपर्याप्त भंडारण के कारण बड़ी मात्रा में जल उपभोक्ताओं तक पहुँचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकासशील देशों में शहरी जल का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा वितरण के दौरान ही नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त, जल गुणवत्ता की समस्या भी पहुँच को सीमित करती है। जहाँ जल भौतिक रूप से उपलब्ध है, वहाँ भी प्रदूषण के कारण वह पीने योग्य नहीं रहता। दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ आज भी कई देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती हैं, जिससे गरीब और हाशियाकृत समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। राजनीतिक और कानूनी बाधाएँ भी जल तक पहुँच को सीमित करती हैं। जल एक साझा संसाधन है, जिसके कारण अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होते हैं। नदियों के बँटवारे, संघीय ढाँचे में अधिकारों के टकराव और अंतरराष्ट्रीय नदी समझौतों की जटिलताओं के कारण कई बार जल-समृद्ध क्षेत्रों में भी समान पहुँच संभव नहीं हो पाती। सामाजिक असमानता इस संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जल संकट का सबसे बड़ा बोझ समाज के कमजोर वर्गों-ग्रामीण गरीबों, शहरी झुग्गी बस्तियों, महिलाओं और बच्चों-पर पड़ता है।

एप्सटीन फाइल्स : यही है शक्तिशाली पुरुष भेड़ियों की हकीकत

इस आदेश के तहत अमेरिकी न्याय विभाग को एपस्टीन से जुड़े सभी अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, कम्युनिकेशन्स और जांच सामग्री सार्वजनिक करने का निर्देश प्राप्त है। हालाँकि यह कानून 2025 में कांग्रेस के दोनों सदनों (हाउस और सीनेट) से लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ था, और राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 नवंबर 2025 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसी कानून के तहत अमेरिकी न्याय विभाग ने समय-समय पर फाइल्स जारी की। परन्तु इन फाइल्स का बड़ा हिस्सा गत 30 जनवरी 2026 को जारी किया गया, जिसमें 3.5 मिलियन से ज्यादा पृष्ठ, 2, 000 से अधिक वीडियो और लगभग 1, 80, 000 फोटो शामिल थे। एप्सटीन फाइल्स के इसी खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया के जाने माने लोगों के चेहरे से नकाब हटने लगी। इन फाइल्स के सार्वजनिक होने के बाद एप्सटीन के यौन अपराधों, ट्रैफिकिंग नेटवर्क और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों की गहराई उजागर हुई। गौरतलब है कि जेफरी एप्सटीन, एक अमीर फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी है। इसने अनेक नाबालिग लड़कियों और युवा महिलाओं का शोषण किया, और इन फाइल्स में राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक हस्तियों के कई नाम सामने आए।

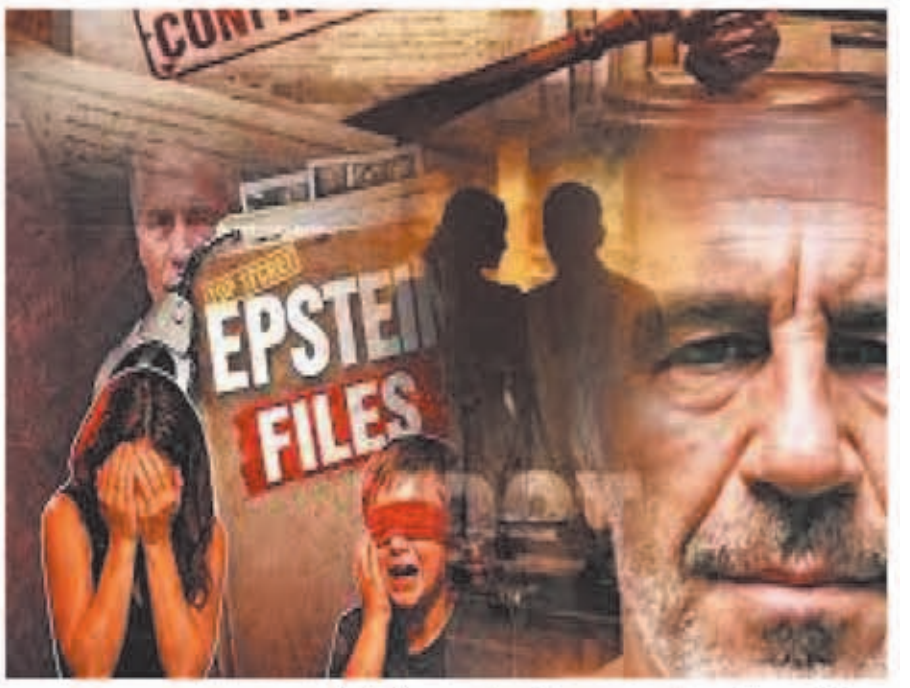

निर्मल रानी

(लेखिका वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

इन दिनों एप्सटीन फाइल्स का भूत अमेरिका से लेकर भारत तक सड़कों पर नाच रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अन्तर्गत और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हस्ताक्षर के बाद ही अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा यह फाइल्स जारी की गई हैं। इस आदेश के तहत अमेरिकी न्याय विभाग को एप्सटीन से जुड़े सभी अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, कम्युनिकेशन्स और जांच सामग्री सार्वजनिक करने का निर्देश प्राप्त है। हालाँकि यह कानून 2025 में कांग्रेस के दोनों सदनों (हाउस और सीनेट) से लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ था, और राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 नवंबर 2025 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसी कानून के तहत अमेरिकी न्याय विभाग ने समय-समय पर फाइल्स जारी की। परन्तु इन फाइल्स का बड़ा हिस्सा गत 30 जनवरी 2026 को जारी किया गया, जिसमें 3.5 मिलियन से ज्यादा पृष्ठ, 2, 000 से अधिक वीडियो और लगभग 1, 80, 000 फोटो शामिल थे। एप्सटीन फाइल्स के इसी खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया के जाने माने लोगों के चेहरे से नकाब हटने लगी। इन फाइल्स के सार्वजनिक होने के बाद एप्सटीन के यौन अपराधों, ट्रैफिकिंग नेटवर्क और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों की गहराई उजागर हुई। गौरतलब है कि जेफरी एप्सटीन, एक अमीर फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी है। इसने अनेक नाबालिग लड़कियों और युवा महिलाओं का शोषण किया, और इन फाइल्स में राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक हस्तियों के कई नाम सामने आए। इन खुलासों के बाद कई प्रमुख व्यक्तियों का भविष्य व जीवन प्रभावित हुआ। कई लोगों को इस्तीफे देने पड़े तो कई के विरुद्ध जांच बिठाई गयी। आपना नाम आने पर कई लोग शर्मिंदगी से जहाँ मुंह छुपाते घूम रहे हैं यहाँ तक कि इस नेटवर्क में नाम आने के बाद कई लोग भूमिगत हो चुके हैं और मीडिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वहीं भारत में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जैसे ह्यविशिष्ट ह्य भी हैं जो एप्सटीन फाइल्स के खुलासे के अनुसार तो जेफरी एपस्टीन से 14 बार मिले परन्तु वे स्वयं एपस्टीन से 8 सालों में केवल 3-4 बार की मुलाकात को ही स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद वह इस सवाल से बच नहीं पा रहे कि 13-14 बार या 3-4 बार नहीं बल्कि यदि एक सजायाफ़्ता बदनाम यौन अपराधी से हरदीप पुरी एक बार भी मिले तो उस मुलाकात की वजह क्या थी? जो व्यक्ति खुद स्वीकार कर चुका है कि वह कम उम्र की बच्चियों से सैक्स करने का आदी था ऐसे ह्यभेड़िया मानसिकता ह्य वाले व्यक्ति से मुलाकात क्यों की गयी? किसके कहने पर या किसके लिये की गयी? बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि अभी दुनिया के और भी अनेकानेक ह्यसफेदपोश भेड़ियोंह्ह के नाम सामने आएंगे और इस्तीफों की भी झड़ी लग सकती है। दुनिया में आये दिन घटित होने वाली तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो पितृ सत्ता या पुरुष प्रधान समाज का बार बार एहसास कराती हैं। परन्तु इस घटना में तो जेफरी एप्सटीन पर 2019 में न्यूयॉर्क में संघीय अदालत ने उसपर सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के आरोप लगाए, जिसमें दर्जनों नाबालिग लड़कियों यहाँ तक कि 14 साल से भी कम उम्र की कुछ बच्चियों का यौन शोषण शामिल था। यह उसकी स्वीकारोक्ति थी कि उसने नाबालिग लड़कियों से यौन संबंध बनाये व अवैध काम किए। इसलिये इस विश्वव्यापी नेटवर्क से पर्दा उठने के बाद अब यह सवाल भी उठने लगा है कि दुनिया के धनाढ्य और शक्तिशाली लोगों की नजर में महिलाओं, खासकर छोटी बच्चियों का क्या स्थान है? महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का ढोंग रचने वाला सफेद पोश पुरुष प्रधान समाज जो कभी महिलाओं को आधी आबादी कहकर खुश करता है तो कभी बच्चियों को ह्यकंजक ह्य व देवी के रूप में पूजता भी है उन्हीं बच्चियों को अपने पैसे व सत्ता के बल पर अपनी हवस का निशाना बनाने वाले लोग नाबालिग लड़कियों और युवा महिलाओं का शारीरिक शोषण भी करते हैं? निश्चित रूप से एपस्टीन फाइल्स पितृसत्ता की एक गहरी तस्वीर पेश करती हैं, जहां धनाढ्य पुरुष विश्वव्यापी नेटवर्क बनाते हैं और एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं और महिलाओं को परिधि पर रखते हैं। वास्तव में ह्यआधी आबादी ह्य को प्रायः सहयोगी, या यौन सुख प्रदान करने वाली के रूप में ही देखा जाता है न कि समान भागीदार के रूप में। खासकर गरीब परिवारों की छोटी बच्चियों को तो कमजोर और आसानी से नियंत्रित करने योग्य माना जाता था। एप्सटीन के नेटवर्क में शामिल कुछ पुरुषों ने कथित तौर पर इन लड़कियों को उपहार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे व्यापारिक या राजनीतिक लाभ मिलते थे। यह दर्शाता है कि शक्तिशाली लोगों की नजर में, महिलाएं और लड़कियां अक्सर सत्ता और प्रभाव बनाए रखने का साधन बन जाती है न कि कोई सम्मानजनक मानव। महिलाओं को केवल प्रजनन उपकरण के रूप में देखना भी पितृसत्ता की ही एक गहरी साजिश है। इसलिये एप्सटीन फाइल्स से प्राप्त हो रहे ब्यौरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एप्सटीन जैसे मामलों में जहाँ कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा छोटी मासूम बच्चियों को मात्र अपनी यौन संतुष्टि के लिये या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौदेबाजी के साधन के रूप में अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को ब्लैकमेल करने की गरज से इस्तेमाल किया गया। यह एक ऐसी व्यवस्थित समस्या है जहां धन, सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहां महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालांकि, एफबीआई की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियां बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती है

एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन - वैश्विक भविष्य की तैयारी और पटना में राजनीतिक भविष्य की रेखा

अपने भीतर केवल वर्तमान की प्रतिक्रिया नहीं समेटे होती, बल्कि वह भविष्य की नींव गढ़ने का प्रयास भी होती है। मनुष्य की चेतना, समाज की संरचना और राष्ट्र की दिशा, इन गतिविधियों के माध्यम से निरंतर आकार लेती रहती है। इतिहास साक्षी है कि जिन क्षणों को ह्यआजह्ह कहकर देखा है, वह आगे चलकर युग-निर्माण के पत्थर बना है। कभी किसी शिखर सम्मेलन में लिया गया निर्णय, तो कभी किसी राजनीतिक कार्यालय में खींची गई रणनीतिक रेखा। दोनों ने ही दशकों तक समाज को प्रभावित किया है। एक ओर नई दिल्ली में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर विश्व स्तर का मंथन, और दूसरी ओर पटना में राजनीतिक भविष्य की ऐसी बुनियाद, जिसका प्रभाव केवल वर्तमान सत्ता-संतुलन तक सीमित नहीं रहने वाला है। यह संयोग नहीं, बल्कि समय की भाषा है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित पाँच दिवसीय एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन केवल एक तकनीकी आयोजन नहीं है। यह मानव सभ्यता के अगले चरण को समझने और दिशा देने का वैश्विक प्रयास है। दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्ष, नीति-निमार्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग जगत के दिग्गज और शोधकर्ता इस मंच पर एकत्र हुए हैं।

जितेन्द्र कुमार सिन्हा

लेखक

हर संगठित गतिविधि, चाहे वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी संस्थान का शुभारंभ हो, वैश्विक सम्मेलन हो, राजनीतिक बैठक हो या जन-प्रदर्शन। अपने भीतर केवल वर्तमान की प्रतिक्रिया नहीं समेटे होती, बल्कि वह भविष्य की नींव गढ़ने का प्रयास भी होती है। मनुष्य की चेतना, समाज की संरचना और राष्ट्र की दिशा, इन गतिविधियों के माध्यम से निरंतर आकार लेती रहती है। इतिहास साक्षी है कि जिन क्षणों को ह्यआजह्ह कहकर देखा है, वह आगे चलकर युग-निर्माण के पत्थर बना है। कभी किसी शिखर सम्मेलन में लिया गया निर्णय, तो कभी किसी राजनीतिक कार्यालय में खींची गई रणनीतिक रेखा। दोनों ने ही दशकों तक समाज को प्रभावित किया है। एक ओर नई दिल्ली में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर विश्व स्तर का मंथन, और दूसरी ओर पटना में राजनीतिक भविष्य की ऐसी बुनियाद, जिसका प्रभाव केवल वर्तमान सत्ता-संतुलन तक सीमित नहीं रहने वाला है। यह संयोग नहीं, बल्कि समय की भाषा है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित पाँच दिवसीय एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन केवल एक तकनीकी आयोजन नहीं है। यह मानव सभ्यता के अगले चरण को समझने और दिशा देने का वैश्विक प्रयास है। दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्ष, नीति-निमार्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग जगत के दिग्गज और शोधकर्ता इस मंच पर एकत्र हुए हैं। यह उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल प्रयोगशालाओं या कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक सीमित विषय नहीं रही, बल्कि यह शासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों तक को प्रभावित करने वाली शक्ति बन चुकी है। शुरूआत में एआई को मानव श्रम की सहायक तकनीक माना गया था। लेकिन आज यह निर्णय-निर्माण, निगरानी, पूर्वानुमान और रणनीति निर्माण का प्रमुख उपकरण बन चुकी है। स्वास्थ्य में एआई बीमारियों की पहचान बदल रहा है। शिक्षा में यह सीखने के तरीकों को वैयक्तिक बना रहा है। रक्षा और सुरक्षा में यह युद्ध की प्रकृति को ही पुनर्परिभाषित कर रहा है। इसी कारण यह शिखर सम्मेलन केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि नैतिकता, नियमन और मानव नियंत्रण पर भी केंद्रित है। आज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एआई एक नया शक्ति-संतुलन बना रही है। जिन देशों के पास उन्नत डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता और एल्गोरिदमिक श्रेष्ठता है, वे वैश्विक मंच पर बढ़त बना रहे हैं। इस सम्मेलन में यह चर्चा विशेष महत्व रखती है कि क्या एआई को नियंत्रित किया जाना चाहिए?, क्या यह नियंत्रण वैश्विक होगा या राष्ट्रीय? और क्या तकनीकी महाशक्तियाँ इसे हथियार की तरह प्रयोग करेंगी? नई दिल्ली में हो रहा यह मंथन आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। भारत लंबे समय तक तकनीक का उपभोक्ता रहा है, लेकिन अब यह मानसिकता बदल रही है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बाद एआई भारत की अगली छलांग है। ह्यइस सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट है कि ह्यहम तकनीक अपनाएंगे भी और उसे मानवता के हित में ढालेंगे भी ह्ह्य यह रुख भारत को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व की भूमिका में भी स्थापित करने की कोशिश है। जहाँ नई दिल्ली में भविष्य की तकनीकी संरचना पर चर्चा हो रही है, तो वहीं पटना में भविष्य की राजनीतिक संरचना पर। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का आवास 1 अणे मार्ग केवल एक सरकारी निवास नहीं है, बल्कि सत्ता-संतुलन का केंद्र रहा है। यहाँ खींची गई लकीरें अक्सर दिल्ली तक असर दिखाती हैं। ३नीतीश कुमार को केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना उनके राजनीतिक कद को कम करके आंकना होगा। वे गठबंधन राजनीति के कुशल खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने समय-समय पर अपनी दिशा बदली, लेकिन प्रासंगिकता बनाए रखी। उनकी राजनीति में भविष्य की गणना हमेशा वर्तमान से बड़ी रही है। आज एक बार फिर पटना से ऐसी राजनीतिक रेखा खिंचने की चर्चा है, जो केवल बीते चुनावी परिणामों की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले राष्ट्रीय परिदृश्य की तैयारी मानी जा रही है। बिहार केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला रहा है। सामाजिक न्याय की राजनीति। जाति आधारित समीकरण और गठबंधन सरकारों का प्रयोग, इन सबका राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नीतीश कुमार की हर राजनीतिक चाल को इसलिए गंभीरता से देखा जाता है, क्योंकि वह अक्सर ट्रेंडसेटर साबित होती है। पहली दृष्टि में नई दिल्ली का एआई सम्मेलन और पटना की राजनीतिक बैठक दो अलग-अलग घटनाएँ लग सकती हैं। लेकिन गहराई से देखें तो दोनों का लक्ष्य एक ही है ह्यभविष्य पर नियंत्रणह्ह। तकनीक भविष्य को संचालित करना चाहती है। राजनीति भविष्य को निर्देशित करना चाहती है। जब दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे से टकराती या मिलती हैं, तब इतिहास बनता है। इन वैश्विक और राजनीतिक हलचलों के बीच आम नागरिक का प्रश्न स्वाभाविक है कि ह्यइस सबका हमारे जीवन से क्या संबंध?ह्ह उत्तर सरल नहीं है, लेकिन स्पष्ट है। एआई आपके रोजगार को बदलेगी। राजनीतिक निर्णय अधिकारों और अवसरों को। इसलिए यह केवल नेताओं और विशेषज्ञों का नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का भविष्य तय कर रहा है। भारत जैसे देश में कोई भी परिवर्तन केवल तकनीकी या राजनीतिक नहीं रहता है, वह सांस्कृतिक भी बन जाता है। एआई पर धार्मिक दृष्टिकोण, राजनीति में नैतिकता का प्रश्न और परंपरा बनाम आधुनिकता की बहस।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नवाचार से राष्ट्र निर्माण तक

सुनील कुमार महला

आज का समय तकनीक का समय है, या यूँ कहें कि हम तकनीक के युग में सांस ले रहे हैं। यह तकनीक ही है, जो मनुष्य के जीवन को अधिक सुविधाजनक बना रही है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी सोच, कार्यशैली और आदतें भी आज बदल रही है। कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस परिवर्तन का सबसे प्रमुख उदाहरण बनकर उभरी है। तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दुनिया भर में आधुनिक तकनीकों के विकास और नवाचार पर विशेष जोर बढ़ा है। आज दुनिया के विभिन्न देश अपनी नीतियों में नई-नई तकनीकों व नवाचारों को शामिल कर अपने देश की विभिन्न पारंपरिक कार्यप्रणालियों को लगातार बदल रहे हैं। विशेष रूप से एआई ने वैश्विक स्तर पर कार्य प्रणाली और मानव भूमिका को गहराई से प्रभावित किया है, इसलिए आज इसे विकास के लिए अनिवार्य और बहुत ही अहम् माना जा रहा है। इसी संदर्भ में, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण एआई शिखर सम्मेलन (इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026; 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक) आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एआई की संभावनाओं, इसकी चुनौतियों, रोजगार पर इसका प्रभाव और आम जीवन में इसके उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। कहना गलत नहीं होगा कि आज एआई का दायरा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कारोबार और रक्षा जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका है, जिससे नए अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि रोजगार पर प्रभाव, जोखिम, डेटा सुरक्षा और पर्यावरणीय असर जैसी चिंताएँ भी इसके कारण सामने आई हैं। विशेष रूप से डेटा केंद्रों में ऊर्जा और पानी की बढ़ती खपत को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। इसलिए एआई आधारित विकास को सफल बनाने के लिए इसके लाभों के साथ-साथ संभावित खतरों के समाधान पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह पाँच दिवसीय कार्यक्रम ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन माना जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं और एआई नीति तथा नवाचार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि यह समिट भारत मंडपम सहित नई दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर आयोजित हो रही है तथा इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है, साथ ही शीर्ष तकनीकी कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ), शोधकर्ता, नीति-निमार्ता और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि 800 से अधिक प्रदर्शक, स्टार्टअप, शोध संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहे हैं। 16-20 फरवरी तक आयोजित यह एआई शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआइ) के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जबकि उससे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार भारत का स्कोर 21.59 है, जबकि अमेरिका का 78.6 और चीन का 36.95 है। इस सूचकांक में भारत कई विकसित देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस से आगे है।

गांव तक क्यों नहीं पहुंचती है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था?

मोना खलझूनिया

हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को वैसे तो कई बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत है। लेकिन सबसे अधिक जिस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है स्वास्थ्य का मुद्दा। जो आज भी इससे वंचित रह जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन डॉक्टरों का बड़ा हिस्सा शहरों तक ही केंद्रित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भारी कमी है। डॉक्टरों, नर्सों और लैब-टेक्नीशियनों के हजारों पद खाली पड़े हैं। कई जगह अस्पताल भवन बने हुए हैं, पर नियमित डॉक्टर नहीं हैं, उपकरण अधूरे हैं और रात की आपात सेवा लगभग नहीं के बराबर है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास निजी अस्पताल या शहर तक पहुँचने के साधन नहीं होते हैं। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी राज्यों के दूर दराज गांवों की स्थिति इससे भी अधिक कठिन है, क्योंकि यहाँ अस्पताल तक पहुँचना ही अपने-आप में एक चुनौती है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश गांवों से नजदीकी बड़े अस्पताल की दूरी कम से कम 20 से 50 किमी तक होना आम बात है। जहां पहुँचने के लिए न केवल जर्जर सड़क बल्कि मौसम और अक्सर परिवहन की कमी के कारण समय पर इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाता है। वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ और अस्पताल ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई। राज्य स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणाएँ होती रहती हैं, पर पहाड़ के छोटे गांवों तक इनका असर बहुत धीमी गति से पहुंचता है। इसका एक उदाहरण उत्तराखंड के बागेश्वर जिला स्थित गरुड़ ब्लॉक का जखेड़ा गांव है। जहां संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुविधाओं के अभाव में चल रहा है। यह अस्पताल केवल जखेड़ा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव जैसे गनीगांव, सैलानी, और लमचूला के लोगों का भी सहारा है। जखेड़ा की आबादी लगभग 1500, गनीगांव की 1600, सैलानी की 1200 और लमचूला की लगभग 1500 है। यानी करीब 5, 800 लोग इस एक प्राथमिक अस्पताल पर निर्भर हैं। इतनी आबादी होने के बावजूद अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहां के निवासियों के जीवन को खतरे में डालता है। इस संबंध में जखेड़ा गांव के 55 वर्षीय रघुवीर सिंह परिहार बताते हैं, अस्पताल तो और भी हैं, लेकिन जरूरत पूरी नहीं होती। डॉक्टर भी केवल एक है, साथ में एक वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट हैं। एक आयुर्वेदिक अस्पताल करीब 30 साल पहले (1991-92) बना था, लेकिन सुविधा कोई खास नहीं है। आशा कार्यकर्ता कांता परिहार कहती हैं, यहाँ सिर्फ बुखार या जुकाम जैसी मामूली बीमारियों से जुड़ी दवाइयाँ ही मिलती हैं और सामान्य जाँच तक ही इलाज सीमित है। वह बताती हैं कि अस्पताल में स्टाफ सुबह 10 बजे आते हैं और दोपहर 2 बजे तक चले जाते हैं। ऐसे में रात में जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है। एंबुलेंस तक समय पर नहीं पहुंच पाती है। मरीज को निजी परिवहन की व्यवस्था कर 33 किमी दूर गरुड़ या बैजनाथ के सदर अस्पताल ले जाना पड़ता है पहुँचते-पहुँचते कई बार मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। स्वास्थ्य सेवा का एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में अक्सर कोई नहीं बोलता है। सैलानी की 20 वर्षीय प्रीति बताती है, माहवारी के दौरान पेट दर्द जैसी समस्या होने पर अस्पताल में खुलकर बात नहीं कर पाती, क्योंकि डॉक्टर पुरुष हैं। अगर महिला डॉक्टर होती तो हम खुलकर अपनी बात कह पाते। स्थानीय पोस्ट ऑफिस कर्मचारी उम्मेद सिंह कहते हैं, यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से अस्पताल तो है, लेकिन सुविधाएँ नहीं हैं। एएनएम का पद है, पर वे अक्सर मौजूद नहीं रहतीं और रात में डॉक्टर भी नहीं होते हैं। ह्ह 66 वर्षीय गोविंद परिहार की चिंता दवाइयों को लेकर है, कहते हैं कि दवाइयाँ कम हैं और कई बार पुरानी हो जाती हैं। प्राथमिक उपचार भी पूरा नहीं मिल पाता। गंभीर मरीज को तुरंत रेफर कर दिया जाता है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि वह रास्ते में बच पाएगा या नहीं। लमचूला की रहने वाली माया कहती है, अगर अस्पताल में सुविधाएं होती तो हमें दूर नहीं जाना पड़ता। खासकर महिलाओं के लिए महिला डॉक्टर होती तो बात करना आसान होता और जीवन थोड़ा आसान लगने लगता। ह्ह गनीगांव के 33 वर्षीय धीरज बिष्ट बच्चों और गर्भवती महिलाओं की कठिनाई बताते हुए कहते हैं, यहाँ मेडिकल स्टोर भी नहीं है और अस्पताल में जरूरी दवाइयां नहीं मिलती हैं, यहां तक कि एंबुलेंस जैसी जरूरी सुविधा की व्यवस्था तक नहीं है। रात में स्टाफ की जरूरत है, जो नहीं है। कई बार बच्चों को गंभीर बीमारी में अस्पताल पहुँचाने तक जान चली जाती है।

संक्षिप्त समाचार

अपात्र ने लिया सरकारी राशन का लाभ, कार्रवाई शेष

सतना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को चिन्हित किए जाने के बाद उन पर कार्रवाई किया जाना शेष है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले में 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले 3886 अपात्र हितग्राहियों का सरकारी राशन का लाभ लेना पाया गया है। इनमें से अब तक 1577 हितग्राहियों पर कार्रवाई कर नाम हटाए गए हैं, जबकि 2309 मामलों में कार्रवाई लंबित है। इसी प्रकार 25 लाख रुपए से अधिक कारोबार करने वाले 32 हितग्राहियों में से केवल 18 पर कार्रवाई हो सकी है और 14 मामलों में अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कंपनी संचालक के रूप में दर्ज 463 हितग्राहियों में भी केवल 108 के नाम हटाए गए हैं, जबकि 355 पर कार्रवाई शेष है।आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि सतना के सभी ब्लॉकों में अपात्रों के नाम हटाने की कार्रवाई चल रही है। उपार्जन कार्य के कारण थोड़ी देरी हुई, प्रयास है कि जल्द से जल्द अपात्रों पर कार्रवाई की जाएगी।

अधजले शव का मेडिकल कॉलेज मे पीएम

सतना। मैहर जिले के ताला क्षेत्र अंतर्गत जंगल में गत दिवस एक अधजली लाश मिली थी। इसकी पहचान कर ली गई है। यह लाश मूक-बधिर महिला सोमवती गुप्ता की बताई जा रही है। हालांकि सूत्रों की मानें तो पुष्टि के लिए पुलिस डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी में है। ताला कस्बे के बाजार टोला से लगभग 3 किलोमीटर दूर सुआलोटा जंगल में मिले 56 वर्षीय मूकबधिर महिला सोमवती गुप्ता के अधजले शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज रीवा में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की निगरानी में डॉक्टर टीम से कराया गया है। इससे पूर्व क्षत-विक्षत शव को सिविल हॉस्पिटल अमरपाटन ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने देखते ही मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। गौरतलब है कि महिला 14 फरवरी को लापता हो गई थीं, लाश तीसरे दिन सुआलोटा जंगल से अधजली हालत में बरामद की गई। घटना स्थल पर पत्थर और जमीन पर खून के छींटे भी मिले, जली खोपड़ी में गंभीर चोट के निशान पाए गए। जिससे पुलिस अब इसे हत्या मानकर अपनी कार्रवाई कर रही है।

पत्नी की हत्या के प्रयास का आरोपी अपने को बता रहा निर्दोष

सतना। पत्नी की हत्या करने की कोशिश करने के आरोप से घिरे पति ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अपने बचाव में अब पत्नी और उसके मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला माननीय न्यायालय में है, लिहाजा अब यह तो वहीं तय होगा कि पति पत्नी में दोषी कौन है, कोई दोषी है भी या नहीं। यहां बता दें कि पूर्णिमा पिता राजकुमार पाण्डेय निवासी झिंगोदर ने पति अनुराग त्रिपाठी पिता सोहनलाल त्रिपाठी के खिलाफ सिविल लाइंस थाना में शिकायत की थी कि उनके पति ने फिनायल की गोली को पानी में मिलाकर जबरिया उस पानी को पिलाकर हत्या का प्रयास किया। इस शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अनुराग को गिरफ्तार किया था। 1 जनवरी से 29 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे अनुराग का कहना है कि उन्हें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वे अपनी ओर से न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर साबित करने का प्रयत्न करेंगे कि उनकी पत्नी और उनके परिजनों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से झूठा अपराध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि स्वयं को निर्दोष एवं सही साबित करने के लिए वो सभी आवश्यक तथ्य प्रस्तुत करेंगे।

आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में ऐतिहासिक कदम :राज्यमंत्री

प्रातः किरण, सतना।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने विधानसभा में प्रस्तुत मध्यप्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के वार्षिक बजट का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति का आधार बताया है। राज्यमंत्री ने कहा कि लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये का यह बजट प्रदेश के विकास को तीव्र गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, तथा उद्योग और आधारभूत अधोसंरचना को केंद्र में रखा गया है। यह जन-केंद्रित विकास, समावेशन और सशक्तिकरण को स्थापित करने वाला बजट है। बजट का मुख्य आकर्षण महिला कल्याण, शिक्षा, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाएं हैं। राज्य की आय में एसजीएसटी एवं वैट का सर्वाधिक योगदान है, जो राज्य की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का संकेत है। यह बजट विकास, सुशासन एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधोसंरचना विस्तार और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता के माध्यम से राज्य को प्रगतिशील और समृद्ध बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला सिद्ध होगा बजट : सांसद

सांसद गणेश सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी–को केंद्र में रखकर प्रदेश के समावेशी, संतुलित एवं दीर्घकालिक विकास का सशक्त रोडमैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट कृषि, अधोसंरचना, औद्योगीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला सिद्ध होगा।

समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का मिलेगा अवसरः भगवती

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पंडित भगवती प्रसाद पांडेय ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मार्ग दर्शन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जो प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सरकार ने गरीबों के कल्याण, युवाओं के रोजगार सृजन, किसानों की आय वृद्धि तथा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए ठोस और प्रभावी प्रावधान किए हैं।

संतुलित, समावेशी एवं विकासोन्मुख बजटः श्यामू

भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी श्याम लाल गुप्ता श्यामू ने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक विकसित प्रदेश के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला संतुलित, समावेशी एवं विकासोन्मुख दस्तावेज है। सरकार ने दीर्घकालिक विकास की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

कर्ज के पहाड़ वाला बजटः विक्रांत

बजट के संबंध में कांग्रेस नेता विक्रांत त्रिपाठी विक्की ने कहा है कि राज्य पर कर्ज़ का बोझ लगातार बढ़ रहा है। हर साल नए ऋण लेकर सरकार खर्च चला रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर आर्थिक भार बढ़ेगा। बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज़ के ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। यदि यही पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में लगाया जाता तो जनता को सीधा लाभ मिलता। बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो की गई, लेकिन उनके लिए ठोस वित्तीय प्रबंधन और स्थायी आय के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं।

आदिवासियों की बेशकीमती जमीन हड़पने का मामला

फर्जीवाड़े की जमीन का अल्ट्राटेक सीमेन्ट उद्योग से ढाई करोड़ में सौदा

प्रातः किरण, सतना।

मैहर जिले के ग्राम भदनपुर के गरीब आदिवासियों की बेशकीमती भूमि उनको धोखे में रखकर बिचौलियों द्वारा विक्रय करा दिये जाने संबंधी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के सत्यापन में पाया गया कि रामसिंह गोड़ निवासी ग्राम भदनपुर दक्षिण पट्टी तहसील एवं जिला मैहर के आधिपत्य की लगभग 3.500 हेक्टेयर कृषि भूमि जो वर्ष 10-11 तक राजस्व अभिलेख खसरा में उसके नाम दर्ज थी, यह जमीनें अशोक सिंह तत्कालीन हल्का पटवारी भदनपुर जिला मैहर एवं अन्य बिचौलियों द्वारा वर्ष 2012-13 के राजस्व खसरे में उसके पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम बिना उसकी जानकारी तथा बिना किसी सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश के वारिसाना दर्ज कराकर फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कराई गई, जबकि रामसिंह गोड़ जीवित थे तथा उनके 2 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थीं।

प्रतीकात्मक फोटो

इस तरह हुई धोखाधड़ी

राजेन्द्र सिंह को जमीन के नाम पर बैंक से ऋण दिलाने के नाम पर उसको धोखे में रखकर शोभा कोल निवासी ग्राम सलैया जिला मैहर एवं बैजनाथ कोल निवासी ग्राम खरौंधी जिला मैहर के नाम रजिस्ट्री / राजस्व अभिलेख खसरा में दर्ज करवा दी गई। उपरोक्त भूमियां अल्ट्राटेक सीमेन्ट सरला नगर मैहर को लगभग 2.50 करोड़ रूपये में विक्रय करवा दिया गया, जिसकी जानकारी राजेन्द्र सिंह को नहीं हो पाई और न ही उसे उपरोक्त भूमियों के बदले कोई धनराशि ही प्राप्त हुई।

इन पर हुई कार्रवाई

ईओडब्ल्यू द्वारा जानकारी दी गई है कि उक्त प्रकरण में आरोपीगण अशोक सिंह तत्कालीन पटवारी भदनपुर दक्षिण पट्टी तहसील मैहर, जिला मैहर, शोभा प्रसाद कोल पिता बन्नेलाल कोल निवासी सलैया पोस्ट अजमाइन थाना बदेरा तहसील मैहर जिला मैहर, बैजनाथ कोल पिता बाबूलाल कोल निवासी खरौंधी पोस्ट जूरा थाना नादन देहात जिला मैहर, दीपक लालवानी पिता उत्तमचंद्र लालवानी निवासी मैहर, गोपाली उर्फ गोपाल आसवानी निवासी मैहर, अज्जू उर्फ अजय पिता होलाराम सावलानी निवासी मैहर, कमला उर्फ प्रदीप कुमार सेन निवासी ग्राम बरा जिला मैहर, रामप्रकाश जायसवाल पिता बेड़िया प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम भदनपुर उत्तरपट्टी, अन्य संबंधित राजस्व अधिकारी एवं अन्य संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध धारा 120-बी, 420,467,468,471 भादवि एवं धारा 7, 13 (1) ए 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) का अपराध घटित किया जाना प्रमाणित पाये जाने से उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।

लाखों का गांजा और कफ सीरप पकड़ी गई

मैहर पुलिस ने दर्ज किये 41 प्रकरण

प्रातः किरण, सतना

नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं के रोकथाम की दिशा में मैहर पुलिस ने जनवरी से दिसम्बर 2025 तक 5 लाख 70 हजार कीमत का गांजा 51 किलो और 6 लाख 44 हजार मूल्य की 3448 शीशियां नशीली कफ सिरप की जप्त कर 58 आरोपियों के विरुद्ध 41 प्रकरण दर्ज कर एनडीपीएस की कार्यवाही की है। इस आशय की जानकारी बुधवार को कलेक्टर एवं

जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड की अध्यक्षता में संपन्न नाकार्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक में दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मैहर अवधेश प्रताप सिंह, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम एसपी मिश्रा, डॉ. आरती सिंह, आरटीओ संजय श्रीवास्तव, डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, सीएमएचओ डॉ. मनोज शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर रानी बाटड ने कहा कि मादक पदार्थों के उपयोग पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारी अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करें। लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराकर जन जागरूकता के लगातार कार्यक्रम करें। संकल्प से सिद्धी अभियान के तहत लग रहे कैम्पों में भी नशा मुक्ति का संदेश देने बैनर पोस्टर लगाये। कृषि, उद्यानिकी विभाग देखें कि फसलों के बीच में कहीं भी नशीले पदार्थों की खेती नहीं की जाये। पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं के रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने समिति में शामिल अधिकारियों से कहा कि मैदानी स्तर के कर्मचारियों को साथ लेकर सूचना तंत्र विकसित करें ताकि सूचनाओं के इनपुट के आधार पर कार्यवाही तत्काल हो सके। शिक्षा, उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय विभाग सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता के कार्यक्रम नियमित रूप से करें। स्कूलों, कालेज में एक शिक्षक को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर प्रति सप्ताह किशोर बच्चों का एक सेशन जरूर कराये। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और औषधि निरीक्षक को मेडीकल स्टोर एवं अन्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिये और कहा कि नींद और दर्द निवारक दवाओं का स्टाक विक्रय इन्ट्री जरूर चेक करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि नशा मुक्ति के लिए हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कौंसलर और आरएसबीके के मेडीकल आफीसर स्कूलों, कालेज में जाकर सेशन करते हैं। गांवों में आरोग्य दूत भी बनाये गये हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण उपलब्ध करायें।

अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश

प्रातः किरण, सतना।

रीवा संभाग अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर एवं मऊगंज जिलों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की अत्यंत धीमी प्रगति को लेकर कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद ने जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। समीक्षा बैठक में पाया गया कि संबंधित विभाग समयबद्ध रूप से प्रकरण तैयार कर बैंकों को प्रेषित नहीं कर रहे हैं, वहीं प्रेषित प्रकरणों की स्वीकृति सुनिश्चित कराने हेतु भी प्रभावी प्रयास नहीं किए जा रहे। कमिश्नर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है। इसके बावजूद निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है।

कमिश्नर ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रकरणों की तैयारी, बैंक प्रेषण एवं स्वीकृति प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल समीक्षा एवं सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। चेतावनी दी गई है कि जिन विभागों के लक्ष्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं, वहाँ संबंधित जिला अधिकारियों के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाएगी।

ओलम्पियाड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चे सम्मानित

प्रातः किरण, सतना।

राज्य शिक्षा केन्द्र के तत्वाधान में कक्षा 2 से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों की 16 जनवरी को हुई जिला स्तरीय ओलम्पियाड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र प्रतियोगियों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मैहर में समारोहपूर्वक सम्मानित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, कलेक्टर रानी बाटड, उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंह और सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह ने मैहर जिले के विभिन्न 11 विषयों की ओलम्पियाड जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले 21 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, पुरूस्कार किट एवं कप प्रदान कर सम्मानित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल ने बच्चों के साथ ही उनके शिक्षक और अभिभावकों को बधाई दी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंह ने कहा कि जैतवारा के उमेश खेमका और नीरा खेमका का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान प्रेरणा का माध्यम बनेगा। डीपीसी विष्णु त्रिपाठी ने बताया कि ओलम्पियाड परीक्षा के लिए जिले में बच्चों ने आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। जिले के 65 जन शिक्षा केन्द्र पर हुई ओलम्पियाड परीक्षा में कक्षा 2 से कक्षा 8 तक के शामिल हुए। जिला स्तर पर ओलम्पियाड परीक्षा में 16-17 जनवरी 2026 को 64 बच्चे शामिल हुए। जिनमें जिला स्तर पर अलग-अलग विषयों में 21 बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया। इनमें मैहर जिले के मैहर विकासखण्ड के एक और रामनगर विकासखण्ड के 20 बच्चों ने प्रथम स्थान बनाया। छात्र शिवांशु कुशवाहा और कुमारी शांति प्रजापति ने दो-दो विषयों में प्रथम स्थान हासिल किया। जिले में ओलम्पियाड परीक्षा में 21 में से 20 बच्चे रामनगर विकासखण्ड के होने के फलस्वरूप एसडीएम रामनगर एसपी मिश्रा और बीआरसी सीपी शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित हुए बच्चों में मैहर के शिवांश लोनिया तथा रामनगर विकासखण्ड के रक्षा बुनकर, रागनी कोल, राखी चौरसिया, अक्षिता सिंह, अवनीश सेन, श्रुति पटेल, सत्यव्रत पटेल, दीपक बहेलिया, साक्षी पटेल, अरनव पटेल, गरिमा द्विवेदी, शारिका द्विवेदी, शांति प्रजापति, शिवांशु कुशवाहा, श्रेया मिश्रा, चांदनी पटेल, रोशनी प्रजापति और वंशिका मिश्रा, उनके माता-पिता और मार्गदर्शी शिक्षक को सम्मानित किया गया।

घटनाक्रम

अमदरा थाना क्षेत्र के पकरिया में सराफा दुकानदार को बनाया निशाना

60 लाख के जेवर लेकर बदमाश रफूचक्कर

प्रातः किरण, सतना।

मैहर जिला के अमदरा थाना अंतर्गत पकरिया की एक सराफा दुकान से सोना- चांदी से भरा बैग लेकर बदमाश भागे हैं। मोटर साइकिल से भागे बदमाशों की तलाश अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में सागर ज्वेलर्स के संचालक सागर सोनी निवासी पकरिया का कहना है कि बैग में 60 लाख का सोना- चांदी था। जिसमें 10 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना है। इस बड़ी वारदात की खबर पाते ही निरीक्षक केपी त्रिपाठी मौके पर दल बल के साथ पहुंचे। इसके बाद सीएसपी महेन्द्र सिंह ने घटना सथल का जायजा लिया। एसपी अवधेश प्रताप सिंह भी घटना से जुड़े बिन्दुओं पर गौर करते हुए पुलिस टीमों को टास्क देते रहे।

पलक झपकते हो गई घटना

पीड़ित सराफा कारोबारी सागर सोनी ने बताया, सुबह करीब साढ़े 10 बजे वह दुकान पर आए। दुकान का लॉक खोलने के बाद घर से लेकर आए सोना- चांदी से भरा बैग दुकान के अंदर रख दिया। पास ही लगे हैंडपंप से पानी भरने गये तभी मोटर साइकिल से आए दो बदमाश बैग उठाकर भाग गए। काफी दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन पकड़ में नहीं आए। सराफा कारोबारी ने बदमाशों का हुलिया और उनकी गाड़ी के बारे में पुलिस को बताया है।

बदमाशों की चौतरफा तलाश

सराफा दुकान में इस घटना के बाद मैहर जिला के सभी थानों की पुलिस को अलर्ट कर बदमाशों की तलाश के लिए उनका हुलिया बताया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए हैं, लेकिन उनमें स्पष्ट तस्वीर नहीं है। इसलिए पुलिस अब कुछ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

कलेक्टर–एसपी पहुंचे परसमनिया

प्रातः किरण, सतना।

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के साथ बुधवार को तहसील उचेहरा अंतर्गत परसमनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की पठन-पाठन, पेयजल व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं सहित शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की मैदानी स्तर पर प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी मयंक चांदीवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

बैडमिंटन कोर्ट में कारोबारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कारोबारी अमृत बजाज की अचानक

मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। कारोबारी की मौत बैडमिंटन खेलते वक्त हुई। उनकी उम्र 57 साल की थी। ईदगाह भाठा निवासी अमृत बजाज अश्वनीनगर स्थित सोनकर बाड़ी के ओपन कोर्ट में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि दूसरे शॉट के दौरान शटल उठाने के लिए झुकते समय वे अचानक गिर पड़े। साथी खिलाड़ियों ने पहले उन्हें संभालने की कोशिश की। पानी के छींटे मारे गए और तौलिये से हवा दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तुरंत उन्हें रायपुरा स्थित जगन्नाथ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में वे सामान्य रूप से खेलते नजर आते हैं। पहला शॉट खेलने के बाद जैसे ही वे दूसरे शॉट पर झुकते हैं, अचानक गिर जाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

रफ्तार का कहर, खाना लेने निकली बैंक कर्मचारी को बुलेट ने मारी टक्कर

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु में लंच ब्रेक के दौरान खाना लेने बाहर निकली 27 साल की बैंक कर्मचारी योगेश्वरी को तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। यह घटना सोमवार को घटी है। दरअसल बैंक में कार्यरत योगेश्वरी राजाजीनगर में खाने का पैकेट लेकर डॉ. राजकुमार रोड पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि बाइक चलाने वाला उलसूर का एक स्टूडेंट है। उसका नाम दीपक है। टक्कर के समय वह तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। योगेश्वरी और दीपक दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। योगेश्वरी ने रात करीब 9 बजे दम तोड़ दिया, जबकि दीपक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया है और कहा है कि उसके ठीक होने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा।

नोएडा में 10 हजार गाड़ियों पर लगी रोक, दौड़ती मिलीं तो हो जाएंगी सीज

नोएडा, एजेंसी। नोएडा जिले की सड़कों पर दस हजार से ज्यादा गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी। परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही इन गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया गया है। इसके बाद भी यह गाड़ियां अगर सड़कों पर दौड़ते मिलेंगे तो सीज कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 10508 गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया गया था। इसमें 10 साल पुराने 1542 डीजल वाहन और 15 साल पुरानी 8966 पेट्रोल गाड़ियां शामिल हैं। एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने कहा कि समयसीमा पूरी करने वाले वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र पहले निलंबित किया जाता है और इसके बाद समयानुसार निरस्त करने की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया को करने से पहले गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजा जाता है। गाड़ी मालिक इन गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियां कबाड़ में बेच दी हैं वे परिवहन विभाग में पहुंचकर पंजीकरण निरस्त करवा लें। ऐसा न करने पर सबसे ज्यादा नुकसान व्यावसायिक वाहन मालिकों को होती है। व्यावसायिक वाहनों पर रोड टैक्स बनता रहता है। साथ ही जुर्माना भी लगता है। नोटिस मिलने के बाद वाहन मालिक परिवहन विभाग पहुंचकर इस बात की जानकारी देते हैं कि वे गाड़ी को बेच चुके हैं।

अब 'जगमोहन' में आएंगे ठाकुर जी, 'जगमोहन' में दर्शनः श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेगी सुगमता

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन से लेकर सजावट तक बड़े बदलाव

वृंदावन , एजेंसी। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आ रही है। मंदिर की व्यवस्थाओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और दिव्य बनाने के लिए 'हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी' ने कई क्रांतिकारी फैसलों पर मुहर लगा दी है। अब भक्त अपने आराध्य के और भी करीब से दर्शन कर सकेंगे। मैनेजमेंट कमेटी की 12वीं बैठक में न केवल दर्शन के स्वरूप को बदलने पर मंथन हुआ, बल्कि मंदिर की सजावट से लेकर ठाकुर जी के विग्रह की स्थिति तक को लेकर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिनसे वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। अभी तक ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन गर्भगृह से होते हैं, लेकिन अब कमेटी उन्हें 'जगमोहन' (गर्भगृह के बाहर का हिस्सा) में विराजमान करने पर विचार कर रही है। दरअसल, बांके बिहारी जी का विग्रह 'चल विग्रह' माना जाता है। यदि ठाकुर जी जगमोहन में विराजमान होते हैं, तो दर्शन का दायरा बढ़ जाएगा और दूर खड़े भक्त भी बिना किसी धक्का-मुक्की के आसानी से निहार सकेंगे। कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक कुमार ने बताया कि इससे मंदिर का कुप्रबंधन समाप्त होगा और शरद पूर्णिमा जैसा दिव्य अनुभव भक्तों को आम दिनों में भी मिल सकेगा। मंदिर प्रबंधन ने आधुनिक तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम पेश करने

का फैसला किया है। आगामी 25 फरवरी से बांके बिहारी जी के दर्शनों की 'लाइव स्ट्रीमिंग' शुरू होने की प्रबल संभावना है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा भक्त घर बैठे दर्शन कर सकेगा। इसके साथ ही, मंदिर की सजावट में अब प्लास्टिक के गुब्बारे या अप्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। बुधवार से केवल प्राकृतिक फूलों और वस्तुओं से ही मंदिर महकेगा। यही नहीं, ठाकुर जी पर चढ़ने वाली मालाओं को अब फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उनसे विधवा महिलाओं द्वारा धूपबत्ती और अगरबत्ती तैयार कराई जाएगी, ताकि बिहारी जी की महक भक्तों के घरों तक पहुंचे।

फाल्गुन होली उत्सव पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को जगमोहन में विराजमान करने, मन्दिर की ओर से पूर्व की भांति व्रतोत्सव निर्णय पत्र छपवाने, मन्दिर में फाल्गुन होली उत्सव के दौरान पुष्प सजावट कराने, चन्द्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को होने के कारण ठाकुर श्रीबांके बिहारीजी मन्दिर की परिवर्तित समय सारिणी, मन्दिर के सभी सेवायतों के साथ सम्बद्ध नौकरों/सहयोगियों का चरित्र सत्यापन, दान की गयी धनराशि पर आयकर छूट, मन्दिर में उपलब्ध अनुपयोगी वस्तुओं का मूल्यांकन कराने के उपरान्त नीलामी, मन्दिर कार्यालय के अभिलेखों का एकाउण्ट सुचारू रूप से व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखने, मन्दिर की बहुमूल्य वस्तुओं को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉकर में रखने के अलावा बैंक खातों से संचालन, भोग प्रसाद के लिए प्रतिदिन व्यय 22 हजार 300 से अधिक करने, मन्दिर चबूतरे पर भेंट एवं किनका रसीद काउन्टर स्थापित करने के प्रस्ताव थे।

समय परिवर्तन पर सख्त रुखः सुप्रीम कोर्ट की अवमानना!

बैठक में दर्शन के समय परिवर्तन को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया। कमेटी ने स्पष्ट किया कि ढाई महीने पहले गोस्वामियों की सहमति से जो नया समय निर्धारित किया गया था, उसे लागू न करना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि नए समय का पालन नहीं किया गया, तो सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, फाल्गुन होली उत्सव के दौरान ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान करने और 3 मार्च 2026 को होने वाले चंद्र ग्रहण के मद्देनजर नई समय सारिणी पर भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मंदिर की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए सभी सेवायतों और उनके सहयोगियों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर की बहुमूल्य वस्तुओं को बैंक लॉकर में सुरक्षित रखने और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाली संस्था को हटाने जैसे कड़े फैसले भी लिए गए हैं।

... तो रद्द हो सकती है स्कूल की मान्यता, शिक्षा बोर्ड की चेतावनी

आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा, कैमरों की निगरानी रहेगी

चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड ने निजी स्कूलों को भी

सख्त चेतावनी दी है। यदि किसी निजी स्कूल का नाम पेपर लीक मामले में सामने आता है और जांच में दोष सिद्ध होता है, तो संबंधित स्कूल पर जुर्माने के साथ उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है।

गुरुग्राम जिले में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी, नकल या पेपर लीक की घटना सामने आती है और परीक्षा दोबारा करानी पड़ती है, तो उसका पूरा खर्च संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूला जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त केंद्र अधीक्षक, उप-अधीक्षक, पर्यवेक्षक और ड्यूटी स्टाफ की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर विभागीय कार्रवाई के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। बोर्ड ने निजी स्कूलों को भी सख्त चेतावनी दी है। यदि किसी निजी स्कूल का नाम पेपर लीक मामले में सामने आता है और जांच में दोष सिद्ध होता है, तो संबंधित स्कूल पर जुर्माने के साथ उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है। परीक्षा कक्षों की रिकॉर्डिंग कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखनी होगी। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के कमरों की खिड़कियों और दरवाजों की जांच, बाहरी हस्तक्षेप पर रोक, तथा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ न होने देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

उड़नदस्ते भी नजर रखेंगे: किसी केंद्र से पेपर आउट होने या परीक्षा रद्द होने की स्थिति बनती है, तो दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित केंद्र स्टाफ और जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा। गुरुग्राम में परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों की उड़नदस्ते भी निगरानी रखेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बार परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

गुजरात में 74 लाख वोटरों के नाम हटाए गए

एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने पब्लिश की अंतिम मतदाता सूची

अहमदाबाद, एजेंसी। चुनाव आयोग (ईसी) ने गुजरात में एसआईआर का काम पूरा कर लिया है। राज्य में यह प्रक्रिया लगभग साढ़े तीन महीने तक चली। मंगलवार को अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किए, उनके मुताबिक गुजरात में अब कुल वोटर्स की संख्या 4.40 करोड़ हो गई है।

फाइनल मतदाता सूची में 4,40,30,725 वोटर्स के नाम हैं, जो पिछले साल 19 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने के बाद 5.60 लाख नाम और जुड़े हैं। कितने नाम हटाए गए? मसौदा मतदाता सूची में करीब 74 लाख वोटर्स के नाम

हटा दिए गए और अब मतदाताओं की कुल संख्या 4.34 करोड़ हो गई, जबकि पहले यह 5.08 करोड़ थी। इस तरह, अंतिम मतदाता सूची में 4.40 करोड़ वोटर्स के साथ 5.60 लाख वोटर्स और जुड़ गए हैं। वोटर लिस्ट में किसी का नाम शामिल करने या हटाने के बारे में आपत्तियां और दावे 19 दिसंबर, 2025 और 30 जनवरी, 2026 के बीच जमा किए गए थे। इसके बाद, चुनाव अधिकारियों ने आपत्तियों की पुष्टि की और 10 फरवरी तक उनका निपटारा कर दिया। 34 जिला चुनाव अधिकारियों, 182 वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, 855 असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, 50,963 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारियों) और बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी से यह काम तय समय में पूरा हो गया।

नोएडा एक्सप्रेसवे और मेट्रो रूट के किनारे प्लॉट होंगे सस्ते

ग्रेटर नोएडा, एजेंसी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे प्लॉट आवंटन सस्ता हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन शुल्क को प्राधिकरण ने समाप्त करने का फैसल लिया है। यह शुल्क साढ़े सात प्रतिशत था। यही नहीं मेट्रो रूट के किनारे भी लिए जाने वाले शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत कर दिया गया है। लोकेशन शुल्क घटने से संपत्ति की दरों में कमी आ सकती है। एक्सप्रेसवे का नोएडा क्षेत्र में करीब 20 किलोमीटर का हिस्सा है। इस क्षेत्र में 40 से ज्यादा सेक्टरों की संपत्तियों की आवंटन कीमतें लोकेशन शुल्क हटाने के बाद कम होंगी। मेट्रो का लोकेशन शुल्क भी काफी कम लगेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के किनारे का लोकेशन शुल्क आईटी, आईटी-संस्थागत, व्यावसायिक और कॉरपोरेट ऑफिस के प्लॉट पर 2019 से लागू था। एक्सप्रेसवे के किनारे इन्हीं भू-उपयोग के भूखंड नियोजन विभाग की तरफ से निकाले गए हैं। इसके अलावा मेट्रो रूट (ब्लू, मैजेंटा और एक्वा लाइन) के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी तरह की संपत्तियों पर 10 प्रतिशत का लोकेशन शुल्क फरवरी 2025 में यूनिफाइड पॉलिसी के साथ लगाया गया था।

अंटार्कटिका के गहरे बर्फीले समंदर में तैरती दिखी स्लीपर शार्क, आश्चर्यचकित रह गए वैज्ञानिक

वाशिंगटन, एजेंसी। वैज्ञानिकों को उस समय गहरा आश्चर्य हुआ जब अंटार्कटिका के लगभग जमते पानी में पहली बार एक विशाल शार्क कैमरे में कैद हुई। यह दुर्लभ दृश्य जनवरी 2025 में रिकॉर्ड किया गया, जब एक स्लीपर शार्क समुद्र तल पर सुस्त गति से तैरती दिखाई दी। यह शार्क 3 से 4 मीटर लंबी बताई जा रही है और करीब 490 मीटर की गहराई में पाई गई, जहां पानी का तापमान केवल 1.27 डिग्री सेल्सियस था। अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि इतनी ठंडी अंटार्कटिक जलधाराओं में शार्क का अस्तित्व संभव नहीं है। यह ऐतिहासिक फुटेज मिंडेरू-यूडब्ल्यूए डीप-सी रिसर्च सेंटर द्वारा लगाए गए कैमरे से रिकॉर्ड हुई, जिसे दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के पास समुद्र की गहराई में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र दक्षिणी महासागर की सीमा के भीतर आता है। इस शोध केंद्र के संस्थापक निदेशक एलन जैमीसन ने कहा कि अंटार्कटिक महासागर में अब

तक किसी भी शार्क के पाए जाने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उन्होंने इसे समुद्री विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज बताया।वीडियो में एक स्केट मछली भी दिखाई देती है, जो शार्क के गुजरने के बावजूद स्थिर रहती है। स्केट की मौजूदगी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक नहीं थी, क्योंकि उनकी प्रजाति पहले से ही इस क्षेत्र में ज्ञात है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण शार्क जैसी प्रजातियां अब ठंडे इलाकों की ओर बढ़ रही हो सकती हैं। हालांकि, यह भी संभव है कि स्लीपर शार्क लंबे समय से इन गहराइयों में मौजूद रही हो, लेकिन इंसानी नजरों से ओझल रही हो।वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये शार्क समुद्र की गहराइयों में मृत व्हेल, विशाल स्क्विड और अन्य समुद्री जीवों के अवशेषों पर निर्भर रहती हैं। अंटार्कटिक जलक्षेत्र में साल के अधिकांश समय शोध संभव नहीं होता, इसलिए ऐसे चौंकाने वाले दृश्य बहुत कम सामने आते हैं।

ट्रम्प ने जापान के साथ ट्रेड डील के शुरूआत की घोषणा की

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को जापान के साथ एक निवेश समझौते के शुरूआत का एलान किया है। जापान ने अमेरिका में कुल 550 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया है, जो ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के अंत तक, यानी जनवरी 2029 तक पूरा होगा।

यह समझौता पिछले साल जुलाई में हुआ था, जिसमें जापान ने अमेरिका में निवेश करने के बदले अपनी कारों और अन्य सामानों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ को कम करवाया था। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके बताया कि इस 550 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के तहत पहली परियोजनाओं की शुरुआत हो गई है। इनमें तीन बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 36 बिलियन डॉलर है। पहली परियोजना जॉर्जिया राज्य में क्रिटिकल मिनरल्स की है, जहां सिंथेटिक डायमंड या अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन होगा, जो अमेरिका की विदेशी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।

दूसरी परियोजना टेक्सास राज्य में तेल और गैस की सुविधाओं की है, जिसमें गल्फ कोस्ट पर एक डीपवॉटर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट सुविधा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो अमेरिकी ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा देंगे।

तीसरी परियोजना ओहियो राज्य में पावर जेनरेशन प्लांट की है, जो एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस पावर प्लांट होगा। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्तर के हैं और इन्हें लागू करने में टैरिफ की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इसे अमेरिका और जापान के लिए ऐतिहासिक समय बताया।

उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर से निर्माण कर रहा है, उत्पादन कर रहा है और जीत रहा है। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में जापान के उद्योग मंत्री रयोसी अकाजावा और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के बीच बैठक हुई थी, जहां पहले दौर के निवेश में तेजी लाने पर सहमति बनी।

हड्डी टूटी न हो और स्किन कटी न हो... तालिबानी कानून में पत्नी और बच्चों को पीटने की इजाजत

● इस कानून में कौन-कौन से प्रावधान ● हड्डी टूटी न हो और स्किन कटी न हो

काबुल, एजेंसी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने एक नया क्रिमिनल कोड लागू किया है, जिसके बाद ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स में चिंता बढ़ गई है। इस कानून के आने के बाद महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने इस पर साइन भी कर दिए हैं।

90 पेज के क्रिमिनल कोड में इस्लामी धर्मग्रंथों की पुरानी शर्तें शामिल हैं। इससे ऊपर बैठे धार्मिक नेताओं को क्रिमिनल केस से लगभग छूट मिल जाती है और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सबसे कड़ी सजा तय हो जाती है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह कानून प्रभावी रूप से महिलाओं को दासों के बराबर रखता है। इसमें कहा गया है कि या तो दास मालिक या पति अपनी पत्नियों को मारपीट के रूप में विवेकाधीन दंड दे सकते हैं।

यह कानून समाज को सख्त वर्गों में बांटता है, धार्मिक विद्वानों को कानूनी जांच से ऊपर रखता है और पतियों और पिताओं को तय लिमिट में महिलाओं और बच्चों को शारीरिक रूप से सजा देने की इजाजत देता है। इस कानून में अपने पति की इजाजत के बिना रिश्तेदारों से मिलने जाने वाली महिलाओं के लिए तीन महीने तक की जेल का भी नियम है और गुलामी कहे जाने वाले रिवाजों को मान्यता देता है। कानून में कहा गया है कि गंभीर अपराधों के लिए शारीरिक सजा सुधार सेवाएं नहीं, बल्कि इस्लामी मौलवी देंगे। इसके साथ ही कम गंभीर अपराधों में पति अपराधी पत्नी को पीट के सजा दे सकता है। यह कानून उन महिलाओं को न्याय दिलाने का रास्ता तो देता है जिन पर हमला होता है, लेकिन उन्हें जज को अपने घाव दिखाकर यह साबित करना होता है कि उन्हें गंभीर शारीरिक नुकसान हुआ है और साथ ही उन्हें पूरी तरह से ढका रहना होता है। इतना ही नहीं, नए कोड के तहत अगर कोई अफगान महिला सभी कानूनी और सामाजिक मुश्किलों को पार करके यह साबित कर देती है कि उसके पति ने उस पर गंभीर हमला किया है तो भी पति को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की सजा दी जाएगी।

बजट प्रतिक्रिया

सरकार का निर्णय समाज प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है-अभय चौधरी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये के प्रावधान का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय समाज के वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद वर्ग के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान एक सराहनीय कदम है। हमारी सरकार सदैव से मानती रही है कि विकास केवल सड़कों और भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सशक्त करना भी उतना ही आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर देना सामाजिक समरसता को मजबूत करेगा। इस योजना से न केवल श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से यह योजना समाज के बड़े वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम-नवीन चौधरी

भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला मीडिया प्रभारी नवीन चौधरी ने लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, लाड़ली बहना योजना के लिए इतना बड़ा बजट प्रावधान हमारी सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सिर्फआर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बहनों के आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का माध्यम है। इस योजना से प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा, परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में महिलाओं की भागीदारी और भी सशक्त होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पारदर्शी क्रियान्वयन के जरिए यह पहल प्रदेश के विकास को नई गति देगी।

700 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता।

मध्यप्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी है। बांह पर काली पट्टी बांधी हुई है और जिस स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर इस बार 9 सूत्रीय मांगें नहीं मानी गई तो फिर भोपाल की तरफकूच किया जाएगा तथा आंदोलन को तेज करेंगे।

संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि कर्मचारी विभिन्न इकाइयों में सेवाएं दे रहे हैं। जिला अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लीनिक, पोषण पुनर्वास केंद्रों में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार की दोहरी नीति दमनकारी नीति के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अधिकारियों एवं निजी

आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दोहरी नीति के खिलाफशासन प्रशासन का एवं विभाग का पत्रों एव करना प्रदर्शन के द्वारा ध्यान आंकर्षण कराया गया, लेकिन सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में ग्वालियर जिले के 700 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं और काली पट्टी बांधकर काम कर अपना विरोध जता रहे हैं।

प्रमुख मांगें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सेवाएं दे चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना कोई शर्त के विभाग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों समायोजन कर नियमित किया जाए अथवा बिना कोई शर्त के संविदा में मर्ज किया जाए। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में निम्न पदों पर सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन एवं हरियाणा शासन की तर्ज पर ठोस नीति तैयार कर स्थाई समाधान किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी के लिए न्यूनतम 21 हजार वेतन निर्धारित किया जाए। श्रम विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित वेतन वृद्धि की गई थी उक्त अनुसार 11 माह के एरियर राशि भुगतान नहीं किया गया विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। समस्त जिलों में निजी आउटसोर्स एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाए विभाग द्वारा सीधा खातों में भुगतान किया जाए। रेगुलर कर्मचारियों की तरह शासकीय छुट्टियों की सुविधा दी जाए। आउटसोर्स कर्मचारी को भी नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाये। ग्रेज्यूटी का लाभ दिया जाये।

महिला ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई

पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर सात दिन में महिला से 3.47 लाख की साइबर ठगी

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता।

ग्वालियर में पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक महिला को निशाना बना लिया। मामला मुरार थाना क्षेत्र की सीपी कॉलोनी का है, जहां 7 फरवरी से शुरू हुई ठगी का खुलासा तब हुआ जब महिला के खाते में दिख रहा मुनाफा बढ़कर करीब साढ़े पांच लाख रुपए हो गया।

महिला ने जब यह रकम निकालने की कोशिश की तो निकासी संभव नहीं हुई। ठगों से संपर्क करने पर उन्होंने शर्त रखी कि जब तक उनके बताए खाते में 11.50 लाख रुपए जमा नहीं किए जाते, तब तक राशि नहीं निकलेगी। ठगी का एहसास होने पर महिला ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुरार थाना क्षेत्र स्थित सीपी कॉलोनी

निवासी अनीशा पत्नी निखिल ने शिकायत में बताया कि 7 फरवरी को टेलीग्राम ऐप पर उन्हें पार्ट-टाइम जॉब का मैसेज मिला, जिसमें ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया। जानकारी लेने पर कहा गया कि उन्हें इंटरनेट पर रिव्यू देने होंगे।

महिला के अनुसार, शुरुआत में उसने 1022 रुपए जैनगो ऐप के जरिए क्रिप्टो में निवेश किए, जिसके बदले उसे 1424 रुपए मिले। शुरुआती मुनाफा देखकर उसने बताए गए अलग-अलग आईडी पर रकम लगानी शुरू कर दी। जब लाभ बढ़ गया तो उसने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन निकासी नहीं हो सकी। ऐप पर संपर्क करने पर उसे बताया गया कि उसका प्रॉफिट अभी कम है और रकम निकालने के लिए और टास्क पूरे करने होंगे।

महिला से सात दिन के भीतर 3 लाख 47 हजार 571 रुपए ठग लिए गए। ज्यादा मुनाफे के लालच में महिला ने अलग-अलग टास्क लेने के नाम पर रकम जमा की, जिससे ऐप में उसका प्रॉफिट बढ़कर 5 लाख 85 हजार 613 रुपए दिखने लगा। जब उसने राशि निकालने की कोशिश की तो निकासी नहीं हो सकी। दोबारा टेलीग्राम पर संपर्क करने पर ठगों ने कहा कि जब तक उसके खाते में 11.61 लाख रुपए बैलेंस नहीं होगा, तब तक पैसा नहीं निकलेगा। इस पर महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले में मुरार थाना प्रभारी मैना पटेल ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

मध्यप्रदेश सरकार का बजट समृद्ध मप्र के लिये बनाया गया बजट है-भूपेंद्र जैन

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेन्द्र जैन ने मध्यप्रदेश के वर्ष 2026-27 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि यह बजट समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये बनाया गया बजट है किन्तु इस बजट में व्यापारियों के एवं व्यापरियों के मार्केट, बाजार आदि क्षेत्रों के डबलपमेंट की बात नहीं कही गई है। औद्योगिक प्रोत्साहन के लिये लगभग 2500 करोड रूपये का प्रावधान है, वहीं डेस्टीनेशन मध्यप्रदेश, इन्वेस्टमेंट ड्राइव के लिये

लगभग 200 करोड का प्रावधान है, किन्तु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के बाजारों को, मार्केटो को सुव्यवस्थित करने, बाजारों में मूलभूत सुविधा जुटाने, अतिक्रमण मुक्त बाजार बनाने एवं टेक्नोलोजीयुक्त बाजार बनाने की दिशा में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश के लिये सुविधा दी गई है किन्तु बाजारों की अधोसंरचना के विकास के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 500 करोड से अधिक की राशि अगर रखी जाती तो हम समृद्ध मध्यप्रदेश में समृद्ध बाजार और मार्केट भी तैयार कर सकते थे।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव, वित्तमंत्री जगदीश देवडा, प्रधानमंत्री की स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो की परिकल्पना से अलग दृष्टिकोण रखते हुये स्वदेशी के विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिये एक निश्चित राशि इस बजट में आवंटन किया जाना आवश्यक था।

किट्टा पार्टी ग्रुप में हुआ गीत और गजल कार्यक्रम

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता। किट्टा पार्टी ग्रुप में प्रत्येक माह सदस्यों को जिंदगी से जोडने के लिए कार्यक्रम किये जाते रहे हैं। इसी क्रम में गीत और गजल का कार्यक्रम शायर अतुल अजनबी और गजल गायक नवनीत कौशल की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के प्रारंभ में क्लब संयोजक राहुल गुप्ता स्पर्शी द्वारा दो नए सदस्यों सत्ता सुधार वाले श्याम श्रीवास्तव एवं मस्त मौला अमृत रंधावा को ग्रुप से जोड़ा गया। श्याम श्रीवास्तव का स्वागत अश्विन जैन द्वारा और अमृत रंधावा का स्वागत धर्मेंद्र शर्मा द्वारा फूल माला पहनकर किया गया। इसके बाद श्याम श्रीवास्तव द्वारा स्वागत किया गया। शायर अतुल अजनबी व गजल गायक नवनीत कौशल का स्वागत डॉ. ओपी वर्मा द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में ग्रुप से जुड़े धर्मेंद्र शर्मा ने हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते गीत गाकर कार्यक्रम का आगाज किया। उसके पश्चात जितेंद्र तागड़े ने है अपना दिल तो आवारा, और दीपक भटनागर ने ये शाम मस्तानीगीत सुना कर महफिल में मस्ती बिखेर दी। उसके शायर अतुल अजनबी ने एक से बढक़र शायरी सुनाई जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, इक नमी सी मिरी दीवार में आ जाती है, और किसी दरख़्त से सीखो सलीक़ा जीने का, जो धूप छाँव से रिश्ता बनाए रहता है। फिर गजल गायक नवनीत कौशल ने किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, और चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक से बढक़र एक गजल सुनाई।

ऑल इंडिया लीनेस क्लब का शपथ ग्रहण हुआ

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता। ऑल इंडिया लीनेस क्लब ग्वालियर द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होटल सौराव इथिया सिटी सेंटर में आयोजित किया गया। पूर्व एआईएलसी प्रेसिडेंट डॉ. आशा माथुर द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस विकास गंगवाल थे। नई टीम में अध्यक्ष लीनेस गीता शर्मा, सचिव लीनेस शशि शाह बंसल, कोषाध्यक्ष लीनेस रंजना चतुर्वेदी को मनोनीत किया गया। वहीं ममता कुलश्रेष्ठ, सलमा कुरैशी और उषा सिकरवार को बोर्ड आफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया। रीजन चेयरपर्सन लीनेस डॉ मीरा जैन कार्यक्रम में उपस्थिति रही।

केआरजी कॉलेज की छात्राओं ने किया ओरछा वाइल्डलाइफसेंचुरी का भ्रमण

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता।

शासकीय केआरजी कॉलेज के प्राणी शास्त्र विभाग एवं इको क्लब द्वारा प्राचार्य डॉ. साधना श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में छात्राओं को ओरछा वाइल्डलाइफ सेंचुरी का शैक्षणिक भ्रमण कराया।

इस अवसर पर प्राणी शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार दुबे ने प्रकृति में जंतुओं एवं पौधों के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में भी सहायक होते हैं। आयोजन प्रभारी एवं इको क्लब इंचार्ज डॉ. मोहित आर्य ने बताया कि बेतवा एवं जामनी नदियों के तट पर स्थित ओरछा अपनी भौगोलिक स्थिति एवं शुष्क परणपति वनों के लिए प्रसिद्ध है।

ओरछा वन्य जीव अभ्यारण में हिरण, नीलगाय, वाइल्ड बोर, लोमड़ी, लंगूर, बंदर, भालू एवं तेंदुए समेत कई जंगली जानवरों एवं पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें जलीय प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। डॉ. शक्ति भारद्वाज ने ओरछा के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व से अवगत कराया। डॉ. प्रीति मौर्य एवं डॉ. सुष्मिता श्रीवास्तव ने बेतवा नदी में पाए जाने वाले जलीय जीवों एवं जल के भौतिक रासायनिक गुणों की जानकारी दी। डॉ. प्रतिष्ठा द्विवेदी एवं डॉ. नेहा बुनकर ने परियोजना कार्य के लिए रिपोर्ट राइटिंग की जानकारी दी। भ्रमण में एमएससी प्राणी शास्त्र एवं बायोटेक्नोलॉजी की 40 छात्राएं उपस्थित थीं।

मुद्दा

मिलावट की मंडी बनता ग्वालियर

ट्रांसपोर्ट नगर से स्टोन पार्क तक जहर का कारोबार, विभागीय कार्रवाई के बावजूद बेखौफ 'मिलावट माफिया'

पदमेश अग्रवाल

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता। कभी अपनी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाने वाला ग्वालियर अब एक खतरनाक पहचान की ओर बढ़ता दिख रहा है पैकेट असली, माल नकली। मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों के काले कारोबार ने शहर को देशभर में बदनाम करना शुरू कर दिया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब मिलावटखोरों के हौसले कानून और कार्रवाई दोनों से कहीं अधिक मजबूत नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट नगर में शिव पुजारी ब्रांड की सौंफपर सीमेंट की कोटिंग कर नकली जीरा बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। यह खुलासा न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि इस बात का भी प्रमाण था कि मिलावटखोर अब मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। सीमेंट जैसी घातक सामग्री को खाद्य पदार्थों में मिलाना सीधे-सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है।

शहर से दूर, सन्नाटे में पनप रहा 'जहर का साम्राज्य'

मिलावट का यह काला कारोबार अब शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों तक सीमित नहीं रहा। ट्रांसपोर्ट नगर, सागरताल, स्टोन पार्क शंकरपुर, ताल रायरू और वैयर हाउस के पास सौरभ द्वारा नकली मसालो का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है बातचीत मे उन्होंने खुद स्वीकार किया की वह पहले मसालो मे मिलावट का काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने काम बंद कर दिया है, जबकि सूत्रों का कहना है की कुछ समय पूर्व ही इन्होने चक्की का लाइसेंस लिया है! सुनसान इलाके अब नकली और मिलावटी सामान बनाने के सुरक्षित अड्डे बनते जा रहे हैं।

हाल ही में खाद्य विभाग की टीम ने स्टोन पार्क स्थित गजानन ट्रेडर्स से गोला कस के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या मिलाया जा रहा था कि कारोबारी को शहर से दूर, सुनसान इलाके में गोदाम बनाना पड़ा? क्या यह सिर्फ कारोबार की सुविधा थी या फिर कानून की नजरों से बचने की सुनियोजित साजिश?

'राजश्री' और 'शंकर' भी निशाने पर

सूत्रों के अनुसार इन इलाकों में किसी गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा नकली 'राजश्री' और 'शंकर' ब्रांड के बंडल तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें असली पैकेजिंग में बाजार में उतारा जा रहा है। बाहर से देखने में ये पैकेट बिल्कुल असली प्रतीत होते हैं, लेकिन अंदर भरा होता है सस्ता, मिलावटी और कभी-कभी जहरीला पदार्थ।

नकली 'सर्फएक्सल' का खेल जारी!

दाल बाजार स्थित अलंकार होटल के पास कारोबार करने वाले एक साहू पर 10 रुपये की पैकिंग में बिकने वाले 'सर्फ एक्सल' की नकली पैकिंग तैयार कर बेचने के आरोप लगे हैं।

सूत्रों का कहना है कि डुप्लीकेट पैकेट असली जैसे दिखते हैं, जिससे उपभोक्ता आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति पूर्व में नकली घी के कारोबार में भी लिप्त रह चुका है। कासिम खान का बाड़ा, दाल बाजार स्थित ठिकाने पर पहले छापामार कार्रवाई भी हो चुकी है। कार्रवाई के बाद कुछ समय कारोबार ठप रहा, लेकिन अब फिर से डुप्लीकेसी शुरू होने की चर्चा है। स्थानीय व्यापारियों में इसे लेकर चिंता का माहौल है। नकली ब्रांड बेचने से उपभोक्ताओं के साथ सीधा धोखा हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग दोबारा सख्त कदम उठाएगा? यह संगठित नेटवर्क न केवल उपभोक्ताओं को धोखा दे रहा है, बल्कि असली ब्रांड की साख को भी गहरा नुकसान पहुंचा रहा है।

विभाग की कार्रवाई के बावजूद 'चौकसी तंत्र' से बच निकलते हैं मिलावटखोर

खाद्य विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन मिलावटखोरों ने इससे बचने का भी पुख्ता इंतजाम कर रखा है। महाडिक के नेतृत्व में दाल बाजार स्थित ओमकार पिसाई केंद्र पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कार्रवाई खत्म होते ही कुछ ही देर में कारोबार फिर शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मिलावटखोरों ने गोदाम के बाहर अपने आदमी तैनात कर दिए, जो हर आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत अंदर तक पहुंचाते हैं। मिलावट को लेकर हमने जब शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों से चर्चा की तो सभी का एक सुर मे कहना था की ऐसे कारोबारियों के खिलाफसख्त कार्यवाही होना चाहिए वही कुछ कारोबारियों का तो कहना था की पूर्व मे जिस तरह तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने नकली घी कारोबारियों पर रासुका लगाई थी उसी प्रकार अब मसालो मे लकड़ी का बुरादा की मिलावट करने वालो के खिलाफभी रासुका के तहत कार्यवाही की जाना चाहिए! यह पूरा सिस्टम किसी संगठित अपराध सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, जहां हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है और कानून को चकमा देने की पूरी तैयारी रहती है।

किराये की चक्की में तैयार हो रहा 'जहर'

सूत्र बताते हैं कि मुर्गी फर्म के पास राठौर ठेकेदार द्वारा एक बृजेश नामक व्यक्ति से चक्की किराये पर लेकर बड़े पैमाने पर मसालों में मिलावट की जा रही है। यहां सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थों को मिलाकर उन्हें नामी ब्रांड के रूप में पैक किया जाता है और बाजार में खपाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस और निर्णायक कार्रवाई सामने नहीं आई है।

कानून कमजोर या इरादे?

बार-बार कार्रवाई के बावजूद मिलावटखोरों का बच निकलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या मौजूदा कानून इतने कमजोर हैं कि मिलावटखोरों को डर ही नहीं लगता? या फिर कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है?

किसानों का रुपए नहीं मिला तो लक्ष्मीगंज मंडी होगी बंद

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता। मध्य प्रदेश किसान सभा द्वारा बुधवार को कृषि उपज मंडी लक्ष्मीगंज में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन मे किसान सभा के राज्य महासचिव अखिलेश यादव मुख्य रूप से शामिल रहे। मंडी में किसानों द्वारा बेची गई धान का भुगतान पिछले डेढ़ वर्षों के अटका पड़ा है। व्यापारियों एवं मंडी कर्मचारीयों की मिलीभगत से हुए घोटाले में करीब 8 करोड़ रुपए का किसानों का भुगतान लंबित पड़ा है। वहीं सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है और किसान अपने रुपयों के लिए भटक रहा है। किसान सभा के जिला अध्यक्ष तलविंदर सिंह ने चेतावनी दी कि अगर किसानों का रुपया जल्द नही मिलता तो किसान सभा सभी किसानों के साथ मिलकर गल्ला मंडी को अनिश्चित काल के लिए बंद करेगी।

एस4 की सामाजिक गोष्ठी को प्रशासन ने दी अनुमति

शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप होंगे मुख्य वक्ता

ग्वालियर, प्रातःकिरण संवाददाता। जिला प्रशासन ने सवर्ण समाज समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित हो रही सामाजिक गोष्ठी कार्यक्रम को अनुमति दे दी है। यह कार्यक्रम 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे से गोले का मंदिर स्थित इंद्रप्रस्थ गार्डन में आयोजित होगा। गौरतलब है कि एस4 संगठन के साथ पुलिस प्रशासन की बैठक हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने बुधवार को आयोजन की परमिशन दे दी है।

कार्यक्रम संयोजक अखिलेश पांडे एवं एड. आशुतोष दुबे ने बताया कि कार्यक्रम की अनुमति मिलने पर बुधवार को मानस भवन प्रांगण में आयोजन समिति की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एस4 के संस्थापक एवं शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज होंगे।

वक्ता के रूप में पूर्व प्रधान आयुक्त भारत सरकार डॉ. अनूप श्रीवास्तव, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना डॉ. राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना महिपाल सिंह मकराना, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजीव सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे।

हमें मैच खेलने जाने से पहले बर्तन धोने पड़े, पाकिस्तान के कप्तान का बड़ा खुलासा

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान हॉकी कप्तान शकील अम्माद बट ने ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे से लौटने के बाद नेशनल फेडरेशन पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरे के दौरान उनकी टीम को रहने की जगह की कमी के कारण न सिर्फ सड़कों पर भटकना पड़ा, बल्कि मैच खेलने जाने से पहले बर्तन भी धोने पड़े।

बट ने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनसे झूठ बोल रहा था और बस बहुत हो गया। बट ने गुस्से में पूछा, हम फेडरेशन के मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। जब खिलाड़ियों को मैच खेलने जाने से पहले किचन साफ ??करना और बर्तन धोने पड़ते हैं, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं?

सरकारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (पीएसबी) के ऑस्ट्रेलिया में नेशनल टीम के होटल में रहने का इंतजाम करने के लिए 10 मिलियन रुपए से ज्यादा देने की बात कन्फर्म करने के बाद पीएचएफ की कड़ी आलोचना हुई है। पाकिस्तान हॉकी टीम को कैनबरा के लिए अपनी आगे की फ्लाइट से पहले सिडनी एयरपोर्ट पर 13-14 घंटे इंतजार करना पड़ा।

इससे भी अधिक परेशान करने वाली खबरें तब आईं जब टीम एफआईएच प्रो लीग मैचों से पहले अपने होटल में चेक इन कर रही थी। खिलाड़ियों को बताया गया कि उनकी कोई बुकिंग नहीं है क्योंकि होटल मैनेजमेंट को कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया गया था। खिलाड़ियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और उनके रहने की जगह का इंतजाम होने से पहले वे सड़कों पर घूमते रहे।

गिरोना डर्बी में बार्सिलोना को झटका, यामाल का पेनल्टी मिस पड़ा भारी

स्पेनिश (एजेंसी)। स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना को गिरोना के खिलाफ 2-1 की हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह ला लीगा तालिका में रियल मैड्रिड से दो अंक पीछे हो गई। रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएदाद को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन हांसी फ्लिक की टीम गिरोना के खिलाफ बढ़त कायम नहीं रख सकी।

यामाल की चूकी पेनल्टी बनी टर्निंग पॉइंट- पहले हाफ में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल नहीं हो सका। बार्सिलोना को बढ़त का सुनहरा मौका तब मिला जब डानी ओल्मो को बॉक्स में गिराया गया और पेनल्टी मिली। हालांकि युवा स्टार लामिन यामाल ने स्पॉट-किक पोस्ट पर मार दी। 59वें मिनट में पाउ क्यूबर्सी ने जूल्स कुंडे के क्रॉस पर हेडर से बार्सिलोना को बढ़त दिलाई। लेकिन गिरोना ने जल्द ही वापसी कर ली।

लेमार और बेल्ट्रान ने पलटा मैच- थॉमस लेमार ने व्लादिस्लाव वानात के पास पर गोल कर स्कोर बराबर किया। इसके बाद गिरोना का आत्मविश्वास बढ़ गया। 87वें मिनट में फान बेल्ट्रान ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गिरोना को 2-1 की बढ़त दिलाई। इस गोल से पहले कुंडे पर फाउल को लेकर बार्सिलोना ने आपत्ति जताई, लेकिन रेफरी ने खेल जारी रखा।

गोलकीपर ने बचाई उम्मीद, फिर भी हार

बार्सिलोना के गोलकीपर जोन गार्सिया ने कई बेहतरीन बचाव किए, जिसमें इवान मार्टिन और वानात के खिलाफ डबल सेव भी शामिल था। इसके बावजूद टीम हार से नहीं बच सकी।

एनरिक नोर्त्जे टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने

नईदिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के अरुण जेतली स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्जे ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। श्रीलंका के खिलाफ मैच में दो विकेट हासिल करते ही वह टी20 विश्व कप इतिहास में तेज गेंदबाजों द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज टिम साउथी को पीछे छोड़ दिया और अब वह श्रीलंका के महान लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।

मलिंगा का रिकॉर्ड खतरे में- तेज गेंदबाजों की इस सूची में सबसे ऊपर श्रीलंका के महान लसिथ मलिंगा का नाम है, जिनके नाम 38 विकेट दर्ज हैं। नोर्त्जे अब सिर्फ एक विकेट दूर हैं और अगले मैच में यह रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। मलिंगा लंबे समय तक टी20 क्रिकेट में यॉर्कर के लिए मशहूर रहे और उन्होंने कई टूर्नामेंटों में श्रीलंका को जीत दिलाई। लेकिन अब नोर्त्जे की निरंतरता उनके इस रिकॉर्ड को चुनौती दे रही है।

साउथी को पछाड़ा, दूसरे स्थान पर पहुंचे

यूएई के खिलाफ मुकाबले में नोर्त्जे ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया। दो विकेट लेते ही उनके कुल विकेटों की संख्या 37 हो गई। इसके साथ ही उन्होंने टिम साउथी (36 विकेट) को पीछे छोड़ दिया।टी20 विश्व कप में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले नोर्त्जे ने बड़े मंच पर अपनी उपयोगिता एक बार फिर साबित की। उनकी गेंदबाजी में गति, उछाल और डेथ ओवरों में नियंत्रण उन्हें खास बनाता है।

टी20 विश्व कप में तेज गेंदबाजों द्वारा सबसे ज्यादा विकेट

टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में तेज गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम रही है। उमर गुल (35 विकेट), ट्रेंट बोल्ट (34 विकेट) और मिशेल स्टार्क (32 विकेट) जैसे दिग्गज भी इस सूची में शामिल हैं। इन सभी गेंदबाजों ने अपने-अपने दौर में विरोधी टीमों को मुश्किल में डाला है, लेकिन मौजूदा समय में नोर्त्जे जिस लय में हैं, वह उन्हें इस सूची में शीर्ष पर पहुंचा सकता है।

38 - लसिथ मलिंगा
37 - एनरिक नोर्त्जे*
36 - टिम साउथी
35 - उमर गुल
34 - ट्रेंट बोल्ट
32 - मिशेल स्टार्क

अरुण जेतली स्टेडियम में प्रभावशाली स्पेल

दिल्ली की पिच पर जहां बल्लेबाजों को आमतौर पर मदद मिलती है, वहां नोर्त्जे ने अनुशासित गेंदबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने नई गेंद से आक्रामक शुरुआत की और मध्य ओवरों में भी रन गति पर अंकुश लगाया। उनकी तेज बाउंसर और सटीक यॉर्कर ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी इस स्पेल ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई जिससे श्रीलंका 6 विकेट के नुकसान पर 122 रन ही बना सका। नोर्त्जे के अलावा कॉर्बिन बॉश ने 3 विकेट झटके।

पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज ने किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान

कनाडा (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद कनाडा के पूर्व कप्तान नवनीत धालीवाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 37 वर्षीय बल्लेबाज़ अफगानिस्तान के खिलाफ 19 फरवरी को होने

वाले मुकाबले के बाद कनाडा की जर्सी में आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे। धालीवाल ने साफ कहा कि यह फैसला पहले से तय था और वह इसी टूर्नामेंट के बाद विदाई लेने वाले थे।

'यह पहले से प्लान था'- धालीवाल ने कहा, मैंने वर्ल्ड कप में आने से पहले ही यह फैसला ले लिया था। मैं पिछले 11-12 साल से खेल रहा हूं। यह मेरा आखिरी मैच होगा। उन्होंने यह घोषणा न्यूजीलैंड से हार के बाद की, जहां 19 वर्षीय युवराज समरा के शतक के बावजूद कनाडा को आठ विकेट से हार झेलनी पड़ी।

टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर- चंडीगढ़ में जन्मे धालीवाल कनाडा के टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज़ बनकर संन्यास लेंगे। 48 टी20 मैच, 1305 रन, औसत 32.62, स्ट्राइक रेट 129.20, 10 अर्धशतक; कप्तान के तौर पर भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा। 29 मैचों में से कनाडा ने 22 मुकाबले जीते, 6 हारे और 1 बेनतीजा रहा।

यादगार पल- धालीवाल के लिए सबसे खास लम्हा 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना रहा। इसके अलावा, उन्होंने उस टूर्नामेंट के पहले मैच में बतौर कप्तान अर्धशतक भी लगाया था।

टी-20 वर्ल्ड कप ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे श्रीलंका और जिम्बाब्वे

कोलंबो (एजेंसी)। पहले ही सुपर आठ में जगह बना चुकी श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम गुरुवार को यहां जब टी20 विश्व कप के मैच में आमने-सामने होगी तो उनका लक्ष्य ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करना होगा। श्रीलंका ने स्थानीय परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए ओमान और आयरलैंड को हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर खुद को में वापसी से श्रीलंका की स्थिति मजबूत बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर श्रीलंका की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उनके अलावा कुसल मेंडिस ने अर्धशतक लगाया था और टीम इन दोनों बल्लेबाजों से अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद करेगी। श्रीलंका की बल्लेबाजी क्रम में सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा कमजोर

खिताब के एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया है।

दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया पर अपनी अप्रत्याशित जीत और खराब मौसम की बदौलत पहली बार सुपर आठ में जगह पक्की कर ली। आयरलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था जिससे उसे एक अंक मिला। इससे ऑस्ट्रेलिया की आगे बढ़ने की उम्मीद पर पानी फिर गया। दासुन शनाका की अगुवाई वाली श्रीलंका की टीम सुपर आठ के लिए क्वालीफाई करने के बावजूद किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी। वह अपनी जीत की लय को बनाए रखने और ग्रुप में शीर्ष पर रहने का लक्ष्य रखेगी। सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका की फॉर्म कड़ी बनकर उभरे हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सिर्फ एक रन बनाया। इस तरह से उनकी खराब फॉर्म का सिलसिला जारी रहा जो पिछले साल पाकिस्तान में टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला से चल रहा है। श्रीलंका गेंदबाजी में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज दुशमंथा चमीरा पर निर्भर रहेगा, जो धीमी पिचों में भी तेज गति से गेंदबाजी करने में सफल रहे हैं। एक अन्य तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना भले ही सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वह अपनी अनूठी गेंदबाजी शैली से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। परंपरागत रूप से स्पिन गेंदबाजी में मजबूत मानी जाने वाली इस टीम के पास दुशान हेमंथा के रूप में एक पूरी तरह से फिट लेग स्पिनर है।

सुपर आठ से पहले इटली पर बड़ी जीत दर्ज करने उतरेगा वेस्टइंडीज

कोलकाता (एजेंसी)। दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम गुरुवार को यहां इटली के खिलाफ टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के अपने अंतिम मैच में अपने टीम संयोजन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। वेस्टइंडीज ने एक दशक पहले इसी मैदान पर अपना दूसरा टी20 विश्व कप जीतने के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन वर्तमान टूर्नामेंट में उसने शुरू से लय पकड़ ली थी और वह इसे जारी रखने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेगा।

टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ वेस्टइंडीज का प्रदर्शन भी बेहतर होता जा रहा है। सुपर आठ में वेस्टइंडीज 23 फरवरी को मुंबई में जिम्बाब्वे और 26 फरवरी को अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इसके बाद वह एक मार्च को सह-मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए यहां वापस लौटेगा। ईडन गार्डन्स में होने वाले उस मुकाबले को देखते हुए वेस्टइंडीज की टीम इस मैदान से अनुकूल होने की कोशिश करेगी।

वेस्टइंडीज के लिए यह अच्छी खबर है कि उसके कप्तान शाई होप ने सही समय पर लय हासिल कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ शून्य और स्कॉटलैंड के खिलाफ 19 रन के मामूली प्रदर्शन के बाद इस सलामी बल्लेबाज ने पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ 44 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। शिमरोन हेटमायर ने मध्य क्रम को मजबूती दी है। उन्होंने इसी मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में 64 रन बनाए थे।

टी-20 वर्ल्ड कप में 13.2 ओवर में हासिल किया लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका की लगातार चौथी जीत

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए यूएई को 6 विकेट से हरा दिया। पहले गेंदबाजों ने यूएई को 122/6 पर रोका और फिर 123 रन के लक्ष्य को 13.2 ओवर में हासिल कर ग्रुप स्टेज में लगातार चौथी जीत दर्ज की।

पहले गेंदबाजी में दिखा बॉश का कमाल

टॉस जीतकर कप्तान एडिन मारकम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर नमी और बादलों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से दबाव बनाया। कोरविन बुच ने शानदार स्पेल डालते हुए 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा रबाडा ने भी सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

यूएई की शुरुआत खराब रही। कप्तान मोहम्मद वसीम, आर्यांश शर्मा और सोहैब खान जल्दी आउट हो गए। अलीशन शरफू ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा

सहयोग नहीं मिला। निर्धारित 20 ओवर में यूएई 6 विकेट पर 122 रन ही बना सकी।

बारिश के बाद तेज रन चेज- हल्की बारिश के कारण दूसरी पारी की शुरुआत में थोड़ी देरी हुई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा आक्रामक अंदाज में किया।

एडेन मार्करम और क्विंटन डी कॉक ने सधी हुई शुरुआत दी। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने 36 रन की तेज पारी खेलकर मैच पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। अंत में जेसन स्मिथ ने विजयी रन लेकर टीम को 13.2 ओवर में जीत दिला दी।

इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 से पहले शानदार लय हासिल कर ली है और अब उसकी नजर भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले पर रहेगी।

रणजी ट्रॉफी- 67 साल में जम्मू-कश्मीर पहली बार फाइनल में

● बंगाल को 6 विकेट से हराया, आकिब नबी ने 9 विकेट लिए

जम्मू (एजेंसी)। कल्याणी में खेले गए रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने दो बार की पूर्व चैंपियन बंगाल को 6 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। जीत के लिए मिले 126 रनों के छोटे लक्ष्य को टीम ने चौथे दिन 34.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

वंशज शर्मा ने 43 रन बनाए, जबकि आईपीएल स्टार अब्दुल समद 30 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत तक पहुंचाया। इस जीत के हीरो तेज गेंदबाज आकीब नबी रहे, जिन्होंने मैच में कुल 9 विकेट लेकर बंगाल की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने पहली पारी में 42 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान भी दिया।

समद की आक्रामक बैटिंग और वंशज का छक्का

मैच के चौथे दिन जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 83 रनों की जरूरत थी और उनके 8 विकेट सुरक्षित थे। सुबह के सत्र में शुभम पुंडीर (27) और कप्तान पारस डोगरा (9) जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया था। इसके बाद अब्दुल समद और 22 साल के युवा वंशज शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच 55 रनों की अटूट साझेदारी हुई। समद ने अपनी 27 गेंदों की पारी में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर बंगाल के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। मैच का अंत वंशज शर्मा ने मुकेश कुमार की गेंद पर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर किया।

बंगाल के इंटरनेशनल स्टार्स फेल रहे

बंगाल की टीम में मोहम्मद शमी, आकाश दीप, मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद जैसे चार इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल थे। इसके बावजूद टीम दूसरी पारी में महज 99 रनों पर सिमट गई। बंगाल ने पहली पारी में 328 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 302 रन बनाए।

कप्तान पारस डोगरा रणजी में 10 हजार बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज

41 साल के कप्तान पारस डोगरा ने मैच के दौरान रणजी ट्रॉफी में अपने 10,000 रन पूरे किए। वे वसीम जाफर के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी से होते हुए जम्मू-कश्मीर पहुंचे डोगरा ने पहली पारी में 58 रनों की जुझारू पारी खेली थी, जिसने जीत की नींव रखी। 41 साल के कप्तान पारस डोगरा ने मैच के दौरान रणजी ट्रॉफी में अपने 10,000 रन पूरे किए।

प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी बधाई

इस ऐतिहासिक जीत पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा,यह खिलाड़ियों की मेहनत और कोचिंग स्टाफ के अनुशासन का नतीजा है। जम्मू-कश्मीर की टीम ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार किया है। मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे खिलाड़ी भारतीय टीम में भी अहम भूमिका निभाते दिखेंगे।

व्यापार

सेंसेक्स
83734.25 पर बंद
निफ्टी
25819.35 पर बंद

सोना
148,940
चांदी
255,000

ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के 9 वाले शेयर में 11 प्रतिशत उछाल

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार भले ही बुधवार को सुस्त रहा हो लेकिन कुछ पेनी शेयर रॉकेट की तरह बढ़े। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के शेयर में भी कुछ ऐसी ही तेजी आई। वैसे तो यह शेयर लगातार तीन दिन से चढ़ रहा है लेकिन बुधवार को इसमें 11 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई। बीएसई पर शेयर 11 पर्सेंट की तेजी के साथ 10.57 प्रति शेयर के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। सिर्फ तीन दिन में यह शेयर 40 पर्सेंट से ज्यादा उछल चुका है। शेयर का 52 वीक हाई 14.02 रुपये है।

अर्थकुंभ वेंचर्स एलएलपी द्वारा बल्क डील के माध्यम से कंपनी के शेयर खरीदने के बाद शेयर डिमांड में आ गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के बल्क डील आंकड़ों के अनुसार 17 फरवरी 2026 को अर्थकुंभ वेंचर्स एलएलपी ने कंपनी के 3,92,88,523 शेयर 9.41 प्रति शेयर के भाव पर खरीदे। इसके अलावा, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने 9.41 प्रति शेयर के भाव से 5,10,71,609 शेयर खरीदे लेकिन 9.36 प्रति शेयर के भाव से 5,09,01,609 शेयर बेचे। इसी बीच, मनसुख सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस ने 9.14 रुपये प्रति शेयर के भाव से 5,17,51,726 शेयर खरीदे, लेकिन 9.16 रुपये प्रति शेयर के भाव से 5,55,51,726 शेयर बेच दिए। इसी तरह, जैनम ब्रोकिंग ने 9.47 रुपये प्रति शेयर के भाव से 3,68,73,832 शेयर खरीदे लेकिन 9.39 रुपये प्रति शेयर के भाव से 2,12,73,833 शेयर बेच दिए।

सिगरेट के बढ़े दाम, खबर के बीच रॉकेट की तरह भागे तीन शेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को सिगरेट निर्माता कंपनी- आईटीसी लिमिटेड, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया और वीएसटी इंडस्ट्रीज

के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। यह तेजी उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें बताया गया है कि इन कंपनियों ने उत्पाद शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सिगरेट के दाम बढ़ाए हैं। आईटीसी के शेयर की कीमत में लगातार तीसरे दिन तेजी आई और आज यह करीब डेढ़ पर्सेंट बढ़कर 330 पर पहुंच गया। वहीं, गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयरों में 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई और यह 2315 तक पहुंच गया। एक अन्य सिगरेट निर्माता कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत में भी 3 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। बता दें कि पिछले महीने, सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि के बाद मार्जिन और वॉल्यूम को लेकर चिंताएं बढ़ने के कारण सिगरेट निर्माता कंपनियों के शेयरों में 9 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक की गिरावट आई थी। बीएंडके सिक्योरिटीज और इनक्रेड के विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि आईटीसी ने उत्पाद शुल्क में वृद्धि के परिचालन आय पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कुछ कैटेगरी में सिगरेट की कीमतें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड फ्लेक और क्लासिक (प्रीमियम) की कीमतों में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, क्लासिक कनेक्ट (स्लिम) की कीमतों में 20 प्रतिशत की और गोल्ड फ्लेक सुपरस्टार (वैल्यू) की कीमतों में लगभग 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

एसआरएफ के 'मालिक' बेच रहे हैं 3 प्रतिशत हिस्सा, करीब चार प्रतिशत लुढ़का शेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। मार्केट में तेजी के बीच एसआरएफ के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को करीब 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस बिकवाली के पीछे की वजह प्रमोटर्स की तरफ से होने वाली शेयरों की बिक्री है। कंपनी के प्रमोटर कामा होल्डिंग्स अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रहे हैं। इस खबर ने निवेशकों के सेंटीमेंट को झटका दिया। आज 17 फरवरी को एसआरएफ के शेयर बीएसई में 2833.65 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 4 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2883.35 रुपये के लेवल पर आ गया। बता दें, कंपनी के शेयर मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर 3.69 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 2743.20 रुपये के लेवल पर था। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कामा होल्डिंग्स ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ

डायरेक्टर्स ने एसआरएफ में 3 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर सहमति दे दी है। यह बिक्री मार्च 2027 तक हो जाएगी। इस बिक्री के बाद प्रमोटर्स की कंपनी में कुल हिस्सेदारी 50 प्रतिशत के नीचे आ जाएगी। एसआरएफ की दिसंबर 2026 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर कामा होल्डिंग्स के पास 50.21 प्रतिशत हिस्सा था। अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान एसआरआफ का नेट प्रॉफिट 433 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, कंपनी का रेवन्यू चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 3713 करोड़ रुपये रहा था। इस कंपनी का पीई रेशियो 47 है। पिछले महीने ही कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने 2025 में दो बार डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 7.60 रुपये का डिविडेंड दिया था। बीते एक महीने में स्टक्क के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 0.21 प्रतिशत गिरा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 3319 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2569.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 81315 करोड़ रुपये का है।

महंगी बाइक्स की बिक्री में तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। लोग अब सस्ती मोटरसाइकिल्स को छोड़कर महंगी बाइक्स का रुख कर रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीनों में प्रीमियम बाइक्स की बिक्री में तेजी आई है। इस दौरान 125 सीसी और उससे ज्यादा इंजन क्षमता वाली बाइक्स की बिक्री बढ़कर 26 फीसदी हो गई है। अमूमन इन बाइक्स की कीमत 80,000 रुपये से शुरू होती है। ईटी की एक रिपोर्ट में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के हवाले से यह दावा किया गया है। पिछले साल सरकार ने सितंबर में जीएसटी दरों में कटौती की थी। इससे इन बाइक्स की कीमत कम हुई है। साथ ही उपभोक्ताओं की पसंद में भी बदलाव आया है। इन कारणों से देश में महंगी बाइक्स की डिमांड बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस सेगमेंट की बिक्री 24.4 प्रतिशत थी। क्रिसिल ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव से मोटरसाइकिल की बिक्री में मजबूत रिकवरी दिख रही है। मोटरसाइकिल की बिक्री में अब भी 125 सीसी तक के एंट्री लेवल मॉडल का जलवा है। कुल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 73 फीसदी है लेकिन धीरे-धीरे 150 से 350 सीसी रेंज की डिमांड बढ़ रही है।

अडानी पावर के शेयर की सुस्त चाल, ब्रोकरेज ने कहा- खरीदो

187 तक जाएगा भाव, अडानी पावर के शेयर का टारगेट प्राइस

नई दिल्ली, एजेंसी। गौतम अडानी समूह की कंपनी-अडानी पावर के शेयर की सुस्त चाल के बीच ब्रोकरेज इसको लेकर बुलिश है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने पावर सेक्टर पर अपना पॉजटिव आउटलुक बरकरार रखा। इसके साथ ही अडानी ग्रुप की पावर कंपनी के शेयर को खरीदने की सलाह दी। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अडानी पावर की थर्मल परियोजनाओं में 64 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी और चल रहे कर्ज में कमी के कारण वित्त वर्ष की तीसरी छमाही तक इसकी क्षमता में 2.3 गुना वृद्धि होकर 41.9 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है।

एंटीक ने अडानी पावर के शेयर पर बाय रेटिंग है और टारगेट प्राइस 187 रुपये तय किया है। वर्तमान में अडानी पावर के शेयर की कीमत 145 रुपये के नीचे है। अडानी पावर के शेयर का 52 वीक हाई और लो रेंज 182.75 रुपये से 93.23 रुपये के बीच है। शेयर की ये दोनों कीमतें पिछले साल रही थीं।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में अडानी पावर का नेट प्रॉफिट 15 प्रतिशत से अधिक गिरकर 2,488 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने मुनाफे में इस कमी का मुख्य कारण पिछली अवधि की एकमुश्त आय का कम होना बताया है। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मुनाफा 2,488 करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में यह 2,940 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 12,717 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 13,434 करोड़ रुपये था। मानसून के जल्दी आने और लंबे समय तक

रहने के कारण मांग में आए व्यवधान के बावजूद, कंपनी की बिजली बिक्री की मात्रा 23.6 अरब यूनिट (बीयू) रही। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा 23.3 अरब यूनिट था। बीते दिनों अडानी पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एस बी ख्यालिया ने कहा थाकि हम अपनी आगामी क्षमताओं के लिए तेजी से लॉन्गटर्म के पावर परचेज डीज सुरक्षित कर रहे हैं। हमारी 23.7 गीगावाट की विस्तार योजना का लगभग आधा हिस्सा पहले ही राज्य डिस्कॉम के साथ पीपीए के तहत जुड़ चुका है। हमारी परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया भी बेहद शानदार रही है और हम अपने लक्ष्यों को समय पर या उससे पहले हासिल कर रहे हैं।

नई कंपनी का गठन

हाल ही में अडानी पावर ने एक कंपनी अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड (एएईएल) का गठन किया है। एएईएल को 5,00,000 रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ गठित किया गया है। इसे 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 50,000 शेयर में विभाजित किया गया है। अडानी पावर की एएईएल में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

3 साल में 1782 प्रतिशत उछल गए हैं ई2ई नेटवर्क्स के शेयर

57 रुपये का शेयर 3000 रुपये के पार, एआई फैक्ट्रीज के लिए दिग्गज कंपनी से पार्टनरशिप

नईदिल्ली, एजेंसी। मल्टीबैगर कंपनी ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। जीपीयू क्लाउड उपलब्ध कराने वाली कंपनी ई2ई नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को हस्थ में 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 3068.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज कंपनी एनवीडिया ने एडवांस्ड ,ह्न फैक्ट्रीज डिलीवर करने के लिए ई2ई नेटवर्क्स को सहयोग करने की घोषणा की है, इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयरों में तेज उछाल आया है। ई2ई नेटवर्क्स अपने प्लेटफॉर्म पर एक एनवीडिया ब्लैकवेल जीपीयू क्लस्टर बना रही है। ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयर पिछले 3 साल में 1782 पर्सेंट चढ़ गए हैं। ई2ई नेटवर्क्स के शेयर 17 फरवरी 2023 को 163 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 फरवरी 2026 को 3068.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 2 साल में ई2ई नेटवर्क्स के शेयरों में 284 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 53 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर करीब 46 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एक महीने

में ई2ई नेटवर्क्स के शेयरों में 37 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3894.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1710.05 रुपये है।

आईपीओ में 57 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम

ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 3 मई 2018 को खुला था और यह 7 मई तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 57 रुपये था। ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयर 15 मई 2018 को हस्थ में 85 रुपये पर लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर उछाल के साथ 89 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयर 18 फरवरी 2026 को 3068.20 रुपये पर जा पहुंचे दिग्गज टेक्नोलॉजी फर्म एनवीडिया भारत और वैश्विक इस्तेमाल के लिए ,ह्न सॉल्यूशंस बनाने वाले सभी स्टेजेज के स्टार्टअप्स की पहचान और उन्हें फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्मों पीक जेड 47, इलेवेशन कैपिटल, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और एक्सेल इंडिया समेत प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्मों के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है।

बीएचईएल को मिला 1500 करोड़ रुपये का काम

सेल से मिला वर्क ऑर्डर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम पश्चिमबंगाल के बुरनपुर स्थिति स्थिति स्टील प्लांट में करना है। कंपनी को अवार्ड लेटर 17 फरवरी को मिला था। इस वर्क ऑर्डर की कीमत 1200 करोड़ रुपये से 1500 करोड़ रुपये के बीच है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। बता दें, कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा 39 महीने की है।

पिछले हफ्ते हुई थी शेयरों की बिक्री: नवर प्रतिशत कंपनी का ऑफर फार सेल पिछले हफ्ते 11 फरवरी को खुला था। पहले दिन ओएफएस 2.3 गुना सब्सक्राइब किया गया था। ऑफर किए गए 9.4 करोड़ शेयरों के लिए 22 करोड़ शेयर की बोली आई थी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5650 करोड़ रुपये की बोली दी थी। बता दें, सरकार ने 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए ग्री शू का विकल्प अपनाया है।

शेयरों में तेजी: आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 0.11 प्रतिशत की तेजी मार्केट के बंद होने के समय पर दर्ज की गई थी। तब यह स्टॉक 262.80 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने में नवर प्रतिशत कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 35 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 10 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 305.85 रुपये और 52 वीक लो लेवल 176 रुपये प्रति शेयर है। भेल का मार्केट कैप 91508 करोड़ रुपये का है।

दो साल में यह स्टॉक 16 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में भेल के शेयरों की कीमतों में 262 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 5 साल में नवर प्रतिशत कंपनी के शेयरों का भाव 555 प्रतिशत बढ़ा है।

लगातार डिविडेंड भी दे रही है कंपनी: भेल उन कुछ सरकारी कंपनियों में से एक है। जिन्होंने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.25 रुपये का डिविडेंड दिया था।

सबसे बड़ी रिफाइनरी पर मंडराया खतरा, पहले ही हो चुकी है 4 साल की देर

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने महाराष्ट्र के र प्रतिशतागिरि में देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने की योजना बनाई थी लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह कई दशकों से अटकी हुई है। अब इससे विदेशी निवेशकों के भी र प्रतिशतागिरि रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स से किनारा करने की आशंका है। ईटी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी पहले ही इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुकी है जबकि सऊदी अरामको भी शर्तों की समीक्षा चाहती है। यह रिफाइनरी की कल्पना अरामको, एडनॉक और सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच जॉइंट वेंचर के रूप में की गई थी। इसमें अरामको और एडनॉक की 50 फीसदी हिस्सेदारी रहनी थी जबकि बाकी 50 फीसदी हिस्सेदारी भारत की तीन कंपनियों के पास रहनी थी। इस प्रोजेक्ट को 2022 में कमीशन हो जाना था लेकिन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि संभवत इस प्रोजेक्ट से निकल चुकी है क्योंकि उसकी दूसरी प्राथमिकताएं हैं। इसी तरह सऊदी अरामको भी पुरानी शर्तों की समीक्षा चाहती है। अरामको इन इस पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

पीक से 2 लाख रुपये सस्ती चांदी

मुंबई, एजेंसी। इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड तेजी से चांदी ने हर किसी को चौंका दिया था। जनवरी के अंत में चांदी ने पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को पार किया था। हालांकि, इसके बाद चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई और अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि क्या मार्च के महीने में चांदी की चाल कैसी रहेगी। आइए जान लेते हैं एक्सपर्ट के अनुमान

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,000 प्रति किलो का सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया था। वहां से कीमतों में करीब 46 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है और भाव लगभग 2 लाख तक फिसल चुके हैं। हालांकि, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद विशेषज्ञ मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में चांदी मजबूत रहने वाली है। लगातार सप्लाई घाटा, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से मजबूत औद्योगिक मांग तथा निवेशकों की बढ़ती रुचि कीमतों को मध्यम और लंबी अवधि में सहारा दे सकती है। वेंचुरा के कमोडिटी प्रमुख एनएस रामास्वामी के अनुसार मौजूदा करेक्शन का पैटर्न पहले की तरह है। आने वाले वक्त में फिर से तेजी देखी जा सकेगी। 20 फरवरी तक चलने वाले चीनी नववर्ष के दौरान आमतौर पर बाजार में उतार-चढ़ाव और कम भागीदारी रहती है। इसके बाद लिक्विडिटी और फिजिकल मांग बढ़ती है, जिससे फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में तेजी आ सकती है। वहीं, ऑगमोंट की रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी का मानना है कि फिलहाल चांदी 70䠀90 (करीब 2,25,000䠀2,85,000) के दायरे में उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर सकती है। उनका सुझाव है कि ट्रेडर गिरावट में खरीद और उछाल पर बिकवाली की रणनीति अपनाएं। तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका-ईरान तनाव से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी।

65 पैसे के शेयर ने दिया 4960 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न

मुंबई, एजेंसी। शेयर बाजार में कई ऐसे बेहद सस्ते स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इनमें से एक स्टॉक काबरा ड्रग्स का भी है। इस स्टॉक ने लंबी अवधि में निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है। फरवरी 2019 में कंपनी का शेयर महज 0.65 के आसपास था, जो अब बीएसई पर करीब 32 तक पहुंच चुका है। इस तरह, सिर्फ सात साल की अवधि में शेयर ने लगभग 4960 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर रकम के हिसाब से देखें तो छह-सात साल पहले जिस निवेशक ने 1 लाख लगाए होते और होल्ड किया होता तो उसकी वैल्यू करीब 50 लाख के आसपास पहुंच चुकी होगी।

आकाश इंस्टीट्यूट भोपाल के तनिष्क सिंघल बने भोपाल टॉपर

भोपाल, एजेंसी। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के भोपाल के छात्रों ने एक बार फिर जेईई मेन (सेशन 1) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपने क्षेत्र में संस्थान के मजबूत शैक्षणिक कार्यक्रम को साबित किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 16 फरवरी को जारी परिणामों के अनुसार, जेईई मेन 2026 में आकाश इंस्टीट्यूट, भोपाल के 11 छात्रों ने 98 परसेंटाइल से अधिक प्राप्त कर बेहतरीन प्रदर्शन दिया। जेईई मेन 2026 में, आकाश इंस्टीट्यूट भोपाल शाखा के छात्रों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। तनीष्क सिंगल ने 99.925 परसेंटाइल प्राप्त कर भोपाल सिटी रैंक 1 हासिल किया। यह पिछले 3 वर्षों में दूसरी बार है जब भोपाल सिटी टॉपर आकाश इंस्टीट्यूट की भोपाल शाखा का छात्र बना है। उनके बाद अर्श गिरी ने 99.56 परसेंटाइल और कृष्णा वर्मा ने 99.55 परसेंटाइल के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंशिका धाकड़ और अनुज सिंह दोनों ने 99.48 परसेंटाइल हासिल किए, निहारिका मीणा ने 99.17, सालेहा अंसारी ने 98.79 तथा वैभव रंजन ने 98.12 परसेंटाइल प्राप्त किए। यह प्रदर्शन भोपाल शहर में सर्वश्रेष्ठ चयन प्रतिशत में से एक माना जा रहा है। बिज़नेस हेड, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने कहा- भोपाल के छात्रों का उत्कृष्ट परिणाम उनके समर्पण और आकाश के मजबूत शैक्षणिक तंत्र का प्रमाण है।

डॉ. हेमलता श्रीवास्तव प्रापर्टी विवाद

कठघरे में रजिस्ट्री ऑफिस, दस्तावेज जांचे बिना कैसे दानपत्र के कागज तैयार किए

नगर निगम की जांच के बाद लीज निरस्तीकरण की तैयारी, करोड़ों की जमीन पर घमासान

जबलपुर, प्रातः किरण, संवाददाता

राइट टाउन स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर सामने आए डॉ. हेमलता श्रीवास्तव प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। नगर निगम की जांच में खुलासा होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पूरी जमीन नगर निगम की लीज पर होने के बावजूद दानपत्र और वसीयत के दस्तावेज बिना वैधानिक अनुमति और जांच के तैयार कर लिए गए।

बिना अनुमति कैसे बने दानपत्र के दस्तावेज?

सूत्रों के अनुसार जिस भूमि पर दानपत्र और वसीयत तैयार की गई, वह नगर निगम की लीज भूमि थी। लीज की शर्तों के अनुसार बिना निगम की अनुमति के संपत्ति का हस्तांतरण संभव नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस ने दस्तावेजों की वैधता की जांच किए बिना कागजात कैसे तैयार कर दिए।

24 घंटे का नोटिस, कोई नहीं पहुंचा दावा करने

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर उपायुक्त शिवांगी महाजन ने मौके पर नोटिस चस्पा कर संबंधित पक्षों को 24 घंटे के भीतर दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। समय सीमा पूरी होने के बावजूद न तो कोई आपत्ति दर्ज कराई गई और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद जांच रिपोर्ट निगमायुक्त को सौंप दी गई है।

लीज शर्तों का उल्लंघन उजागर

नगर निगम सूत्रों के मुताबिक–प्लॉट क्रमांक 51, राइट टाउन (क्षेत्रफल 25,047 वर्गफीट) लीज पर था।वर्ष 2020–21 से लीज भू–भाड़ा जमा नहीं किया गया।लीज की शर्त क्रमांक 3, 6, 7 और 8 का उल्लंघन पाया गया।शर्त क्रमांक 6 के तहत निगम को जमीन पर पुनः प्रवेश का अधिकार सुरक्षित है।

निगम जल्द ले सकता है कब्जा

निगमायुक्त का कहना है कि लीज भूमि को दानपत्र व वसीयत के माध्यम से हस्तांतरित करने की कोई अनुमति नहीं ली गई, जो स्पष्ट रूप से शर्तों का उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट के आधार पर लीज निरस्त कर जमीन को निगम के अधिपत्य में लेने की तैयारी है।

क्या था पूरा मामला?

डॉ. हेमलता के पति और पुत्र के निधन के बाद लगभग 11 हजार वर्गफीट भूमि का हिस्सा डॉ. सुमित जैन और प्राची जैन को दानपत्र के माध्यम से दिया गया था, जबकि करीब 14 हजार वर्गफीट भूमि एक धार्मिक संस्था के नाम वसीयत की गई थी। इसी को लेकर विवाद गहराया। डॉ. हेमलता के निधन के बाद जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति को सील कर दिया था।

जॉनसन स्कूल ने आदिवासी छात्रा के भविष्य से किया खिलवाड़

फीस नहीं भरने पर दसवीं के पेपर में नहीं दिया बैठने

जबलपुर, प्रातः किरण, संवाददाता

शहर के नर्मदा रोड स्थित जॉनसन प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं जमा होने के कारण 10वीं कक्षा की एक आदिवासी छात्रा को बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोक दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है, जब छात्रा अंग्रेजी विषय का प्रश्नपत्र देने विद्यालय पहुंची थी। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने बकाया फीस का हवाला देते हुए उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया और पहले पूरी फीस जमा करने की शर्त रख दी।

कमजोर आर्थिक स्थिति बनी वजह

जानकारी के अनुसार सानिया उइके 10वीं कक्षा की नियमित छात्रा है और बोर्ड परीक्षा दे रही है। मंगलवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसका अंग्रेजी का पेपर था। छात्रा समय पर विद्यालय पहुंची और प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में शामिल करने की गुहार लगाई। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक शेष फीस जमा नहीं की जाएगी, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

छात्रा की गुहार नहीं सुनी

छात्रा का कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और कुछ फीस शेष है, जिसे वह अन्य विषयों की परीक्षाओं के दौरान या बाद में जमा कर देगी। उसने प्रबंधन से अनुरोध किया कि उसे कम से कम अंग्रेजी की परीक्षा देने दी जाए ताकि उसका एक वर्ष खराब न हो। बावजूद इसके, विद्यालय प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे वापस लौटा दिया।

आक्रोशित परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन

परीक्षा से वंचित किए जाने की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। उन्होंने विद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर स्कूल प्रबंधन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। उनका कहना है कि फीस वसूली का यह तरीका न केवल अमानवीय है, बल्कि शिक्षा के अधिकार के भी खिलाफ है।

शिक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग

घटना की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंचने की बात कही जा रही है। परिजन दोषी प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई और छात्रा को पुनः परीक्षा में बैठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली और फीस वसूली के तौर–तरीकों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पूर्व महापौर प्रभात साहू हेलमेट विवाद

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसटीएफ से मांगी रिपोर्ट

लार्डगंज पुलिस की जांच पर सवाल, अब 24 मार्च को होगी सुनवाई

जबलपुर। बलदेवबाग चौराहे पर हुए चर्चित हेलमेट विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी एसटीएफ को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने एसटीएफ को जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है।

यह पूरा मामला– 18 सितंबर 2025 का है, जब हेलमेट चेकिंग के दौरान पूर्व महापौर प्रभात साहू और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के बीच तीखी झड़प हुई थी। अधिवक्ता मोहित वर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि लार्डगंज थाना पुलिस ने इस मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और केवल पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि पूर्व महापौर पर कोई आंच नहीं आने दी। पुलिस की इस कार्यप्रणाली को देखते हुए हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई (23 जनवरी) को जांच की जिम्मेदारी जबलपुर एसटीएफ को सौंप दी थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एसटीएफ के डीएसपी संतोष कुमार तिवारी ने कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि जांच अभी प्रक्रियाधीन है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें और समय दे दिया है।

मेडिकल छात्र की मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

रैगिंग का आरोप, सीबीआई जांच की मांग

जबलपुर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र शिवांश गुप्ता की संदिग्ध मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। शिवांश के पिता ने याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि रैगिंग और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई मौत का मामला है। मांग की गई कि इस मामले की जांच सीबीआई से या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के वार्डन रविकांत महंत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में गृह सचिव, जबलपुर के पुलिस अधीक्षक, गढ़ा थाने के एसएचओं को भी पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि 4 जून को शिवांश हॉस्टल से बाहर गया और 5 जून को लौटा। सुबह लगभग 10.30 से 11.30 बजे के बीच वह हॉस्टल की छत पर किसी से फोन पर बात कर रहा था। करीब 11.45 बजे वह छत से नीचे गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गयाए जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शिवांश के पिता संतोष कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी व अमर प्रकाश गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि शिवांश ने वर्ष 2024 की नीट परीक्षा में 660 अंक प्राप्त किए थे। मध्य प्रदेश रैंक 734 के आधार पर उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रवेश मिला था। वह प्रथम वर्ष एमबीबीएस का छात्र था। पांच जून 2025 को परिजनों को सूचना मिली कि शिवांश घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। परिजन जबलपुर पहुंचे, जहां 6 जून 2025 को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने शिवांश को मृत घोषित कर दिया। पिता का दावा है कि 12 जून को कॉलेज परिसर पहुंचकर उन्होंने शिवांश के सहपाठियों से बातचीत की। आरोप है कि द्वितीय वर्ष के छात्र नयन साहू ने शिवांश के साथ रैगिंग और दुर्व्यवहार किया। एक प्रथम वर्ष की छात्रा से मित्रता को लेकर विवाद था। परिजनों का दावा है कि मई माह में शिवांश ने अपनी मां को बताया था कि नयन साहू ने स्थानीय लडक़ों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की। डर के कारण उसने वॉर्डन या प्रशासन से शिकायत नहीं की। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

डिग्री की गरिमा तार-तारः गुरुओं के हाथ में थमाए मार्केटिंग के पंपलेट

जबलपुर, प्रातः किरण, संवाददाता

शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायीकरण इस कदर बढ़ गया है कि अब छात्रों की क्लास लेने वाले शिक्षक सड़कों पर कॉलेज के पंपलेट बांटते नजर आएंगे। जबलपुर सहित प्रदेश के कई निजी कॉलेज संचालकों ने अपनी कॉलेज की मार्केटिंग को लेकर एक नया मौखिक फरमान जारी किया है। इसके अनुसार अब कॉलेज की फैकल्टी और प्रोफेसरों को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के केंद्रों पर जाना होगा और वहां कॉलेज की खूबियां बताकर अपनी संस्था का ब्रोशर और पंपलेट बांटने होंगे।

सूत्रों के अनुसार, कॉलेज प्रबंधन ने शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके प्रदर्शन और प्रमोशन को अब इस फील्ड वर्क से जोड़ा जाएगा। पहले यह काम मार्केटिंग टीम या कॉलेज के छोटे कर्मचारी किया करते थे, लेकिन इस सत्र में फैकल्टी को ही मैदान में उतार दिया गया है। तर्क यह दिया जा रहा है कि जब शिक्षक खुद छात्रों से बात करेंगे, तो एडमिशन की संभावना बढ़ जाएगी।

निजी कॉलेजों का तुगलकी फरमानः एडमिशन लाओ तो बची रहेगी नौकरी,खुलकर शिकायत करने कोई तैयार नहीं

क्या इस दिन के लिए की थी पीएचडी

निजी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने नाम न छापने की शर्त पर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा, हमने पीएचडी और नेट की पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि हमें धूप में खड़े होकर कागज बांटने पड़ें। यह न केवल हमारे पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी है। लेकिन नौकरी बचाने के डर से हमें यह काम मजबूरी में करना पड़ रहा है।

शैक्षणिक स्तर बेहद बुरा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि जब एक शिक्षक का मुख्य काम छात्रों को पढ़ाने और शोध करने के बजाय मार्केटिंग करना बन जाएगा, तो शिक्षा के स्तर का गिरना तय है। परीक्षा केंद्रों के बाहर शिक्षकों की यह ड्यूटी छात्रों और अभिभावकों के बीच भी गलत संदेश दे रही है। शिक्षकों को इस तरह के कार्यों में झोंकना शिक्षा की मूल भावना के विपरीत है।

नियमों के विरुद्ध है यह पंपलेट अभियान

इस संबंध में जब लीड कॉलेज प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी से बात की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत शिक्षण सत्र में कॉलेज कैंपस का भ्रमण कराने के निर्देश हैं। परीक्षा के दौरान केंद्रों के बाहर शिक्षकों से पंपलेट या ब्रोशर बंटवाना इस अभियान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कांचघर चौराहे पर बवाल

अधिवक्ताओं से अभद्रता, कॉलर पकड़ जमीन पर गिराया, फाड़ी ड्रेस

जबलपुर। घमापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांचघर चौराहे पर गाड़ी टच होने की मामूली बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दो अधिवक्ताओं के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि युवक ने एक अधिवक्ता की कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनकी ड्रेस फाड़ दी। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ललित कॉलोनी निवासी अधिवक्ता यशवंत कुमार मानकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वे अपनी साथी अधिवक्ता सोनाली बावरिया के साथ किशोर न्यायालय से काम निपटाकर लौट रहे थे। कांचघर चौराहे पर वाहन क्रमांक एमपी 20 केएन 7206 के चालक ने गाड़ी टच होने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल अधिवक्ताओं की कार के सामने अड़ा दी और बहस करने लगा। विरोध करने पर उसने अभद्रता करते हुए अधिवक्ता यशवंत मानकर की कॉलर पकड़ ली और उन्हें जमीन पर पटक दिया। इस दौरान आरोपी ने उनकी ड्रेस फाड़ दी और जान से मारने की धमकी दी।

मोबाइल में कैद हुई पूरी घटना– घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच अधिवक्ता सोनाली बावरिया ने अपने मोबाइल फोन से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत पर आरोपी वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

सीएमएचओ दफ्तर — **छलका बुजुर्ग का दर्द, मेरा पैर लौटा दो कहकर रो पड़ी**

शर्म करो स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार

जबलपुर, प्रातः किरण, संवाददाता

जिले का स्वास्थ्य महकमे ने पैसों के आगे बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है, लूट–खसूट वाले अस्पतालों में गलत इलाज की वजह से किसी की मौत हो या पैर–हाथ कटे इससे विभाग के सीएमएचओ को कोई लेना–देना नहीं है। सीएमएचओ आफिस में मंगलवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे सबकी आंखें भर आई, एक 70 साल की बुजुर्ग एक पैर से न्याय के लिए सीएमएचओ कार्यालय पहुंची लेकिन उसे न्याय नहीं मिला तो वह फफक–फफक रोने लगी। जिले के स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला। करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला एक पैर के सहारे न्याय की गुहार लगाने पहुंची, लेकिन जब उसे ठोस आश्वासन नहीं मिला तो वह वहीं फफक–फफक कर रोने लगी। इस दृश्य को देखकर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

दुर्घटना के बाद निजी अस्पताल ले जाने का आरोप

समाजवादी पार्टी के नेता आशीष मिश्रा के साथ झांसीघाट निवासी सुकून बाई अपनी शिकायत लेकर सीएमएचओ कार्यालय पहुंची थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ माह पूर्व सड़क दुर्घटना में उनके पैर में गंभीर चोट आई थी। परिजन उन्हें एंबुलेंस से शासकीय मेडिकल अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में स्वयं को डॉक्टर बताने वाले अमित खरे मिले, जो स्मार्ट सिटी अस्पताल के संचालक बताए जाते हैं। आरोप है कि उन्होंने मरीज को अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए समझाया और मेडिकल अस्पताल ले जाने के बजाय अपने अस्पताल ले गए।

महीनों इलाज के बाद बिगड़ी हालत, काटना पड़ा पैर

बुजुर्ग महिला का कहना है कि स्मार्ट सिटी अस्पताल में कई महीनों तक इलाज चलता रहा। परिवार ने अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आरोप है कि बाद में अचानक इलाज बंद कर दिया गया और उचित देखभाल नहीं मिलने से घाव बिगड़ता गया। हालत इतनी गंभीर हो गई कि संक्रमण फैल गया और अंततः दूसरे अस्पताल में उनका एक पैर काटना पड़ा।

पॉलीथिन बांधकर सड़ाया गया पैर, परिजनों का आरोप

इसी अस्पताल को लेकर एक अन्य मामला भी सामने आया है। झांसीघाट निवासी बसंती बर्मन सड़क दुर्घटना में घायल हुई थीं। परिजनों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी अस्पताल में उनके घायल पैर पर उचित चिकित्सा देने के बजाय लापरवाही बरती गई। आरोप यह भी है कि अस्पताल संचालक के निर्देश पर पैर पर पॉलीथिन बांध दिया गया, जिससे संक्रमण बढ़ा और कुछ दिनों बाद उनका भी पैर काटना पड़ा।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

इन आरोपों से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि निजी अस्पतालों की मनमानी और कथित लापरवाही के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीएमएचओ कार्यालय में बुजुर्ग महिला ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही, उन्होंने अपने इलाज से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर दोषी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। मामले ने शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और निजी अस्पतालों की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इन गंभीर आरोपों की जांच कर पीड़ितों को न्याय दिला पाता है या नहीं।

प्रकाशक एवं मुद्रक विशाखा अवस्थी द्वारा श्री हनुमत कृपा पब्लिकेशन से मुद्रित एवं ब्लॉक -7, हॉल ए-7 स्कीम-18, जेडीए ऑफिस के बाजू, सिविक सेंटर से प्रकाशित। RNI NO. MPHIN/25/A1541
सलाहकार संपादक अरविंद शीले, प्रबंध संपादक श्रवण मिश्रा, संपादक मदन मोहन अवस्थी* पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार दूरभाष -9827007217, 9425856600, 0761-3515636, सतना कार्यालय-07672-292110